www. bntonline.in | ebnt paper epaper.bntonline.in | Breaking News Today | bntnewschannel | breaking.news.today | BNTNews_2008

RNI NO.DELBIL/2008/24327

17 साल बेमिसाल

Breaking News Today

हम सबकी खबर लें, हम सबको खबर दें!

Vol. No. XVII & Issue No. 06 | 26 March 2025 | Fortnightly | Pages 16 | ₹ 5

केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन भत्ते-पेंशन में की बढ़ोतरी

■ **बीएनटी न्यूज**

केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन में 24 प्रतिशत की वृद्धि की है, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। यह बढ़ोतरी मूल्य वृद्धि सूचकांक के आधार पर तय की गई है, जिसका मतलब है कि सांसदों के वेतन में यह बदलाव महंगाई दर के अनुसार किया गया है।

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, केंद्र ने 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी, संसद सदस्यों (सांसदों) के वेतन, भत्ते और पेंशन में वृद्धि की है।

अधिसूचना के अनुसार, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों का वेतन एक लाख रुपए से बढ़ाकर 1.24 लाख रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है, जबकि दैनिक भत्ता 2,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है।

पूर्व सांसदों को दी जाने वाली पेंशन भी वर्तमान में 25,000 रुपए से बढ़ाकर 31,000 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है।

अधिसूचना में कहा गया है कि पांच साल से अधिक की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन को पहले के 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है।

संसद के चालू बजट सत्र के दौरान सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन की घोषणा की गई। मौजूदा और पूर्व सांसदों के वेतन और भत्ते में पिछली बार संशोधन की घोषणा अप्रैल 2018 में की गई थी।

वर्ष 2018 के संशोधन में मुद्रास्फीति और जीवन-यापन की बढ़ती लागत के अनुरूप सांसदों का मूल वेतन 1,00,000 रुपए प्रति माह निर्धारित किया गया था।

2018 के संशोधन के अनुसार, सांसदों को अपने कार्यालयों को बनाए रखने और अपने संबंधित जिलों में मतदाताओं से जुड़ने की लागत को कवर करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में 70,000 रुपए का भत्ता मिलता है। इसके अलावा, उन्हें कार्यालय भत्ते के रूप में प्रतिमाह 60,000 रुपए और संसदीय सत्रों के दौरान 2,000 रुपए दैनिक भत्ते के रूप में मिलते हैं। इन भत्तों में भी अब बढ़ोतरी की जाएगी।

इसके अलावा, सांसदों को फोन और इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए सालाना भत्ता भी मिलता है। वे अपने और अपने परिवार के लिए प्रतिवर्ष 34 मुफ्त घरेलू उड़ानों का आनंद लेते हैं और पेशेवर एवं व्यक्तिगत उपयोग के लिए किसी भी समय प्रथम श्रेणी की ट्रेन यात्रा करते हैं। वे सड़क का उपयोग करने पर माइलेज भत्ते

शेष पृष्ठ 2 पर

संक्षिप्त खबरें

छात्र संगठनों के प्रदर्शन में पहुंचे राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के छात्र संगठनों के प्रदर्शन में शिरकत की। उन्होंने जंतर मंतर में एकत्रित हुए छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर शिक्षा तंत्र को खा जाने का आरोप लगाया और संघ को अपने निशाने पर लिया।

सांसद राहुल गांधी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आरएसएस शिक्षा-तंत्र को खत्म करने पर तुला हुआ है। उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान के तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरएसएस के लोग वाइस चांसलर बने बैठे हैं। इसके बाद बहुत जल्द ही राज्यों की यूनिवर्सिटीज में भी आरएसएस के ही वाइस चांसलर नियुक्त होंगे। अब यदि एजुकेशन सिस्टम ही इनके हाथ में चला गया तो सब खत्म हो जाएगा।

शेष पृष्ठ 2 पर

अंदर पढ़ें

खबरें	पृष्ठ
नागपुर हिंसा: योगी की राह...	02
परिसीमन विरोध पर विपक्ष...	03
मोदी की विदेश यात्राओं में...	04
मोदी ने महाकुंभ को बताया...	05
राहुल गांधी ने लोकसभा में...	06
मैं हिंदू हूं: मुझे प्रमाणपत्र की...	07
नीतिश को आश्रम चले जाना...	08
पीएम मोदी ने तुलसी गबार्ड...	09
मेरे राष्ट्रप्रथम विश्वास जैसी...	10
सेंट्रल बैंकिंग, लंदन ने आरबीआई..	11
तेलंगाना सरकार ने पेश किया...	12
स्वास्थ्य निधि का पूरा पैसा...	13
शाहरूख और विराट कोहली...	14
'कर्ज' के लिए ट्रॉफी मिलते...	15
फिल्मों में की गई हिंदी की...	16

This world is a bitter tree, it has only two sweet nectar like fruits - one is soft voice and the other is company of gentlemen.

-Chanakya

कर्नाटक विधानसभा:
6 माह के लिए 18 भाजपा विधायक निलंबित

■ **बीएनटी न्यूज**

कर्नाटक विधानसभा ने विधानसभा की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए 18 भाजपा विधायकों को छह महीने के लिए निलंबित करने संबंधी विधेयक पारित कर दिया। विधेयक को कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने पेश किया। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने 'हनी-ट्रैप' मामलों के मुद्दे पर हंगामा करने और सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 18 विधायकों को विधानसभा से निलंबित कर दिया।

तरीके से संचालित किया।

निलंबित विधायकों में विपक्ष के मुख्य सचेतक डोड्डनगौड़ा एच पाटिल, अश्वथ नारायण सीएन, एसआर विश्वनाथ, बीए बसवराज, श्री एमआर पाटिल, चन्नबसप्पा (चन्नी), बी सुरेश गौड़ा, उमानाथ ए कोट्यान, शरणु सालगर, शैलेन्द्र बेलडेल, सीके राममूर्ति, यशपाल ए सुवर्णा, बीपी हरीश, भरत शेट्टी वाई,

भाजपा विधायकों को 6 महीने के लिए निलंबित करना सही नहीं

कर्नाटक विधानसभा से भाजपा के 18 विधायकों को निलंबित किए जाने पर भाजपा सांसद जगदीश शेट्टार ने कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि स्पीकर का व्यवहार ठीक नहीं है। विधायकों को एक दिन के लिए निलंबित किया जा सकता था, लेकिन छह महीने के लिए उन्हें निलंबित करना ठीक नहीं है।

भाजपा सांसद जगदीश शेट्टार ने कर्नाटक विधानसभा में भाजपा के 18 विधायकों को निलंबित किए जाने पर बीएनटी न्यूज से बात करते हुए कहा, 'सदन में अनुशासन बनाए रखना चाहिए, लेकिन विपक्ष के विरोध के मद्देनजर स्पीकर का इस तरह से विधायकों को निलंबित करना ठीक नहीं है। स्पीकर ने अपने कार्यालय में बुलाकर चेतावनी दी, लेकिन बाद में छह महीने के लिए निलंबित कर दिया गया, जो सबसे निंदनीय है। इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई थी। निलंबन को रद्द किया जाना चाहिए, स्पीकर का व्यवहार ठीक नहीं है। एक दिन के लिए निलंबित किया जा सकता था। स्पीकर ने असंवैधानिक कदम उठाया है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।'

शेष पृष्ठ 2 पर

विपक्षी भाजपा और जद (एस) ने एक मंत्री और अन्य राजनेताओं से जुड़े कथित 'हनी-ट्रैप' प्रयास की न्यायिक जांच एक मौजूदा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराने की मांग की। भाजपा विधायकों ने सदन के वेल में घुसकर और अध्यक्ष की कुर्सी के सामने कागज फाड़कर और फेंककर व्यवधान पैदा किया। यह कार्रवाई सदस्यों द्वारा दिन की शुरूआत में विधानसभा की कार्यवाही में कथित बाधा डालने के जवाब में की गई थी, जब उन्होंने अध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना की और खुद को अनुशासनहीन और अपमानजनक

मुनिरत्ना, बसवराज मैटिमूड, धीरज मुनिराजू और चंद्रू लमानी शामिल हैं। निलंबन आदेश के अनुसार, इन सदस्यों को विधानसभा हॉल, लॉबी और गैलरी में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा।

उन्हें किसी भी स्थायी समिति की बैठक में भाग लेने और विधानसभा के एजेंडे में अपने नाम से कोई विषय या मामला सूचीबद्ध करने से भी मना किया जाएगा। निलंबन अवधि के दौरान उनके द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उन्हें समिति के चुनावों में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आवश्यकता है
वीडियो एडिटर, कंटेंट राइटर एवं वेब डेवलपर
संपर्क करें:
9990533306

CORRUPTION ! तुझे सलाम

बात वही, सोच नई
हर खबर पर पैनी नजर

जज का कैश कांड
कब होगा न्यायपालिका में सुधार?

संपादक की कलम से...

राजेन्द्र कुमार गोयल
मुख्य संपादक
chiefeditor@bntonline.in

घटना की शुरूआत होती है 14 मार्च 2025 को, होली की छुट्टियों के दौरान, जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी बंगले, तुगलक क्रिसेंट, लुटियंस दिल्ली, में आग लगी। उस समय जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी भोपाल में थे। उनकी बेटी और घरेलू स्टाफ ने आग लगने की सूचना दी और फायर ब्रिगेड को बुलाया। आग बुझाने के बाद, फायर ब्रिगेड और मौके पर मौजूद दिल्ली पुलिस ने स्टोररूम में जले हुए जूट के थैलों में भारी मात्रा में नकदी देखी। शुरूआती अनुमान के अनुसार, यह राशि रु15 करोड़ तक हो सकती है, हालाँकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। वीडियो और तस्वीरों में जली हुई 500 रुपये की नोटें दिखाई दीं, जिनमें महात्मा गांधी की तस्वीरें आंशिक रूप से जल चुकी थीं।

प्रारंभिक प्रतिक्रिया और विवाद

फायर डिपार्टमेंट ने आग को 'स्टेशनरी और घरेलू सामानों' से जुड़ा बताया, लेकिन कैश का कोई आधिकारिक उल्लेख नहीं किया। दिल्ली फायर सर्विस के निदेशक अतुल गर्ग ने बाद में कहा कि उनके कर्मियों ने 'एक भी पैसा' नहीं देखा और स्थान पुलिस को सौंप दिया गया। हालाँकि, वीडियो और तस्वीरें (जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जारी कीं) इस दावे से मेल नहीं खातीं। जस्टिस वर्मा ने इसे 'षड्यंत्र' करार दिया। उन्होंने कहा कि न तो वह और न ही उनका परिवार उस स्टोररूम में नकदी रखता था। उनका दावा है कि यह उनके खिलाफ छवि खराब करने की साजिश है और आग लगने के बाद जब वे स्टोररूम में गए, तो वहाँ कोई नकदी नहीं थी। बाद में वीडियो सामने आने पर उन्होंने साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की आशंका जताई। स्टोररूम में जबरन घुसने के कोई सबूत नहीं मिले। यह जगह घरेलू स्टाफ, माली और CPWD कर्मियों के लिए सुलभ थी, जिससे यह सवाल उठता है कि कैश वहाँ कैसे पहुँचा।

सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम की कार्रवाई

घटना की जानकारी दिल्ली पुलिस और सरकार के माध्यम से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना तक पहुँची। CJI ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक बुलाई। 20 मार्च 2025 को, कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से जस्टिस वर्मा को उनके मूल कोर्ट, इलाहाबाद

हाई कोर्ट, में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह ट्रांसफर जाँच से स्वतंत्र है और पहले से विचाराधीन था। 21 मार्च 2025 को, उखक ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय से रिपोर्ट माँगी। इसके बाद, 22 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक तीन सदस्यीय समिति गठित की, जिसमें शामिल हैं:

1. जस्टिस शील नागू (पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश)
2. जस्टिस जी.एस. संधवालिया (हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश)
3. जस्टिस अनु शिवरामन (कर्नाटक हाई कोर्ट की जज)

यह समिति जाँच करेगी और अपनी रिपोर्ट उखक को सौंपेगी। जस्टिस वर्मा को अस्थायी रूप से न्यायिक कार्यों से हटा दिया गया है और

शेष पृष्ठ 2 पर

2014 में क्यों टूटा था शिवसेना-भाजपा का गठबंधन?

■ **बीएनटी न्यूज**

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए 2014 में शिवसेना और भाजपा के बीच हुए नाटकीय विवाद की अंदरूनी कहानी साझा की। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर के अभिनंदन समारोह में फडणवीस ने पहली बार गठबंधन टूटने के कारणों के बारे में खुलकर बात की।

फडणवीस ने कहा: 'हम शिवसेना को 147 सीटें देने के लिए तैयार थे, और यह तय हुआ था कि मुख्यमंत्री हमारी तरफ से होगा, जबकि उपमुख्यमंत्री शिवसेना से होगा।'

उन्होंने आगे दावा किया कि शुरूआती चचाओं में आपसी समझ का संकेत मिला, लेकिन सीट आवंटन पर समझौता करने से शिवसेना के इनकार के कारण गठबंधन टूट गया।

फडणवीस ने बताया, 'लेकिन उद्धव ठाकरे 151 सीटों पर अड़े रहे और यही वह समय था जब गठबंधन टूट गया।'

उनके अनुसार, भाजपा ने सीट बंटवारे का एक

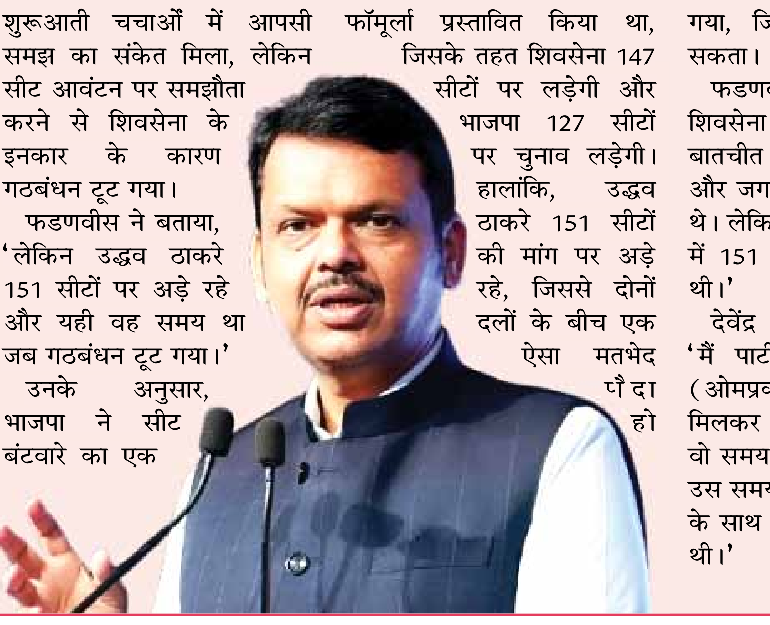

फॉमूर्ला प्रस्तावित किया था, जिसके तहत शिवसेना 147 सीटों पर लड़ेगी और भाजपा 127 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि, उद्धव ठाकरे 151 सीटों की मांग पर अड़े रहे, जिससे दोनों दलों के बीच एक ऐसा मतभेद पैदा हो गया, जिसे सुलझाया नहीं जा सकता।

फडणवीस ने आगे कहा: 'हम शिवसेना के नेतृत्व के साथ बातचीत कर रहे थे और हम उन्हें और जगह देने के लिए भी तैयार थे। लेकिन उद्धव ने अपने दिमाग में 151 की संख्या तय कर ली थी।'

देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 'मैं पार्टी अध्यक्ष था। उन्होंने (ओमप्रकाश माथुर) कहा कि हम मिलकर सरकार लाएंगे और यह वो समय था जब हमारे प्रिय मित्र उस समय की तत्कालीन शिवसेना के साथ हमारी बातचीत चल रही थी।'

शेष पृष्ठ 2 पर

राजीव चंद्रशेखर चुने गए केरल भाजपा के नए अध्यक्ष

■ **बीएनटी न्यूज**

पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को भाजपा की केरल इकाई का नया अध्यक्ष चुना गया है। भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक प्र'ाद जोशी ने पार्टी की राज्य परिषद की बैठक के दौरान यह घोषणा की।

वहीं, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और अपने लोकसभा प्रतिद्वंद्वी राजीव चंद्रशेखर को भाजपा की केरल राज्य इकाई का नया अध्यक्ष चुने जाने पर

बधाई दी।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'भाजपा के नवनिर्वाचित केरल प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर को बधाई और शुभकामनाएं। एक बार फिर आमने-सामने आने की उम्मीद है।'

राजीव चंद्रशेखर को 2024 के लोकसभा चुनावों में तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद शशि थरूर से हार का सामना करना पड़ा था।

राजीव 16,077 मतों के अंतर से हार गए, फिर भी उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार किया तथा 35.52 प्रतिशत वोट प्राप्त किए, जो इस सीट पर पार्टी के लिए अब तक का सर्वाधिक वोट शेयर है, तथा ओ. राजगोपाल द्वारा स्थापित 32.32 प्रतिशत के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व युवाओं के बीच चंद्रशेखर की अपील और विकास पर उनके फोकस पर दांव लगा रहा है, ताकि केरल में पार्टी की संभावनाओं को मजबूत किया

शेष पृष्ठ 2 पर

मुद्दों की बात

जनता की परेशानी सत्ता के गलियारे तक आवाज पहुंचाएं

आओ मिलकर
आवाज उठाएं

जनसंख्या विस्फोट * बेरोजगारी * आत्महत्या करता किसान * दमघोंटू प्रदूषण * अनाज के लिए भंडारण की कमी * न्याय में देरी * भूख * शिक्षा, आदि अनेक मुद्दे...

Breaking News Today
339, 3rd Floor , Tower B-3, Spaze Techpark, Sohna Road, Gurgaon-122002 Haryana, India.

राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में एक खेल कार्यक्रम में राष्ट्रगान के दौरान हंसते और बोलते हुए कैमरे पर कैद होने के बाद विपक्ष के निशाने पर आ गए। उनके पूर्व डिप्टी तेजस्वी यादव ने उन पर राज्य और राष्ट्र का अपमान करने का आरोप लगाया। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सेपकटकरा विश्व कप के उद्घाटन के मौके पर नीतीश कुमार कैमरे पर आईएएस अधिकारी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार से हंसते और बात करते हुए कैद हुए, जो मंच पर उनके ठीक बगल में खड़े थे।

वे अधिकारी के कंधे पर हाथ रखते और उनका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करते देखे गए। एक बार तो वे मुस्कुराते हुए दर्शकों में से किसी को नमस्कार करते हुए हाथ जोड़ रहे थे। दीपक कुमार को मुख्यमंत्री की आस्तीन खींचते हुए देखा गया ताकि वे स्थिर रहें। इससे पहले, जब राष्ट्रगान की घोषणा हुई तो नीतीश कुमार मंच से उतर गए और प्रतिभागियों से हाथ मिलाने चले गए। राष्ट्रगान का वीडियो वायरल होते ही विपक्ष ने सोशल मीडिया पर आलोचनाओं की बाढ़ ला दी।

तेजस्वी ने एक्स पर लिखा कि कम से कम कृपया राष्ट्र गान का तो अपमान मत करिए मा॰ मुख्यमंत्री जी। युवा, छात्र, महिला और बुजुर्गों को तो आप प्रतिदिन अपमानित करते ही है। कभी महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर ताली बजा उनकी शहादत का मखौल उड़ाते है तो कभी राष्ट्रगान का! आपको याद दिला दें कि आप एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री है। चंद सेकंड के लिए भी आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिर नहीं है और आपका इस तरह अचेत अवस्था में इस पद पर बने रहना प्रदेश के लिए अति चिंताजनक बात है। बिहार को बार-बार यूं अपमानित मत कीजिए।

लालू यादव ने भी एक्स पर वीडियो पोस्ट किया है। कैप्शन में लिखा है, "राष्ट्रगान का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिहारवासियों, अब भी कुछ बचा है?"

इस मामले पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के सूत्रों ने संकेत दिया है कि इस मुद्दे पर राज्य विधानसभा में संभावित विवाद को टालने के लिए मुख्यमंत्री बिना शर्त माफी मांग सकते हैं।

नागपुर हिंसा : योगी की राह पर फडणवीस; दंगाई करेंगे नुकसान की भरपाई, प्रॉपर्टी भी होगी जब्त

■ **बीएनटी न्यूज**

महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसा के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दंगे में हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से कराई जाएगी और अगर वे भुगतान नहीं करते, तो उनकी संपत्ति जब्त कर बेची जाएगी।

सीएम फडणवीस ने बताया कि दंगे में शामिल 104 लोगों को पकड़ा गया है, जिनमें से 92 गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि शेष नाबालिग हैं। दंगाइयों की पहचान सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए की जा रही है और अंतिम आरोपी की गिरफ्तारी तक कार्रवाई जारी रहेगी।

उन्होंने कहा कि हिंसा औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र जलाने के बाद फैली। इसके बाद सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई गईं कि एक चादर जलाई गई थी, जिस पर कुरान की आयतें लिखी थीं, लेकिन यह पूरी तरह झूठ था। उन्होंने ऐलान किया कि सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों को भी आरोपी बनाया जाएगा। इसके साथ ही बांग्लादेशी कनेक्शन की जांच भी की जाएगी, हालांकि इस पर फिलहाल कुछ कहना जल्दबाजी होगी।

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की

तर्ज पर दंगाइयों पर कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने स्पष्ट किया, 'जहां बुलडोजर चलाने की जरूरत होगी, वहां बुलडोजर चलेगा।' मालेगांव में एमडीपी के कार्यालय खुलने और उसकी फंडिंग को लेकर भी जांच होगी। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी जगजाहिर है, लेकिन अब इसके आर्थिक स्रोतों की गहन जांच होगी।

उन्होंने कहा कि नागपुर में हुई हिंसा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शहर के 80 प्रतिशत इलाके हिंसा से प्रभावित नहीं हैं और जहां दंगे हुए थे, वहां भी अब शांति है। इसलिए पीएम मोदी का दौरा तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। इसके साथ ही सीएम फडणवीस ने आश्वासन दिया कि दंगे में जिनकी गाड़ियां और संपत्ति क्षतिग्रस्त हुई हैं, सरकार उनकी मदद करेगी। अगले सात दिन में राहत योजना लागू की जाएगी, लेकिन जो भी नुकसान हुआ है, उसकी वसूली दंगाइयों से ही होगी।

उन्होंने दो टूक कहा कि किसी को भी दंगा भड़काने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। कड़ी कार्रवाई कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न दोहराई जाएं।

भागलपुर के सुल्तानगंज में महागठबंधन ने किया इफ्तार पार्टी का आयोजन

■ **बीएनटी न्यूज**

बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड क्षेत्र के दिलगौरी मोड़ ईदगाह मैदान प्रांगण में विपक्षी महागठबंधन द्वारा इफ्तार का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस, राजद और वामपंथी दलों के कई नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए।

बिहार युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ललन यादव के नेतृत्व में आयोजित भव्य दावत-ए-इफ्तार पार्टी में सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों के रोजेदार और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। मौके पर उपस्थित सभी रोजेदारों ने देश में अमन और चैन के लिए दुआएं मांगी और लजीज व्यंजनों का आनंद लेते हुए सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया।

उपस्थित लोगों ने कहा कि महागठबंधन के पूर्व प्रत्याशी ललन यादव द्वारा यह इफ्तार दावत देकर आपसी भाईचारे का बहुत बड़ा पैगाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि इन दिनों पवित्र रमजान का महीना चल रहा है। यह महीना दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है। रमजान का यह पाक महीना न केवल इबादत का समय है, बल्कि यह एकता, भाईचारे और साझा सुख-दुख का प्रतीक भी है। इसी भावना के साथ, सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में दो विशेष इफ्तार पार्टियों का आयोजन किया गया है, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों से रोजेदारों ने हिस्सा लिया।

पृष्ठ 1 का शेष

जज का कैश कांड

उन्हें अपने फोन डेटा को संरक्षित करने का निर्देश दिया गया है। अब जस्टिस वर्मा के 6 महीने की कॉल डिटेल्स की जांच की जाएगी।

जाँच रिपोर्ट और साक्ष्य

दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय ने अपनी रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा से कैश की मौजूदगी का स्पष्टीकरण माँगा। रिपोर्ट में कहा गया कि स्टोररूम में कोई जबरन घुसपैठ नहीं हुई, और यह केवल स्टाफ के लिए सुलभ था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दस्तावेज: 22 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने असाधारण कदम उठाते हुए रिपोर्ट, वीडियो और तस्वीरें सार्वजनिक कीं। वीडियो में एक फायरमैन जले हुए नोटों को प्लास्टिक बैग से निकालते दिखा, और एक आवाज कहती है, 'महात्मा गांधी में आग लग गई।' सफाई कर्मचारी इंदरजीत ने बताया कि घटना के कुछ दिन बाद सड़क पर जली हुई 500 रुपये की नोटें मिलीं, जिससे साक्ष्य नष्ट करने की आशंका बढ़ी।

जस्टिस वर्मा का इतिहास और संदेह

जस्टिस यशवंत वर्मा (जन्म: 6 जनवरी 1969, प्रयागराज) ने 1992 में रीवा विश्वविद्यालय से LLB किया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। वे 2014 में अतिरिक्त जज और 2016 में स्थायी जज बने। अक्टूबर 2021 में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया गया। 2018 में, CBI ने सिंभाओली शुगर मिल्स बैंक धोखाधड़ी मामले में जस्टिस वर्मा को गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में आरोपी नंबर 10 नामित किया था। यह मामला रु148.59 करोड़ के फर्जी ऋण से जुड़ा था। हालाँकि, यह जाँच आगे नहीं बढ़ी, और सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में इसे रद्द कर दिया था। इस पुराने मामले ने वर्तमान विवाद को और जटिल बना दिया। 2023 में, जस्टिस वर्मा ने UPI की प्रशंसा की थी, इसे नकद लेनदेन कम करने वाला क्रांतिकारी कदम बताया था। अब कैश मिलने से यह विडंबना चर्चा में है।

विरोध और प्रतिक्रियाएँ

इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने ट्रांसफर का विरोध किया, इसे 'कचरे का डिब्बा' बनाना करार दिया। अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा, '99% जज ईमानदार हैं, तो 1% को क्यों बचाया जा रहा है?' दिल्ली हाई कोर्ट बार अध्यक्ष मोहित माथुर ने कहा कि यदि जाँच में दोष सिद्ध हुआ, तो निंदा होनी चाहिए, लेकिन जल्दबाजी से जनता का भरोसा कम हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ने इसे गंभीर मामला बताया और पूछा कि यह पैसा किसका था और क्यों था। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और इंदिरा जयसिंह ने कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना की, इसे पारदर्शी बनाने की माँग की।

कानूनी प्रक्रिया और संभावित परिणाम

सुप्रीम कोर्ट की 1999 की प्रक्रिया के तहत, CJI पहले जज से जवाब माँगता है। यदि जवाब असंतोषजनक हो, तो तीन जजों की समिति बनती है। यदि दोष सिद्ध हो, तो CJI जज को इस्तीफा देने को कह सकता है, या संसद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है (अनुच्छेद 124(4))। K. Veeraswami (1991) मामले के अनुसार, CBI जांच के लिए CJI की मंजूरी जरूरी है। अभी तक यह शुरू नहीं हुई।

न्यायपालिका के अंदर भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत गंभीर है। यह जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करे कि नियुक्ति प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी होना चाहिए। संदेह जनक आचरण वाले जजो के काम काज पर टाईम बाउंड जांच होनी चहिये, ताकि आम जनता का न्यायपालिका पर फिर से भरोसा कायम हो सके।

इस तरह के घटनाओं से लोगों का विश्वास कानून व्यवस्था और तंत्र पर shake होता है। लोगों में यह भावना घर कर रही है कि घोटालेबाजों का कुछ नहीं होगा। यह एक आम धारणा है कि ये घोटालेबाज अपनी money power एवं contacts का इस्तेमाल कर बच निकलेंगे। घोटालेबाजों का राजनैतिक गठजोड़ व सत्ता लोलुप्ता भी एक बड़ी समस्या है। निष्पक्ष जांच नहीं हो पाती। Investigating Agencies पर political pressure डाला जाता है। घोटालेबाजों को कानून का कोई भय नहीं कानूनों को कठोरता से लागू किया जाना चाहिए। जांच time-bound manner में की जानी चाहिए। जरा सोचिए! फैसला आप खुद कीजिये।

डीके शिवकुमार के 'संविधान' वाले बयान संसद से सड़क तक हंगामा

■ **बीएनटी न्यूज**

डीके शिवकुमार ने कर्नाटक में सरकारी ठेकों में प्रस्तावित अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के प्रावधान पर बयान दिया था।

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डीके शिवकुमार का पुतला फूंका। वहीं, राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मुद्दे को उठाया।

इसके बाद राज्यसभा में ही केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इस पर जवाब मांगा। डीके शिवकुमार का कहना है कि बीजेपी ने उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया है।

वहीं कांग्रेस का दावा है कि उन्होंने इस मामले में जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है।

किस बयान पर हंगामा मचा है?

कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। कार्यक्रम के दौरान उनसे कर्नाटक में अल्पसंख्यकों के लिए प्रस्तावित आरक्षण को लेकर सवाल पूछा गया था।

एंकर डीके शिवकुमार से पूछते हैं- आपकी आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है।

इस पर डीके शिवकुमार कहते हैं, 'हां, मैं सहमत हूं। देखते हैं, कोर्ट क्या कहता है। हमने एक शुरूआत की है। मुझे पता है कि लोग कोर्ट जाएंगे। हमें अच्छे दिनों का इंतजार करना चाहिए, अच्छे दिन आएंगे। बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, संविधान बदल रहा है। ऐसे फैसले भी आ रहे हैं जो संविधान को भी बदल देंगे।'

अल्पसंख्यकों को ठेकेदारी में चार प्रतिशत आरक्षण की जरूरत क्यों है?

इस सवाल के जवाब में डीके शिवकुमार बताते हैं, 'यह हमारी ड्यूटी है कि समाज के सभी वर्गों का उत्थान करें। आजादी के बाद आरक्षण तय हुआ था और कहा गया था कि समाज के सभी कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। इसलिए आर्थिक रूप से हमें उन्हें ऊपर उठाना चाहिए।'

संविधान कोई नहीं बदल सकता: खड़गे

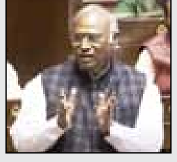

राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो डीके शिवकुमार के बयान पर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी के सांसदों ने इसे मुद्दा बनाया और डीके शिवकुमार के इस्तीफे की मांग की।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान कोई नहीं बदल सकता है, इसे बचाने के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा, 'कौन से आदमी ने कहा कि देश का संविधान बदलने वाले हैं। देश का संविधान जिसे बाबासाहेब आंबेडकर ने बनाया है उसे कोई बदल नहीं सकता है। उसकी रक्षा के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले हैं।'

खड़गे के बयान से पहले जेपी नड्डा ने इस विषय पर चर्चा करने और अल्पसंख्यकों को सरकारी ठेके में आरक्षण को वापस लेने की मांग की थी।

सदन में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'सर, कांग्रेस के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता, ज़िम्मेदार कांग्रेसी नेता, जो कि एक संवैधानिक पद पर हैं। उन्होंने एक बयान दिया कि वो भारत का संविधान बदलने जा रहे हैं ताकि मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दिया जा सके। हम इस बयान को हल्के में नहीं ले सकते।'

'ये लोग हमेशा संविधान की बात करते हैं और बाबा साहेब आंबेडकर की तस्वीर पकड़े रहते हैं। लेकिन इनके लोग आधिकारिक तौर पर ऐसे बयान देते हैं कि वो संविधान बदल देंगे। मैं यहां मौजूद कांग्रेस के अध्यक्ष से कहूंगा कि वो इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति पूरी तरह साफ करें।'

डीके शिवकुमार की सफाई

सदन में हंगामे के बाद बीजेपी ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बीजेपी का कहना है कि कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री ने एक चैनल के कार्यक्रम में संविधान बदलने की बात कही है।

डीके शिवकुमार का कहना है कि उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है और उन्होंने संविधान बदलने वाली बात नहीं कही है।

डीके शिवकुमार ने कहा, 'मैं नड्डा जी से सीनियर और समझदार नेता हूं। मैं पिछले 36 सालों से सदन में हूं। मुझे बेसिक समझ है। मैंने कैजुअली कह दिया था कि कई फैसलों के बाद कई बदलाव हो सकते हैं। पिछड़ा वर्ग के कोटे के मुताबिक पहले ही आरक्षण दिया जा चुका है। मैंने नहीं कहा कि हम संविधान बदलने जा रहे हैं।'

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का कहना है कि जस्टिस यशवंत वर्मा और दूसरे मामलों से ध्यान हटाने के लिए यह मुद्दा उठाया जा रहा है।

जयराम रमेश का कहना है, 'नड्डा जी और रिजिजू जी, दोनों ने राज्यसभा में सही बात नहीं बोली है। कांग्रेस और हमारे नेताओं को बदनाम किया। जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण देने के पक्ष में है, ये तो बिल्कुल झूठ है। हमने चेयरमैन साहब को नड्डा जी और रिजिजू जी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है।'

यह गांधी परिवार का बयान

कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के 'संविधान बदल रहा है' बयान पर अब राजनीति तेज हो गई है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने डीके शिवकुमार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनका बयान गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व करता है।

भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, 'डीके शिवकुमार द्वारा दिया गया बयान केवल उनका अपना बयान नहीं है, बल्कि यह गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। जब वह कहते हैं कि अगर वे कभी सत्ता में आए तो मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान बदल देंगे, तो यह उनके असली इरादों को दशार्ता है। उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को दे देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगा और उनके दिए संविधान को बदलने की कोशिश करेगा, ऐसा हम होने नहीं देंगे।'

क्या है पूरा मामला?

बीते हफ्ते कर्नाटक विधानसभा में सरकारी ठेकों में अल्पसंख्यकों को चार प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी विधेयक पारित हुआ था।

इस दौरान सदन में विपक्ष ने 'हनीट्रैप' के आरोपों की न्यायिक जांच के लिए जमकर हंगामा किया था।

सिद्दारमैया के पिछले मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान ऐसी ही आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए की गई थी। अब इस प्रस्ताव में मुसलमान, ईसाई, जैन और सिख आदि अल्पसंख्यक समूहों को आरक्षण देने का प्रावधान है।

कर्नाटक में बीजेपी विधायकों ने बिल का विरोध करते हुए कहा था कि विधेयक का उद्देश्य 'केवल समाजों का ध्रुवीकरण करना' और 'धार्मिक समाजों के बीच सामाजिक ताने-बाने और सद्भाव को नष्ट करना' है।

केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन...

का दावा भी कर सकते हैं। सांसदों को सालाना 50,000 यूनिट बिजली और 4,000 किलोलीटर पानी की मुफ्त सुविधा भी मिलती है।

सरकार उनके आवास और रहने की व्यवस्था भी करती है। अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान, सांसदों को नई दिल्ली में किराए-मुक्त आवास प्रदान किया जाता है। उन्हें अपनी वरिष्ठता के आधार पर छात्रावास के कमरे, अपार्टमेंट या बंगले मिल सकते हैं। जो सांसद आधिकारिक आवास का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, वे मासिक आवास भत्ता प्राप्त करने के पात्र हैं।

सांसदों के वेतन में 24 प्रतिशत की यह वृद्धि 'सांसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954' द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत की गई है। इस अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार को सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन करने का अधिकार है।

भाजपा विधायकों को 6 महीने के लिए निलंबित...

भाजपा सांसद जगदीश शेट्टार ने परिसीमन पर कहा, 'विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध करने का बीड़ा उठाया है और इसमें केरल, तेलंगाना और कर्नाटक के मुख्यमंत्री शामिल हैं। उनके (विपक्ष) पास पीएम मोदी और भारत सरकार के खिलाफ बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए वे चाहते हैं कि कुछ मुद्दे जीवित रहें, क्योंकि तमिलनाडु में 2026 में चुनाव हैं। ताकि जनता का समर्थन मिल सके और इस ओर ध्यान आकर्षित किया जा सके। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि अभी तक परिसीमन समिति का गठन नहीं किया गया है।'

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि वह (विपक्ष) राजनीति से प्रेरित होकर मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मुद्दा है।'

कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष यूटी खादर ने 'हनी ट्रैप' मामलों के मुद्दे पर हंगामा करने और सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए भाजपा के 18 विधायकों पर कार्रवाई की। उन्होंने 18 विधायकों को विधानसभा से 6 महीने के लिए निलंबित किया है।

छात्र संगठनों के प्रदर्शन में पहुंचे राहुल गांधी

उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार तो बेरोजगारी पर खामोश है।

देश की युवा पीढ़ी को बेरोजगार बनाया जा रहा है। देश के अंदर किसी को भी रोजगार उपलब्ध नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में हम छात्रहितों पर समझौता हरगिज नहीं करेंगे। छात्रों का आव्हान करते हुए राहुल ने कहा कि हम सभी को एक-साथ मिलकर इन ताकतों से लड़ना है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को देश में व्याप्त बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा प्रणाली पर बात करनी चाहिए, लेकिन उनका सिस्टम तो अंबानी-अडानी तक ही सीमित है। इस दौरान उन्होंने इंडिया अलायंस पर भी अपनी बात रखी और कहा कि इंडिया अलायंस के तौर पर हमारे मध्य विचारधारा को लेकर थोड़ा-बहुत मतभेद हो सकता है, लेकिन हम सब का उद्देश्य एक ही है। हम सब मिलकर देशहित में आरएसएस और उनकी विचारधारा के खिलाफ लगातार काम करते रहेंगे।

राजीव चंद्रशेखर चुने गए केरल भाजपा...

जा सके, खासकर स्थानीय चुनावों के मद्देनजर।

प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार चंद्रशेखर ने औपचारिक रूप से एक समारोह में कार्यभार संभाला, जिसमें निवर्तमान अध्यक्ष के सुरेंद्रन और राज्य प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर सहित वरिष्ठ भाजपा नेता शामिल हुए। पार्टी का झंडा सौंपते हुए सुरेंद्रन ने कहा कि भाजपा ने पिछले एक दशक में केरल में अभूतपूर्व विकास देखा है और विश्वास व्यक्त किया कि चंद्रशेखर के नेतृत्व में पार्टी और मजबूत होगी।

कर्नाटक से तीन बार राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के करीबी माने जाते है। वह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुके हैं। उन्होंने मोदी सरकार में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, कौशल विकास और उद्यमिता, और जल शक्ति जैसे प्रमुख विभागों को संभाला था।

2014 में क्यों टूटा था शिवसेना-भाजपा का गठबंधन?

उन्होंने ओम प्रकाश माथुर के महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के बारे में विस्तार से बताया, जिन्होंने भाजपा नेता अमित शाह से बात की, जिन्होंने फिर इस मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाया।

'गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री से बात की, और यह तय हुआ कि अगर भाजपा के लिए 127 और शिवसेना के लिए 147 का फॉमूर्ला होगा, तभी गठबंधन जारी रहेगा। अन्यथा, गठबंधन काम नहीं करेगा,' फडणवीस ने कहा।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने उस महत्वपूर्ण क्षण का खुलासा किया, जिसके कारण अंतिम रूप से गठबंधन टूट गया। उन्होंने कहा: 'मुझे अमित शाह और ओम प्रकाश माथुर पर भरोसा था। हमें विश्वास था कि हम जीत सकते हैं, लेकिन पार्टी के बाकी लोग उतने आशावादी नहीं थे।'

अंततः, माथुर और अमित शाह के समर्थन से फडणवीस ने शिवसेना को अल्टीमेटम दिया, जिसमें शिवसेना के लिए 147 और भाजपा के लिए 127 के प्रस्तावित फॉमूर्ले पर शिवसेना के साथ चुनाव लड़ने की पेशकश की गई।

फडणवीस ने याद करते हुए कहा, 'हमने उनसे कहा कि अगर आप 147 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हम आपके साथ खड़े होंगे और हम 127 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दोनों पार्टियों को बेहतरीन नतीजे मिलेंगे और दोनों 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे।' हालांकि, उद्धव ठाकरे ने 151 सीटों पर अड़े रहने के कारण प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

फडणवीस के अनुसार, इस हठ के कारण गठबंधन टूट गया।

फडणवीस ने कहा: 'लेकिन ऐसा लगता है कि नियति के नियम में कुछ और ही लिखा था – मुझे मुख्यमंत्री बनना था।'

फडणवीस ने चुनाव रणनीति के बारे में भी जानकारी साझा की। सीट बंटवारे की बातचीत में असफलता के बावजूद, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने रिकॉर्ड संख्या में निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ा।

उन्होंने कहा, 'हमने 260 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था, जो अभूतपूर्व था। इससे पहले, हमने कभी 117 से ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा था।' फडणवीस के अनुसार, 260 सीटों पर लड़ने के इस साहसिक निर्णय ने महाराष्ट्र में भाजपा की सफलता की नींव रखी।

फडणवीस के मुताबिक, 'तब से, भाजपा महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है और पिछले 30 वर्षों में 100 सीटों का आंकड़ा पार करने वाली एकमात्र पार्टी है। इस सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और ओम प्रकाश माथुर को जाता है।'

यह खुलासा उन नाटकीय राजनीतिक घटनाओं पर नई रोशनी डालता है, जिसके कारण भाजपा-शिवसेना गठबंधन टूट गया और महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह बदल गई।

परिसीमन विरोध पर विपक्ष एकजुट

■ बीएनटी न्यूज

देश में आगामी होने वाले परिसीमन को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसके विरोध में शनिवार को चेन्नई में बैठक हुई जिसमें 6 राज्यों के सीएम शामिल हुए। ये बैठक तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने बुलाई थी। इस बैठक में ज्यादातर दक्षिणी राज्यों के सीएम शामिल हुए। इन नेताओं ने परिसीमन का विरोध करते हुए कें द्र की मोदी सरकार पर हमला किया। नेताओं ने कहा परिसीमन राज्यों से चर्चा के बाद हो नहीं तो राज्यों के बीच मतभेद हो जाएगा। विपक्षी नेता ने परिसीमन प्रक्रिया को इस तरह से संचालित करने के महत्व पर प्रकाश डाला कि संसद के दोनों सदनों में राज्यों का मौजूदा आनुपातिक प्रतिनिधित्व बना रहे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संसदीय सीटों के आवंटन में कोई भी बदलाव राज्यों के बीच असमानता पैदा कर सकता है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर उनके राजनीतिक प्रभाव पर असर पड़ सकता है। बैठक में कम से कम पांच राज्यों के 14 नेताओं ने भाग लिया – जिनमें

पिनाराई विजयन, भगवंत मान और रेवंत रेड्डी शामिल हैं झ जो उच्च आर्थिक विकास और साक्षरता वाले राज्यों के लिए लोकसभा सीटों के परिसीमन अभ्यास से उत्पन्न खतरे पर विचार–विमर्श कर रहे हैं।

बैठक से पहले चेन्नई नगर निगम की कार्यालय इमारत रिपन बिल्डिंग को रंगीन रोशनी से सजाया गया है। संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) की बैठक के प्रति समर्थन दिखाने के लिए आकर्षक मरीना बीच पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की रेत की आकृति बनाई गई है। केरल, तेलंगाना और पंजाब के मुख्यमंत्री क्रमशः पिनराई विजयन, रेवंत रेड्डी, भगवंत सिंह मान और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के कार्यकारी अध्यक्ष बलविंदर सिंह भुंडर तथा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरल के महासचिव पीएमए सलाम उन नेताओं में शामिल हैं, जो स्टालिन की अध्यक्षता में होने वाली द्रमुक की जेएसी बैठक में हिस्सा लेने के लिए चेन्नई पहुंचे।

कांग्रेस की तेलंगाना इकाई के प्रमुख बी महेश कुमार गौड़ और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव भी चेन्नई पहुंच गए हैं। बीआरएस सूत्रों ने बताया कि केटी रामा राव बैठक में पार्टी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए तमिलनाडु की राजधानी पहुंचे।

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि आगामी परिसीमन की प्रक्रिया के कारण किसी भी राज्य का संसद में प्रतिनिधित्व खत्म न हो। शनिवार को प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में रेड्डी ने इस मुद्दे की गंभीरता को रेखांकित करते हुए चेतावनी दी कि किसी राज्य के लिए लोकसभा या राज्यसभा सीटों की संख्या में कोई भी कमी देश के सामाजिक और राजनीतिक सौहार्द को बिगाड़ सकती है। रेड्डी ने अपने पत्र में कहा, परिसीमन की प्रक्रिया इस तरह से संचालित की जानी चाहिए कि किसी भी राज्य को सदन की कुल सीटों की संख्या के संदर्भ में लोकसभा या राज्यसभा में अपने प्रतिनिधित्व में कोई कमी न झेलनी पड़े। रेड्डी ने केंद्र से संविधान में संशोधन पर विचार करने का आग्रह किया ताकि किसी भी राज्य को अपने संसदीय प्रतिनिधित्व में कमी से बचाया जा सके। सीटों के मौजूदा वितरण की सुरक्षा से शासन के प्रति निष्पक्ष और संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा, क्षेत्रीय असमानताओं को रोका जा सकेगा और संघीय एकता बनी रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री की यह अपील परिसीमन प्रक्रिया पर चर्चा के बीच आई है, जो 2026 की जनगणना के बाद होने की उम्मीद है।

> ● कांग्रेस नेता एम. वीरप्पा मोइली ने कहा, 'एक बहुत मजबूत भावना है कि अगले परिसीमन के जरिए भाजपा सरकार की मंशा दक्षिण में सीटें कम करने की है। हालांकि, वे कहते हैं कि हम इसे कम नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही वे यह आश्वासन भी नहीं देते कि वे उत्तर भारत में इसे नहीं बढ़ाएंगे। इसलिए अगर वे उत्तर भारत में इसे बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब है कि दक्षिण में चुनाव है। वे सिर्फ दक्षिण भारत के लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं।'

इस अभ्यास का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि पैटर्न के आधार पर संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से परिभाषित करना है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई में इस मुद्दे पर पहली संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी डीएमके सरकार परिसीमन प्रक्रिया के निष्पक्ष होने तक लड़ाई जारी रखेगी। स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके ने लंबे समय से चिंता व्यक्त की है कि प्रस्तावित परिसीमन से लोकसभा की संख्यात्मक ताकत उत्तर भारतीय राज्यों के पक्ष में झुक जाएगी और परिवार नियोजन उपायों के लिए दक्षिण भारत को दंडित किया जाएगा, हालांकि भाजपा ने इससे इनकार किया है।

वर्तमान जनसंख्या के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नहीं होना चाहिए। हम सभी को इसका डटकर विरोध करना चाहिए। संसद में जनप्रतिनिधियों की संख्या कम होने से हमारी अपनी बात कहने की ताकत कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर प्रतिनिधित्व कम हो जाता है, तो राज्यों के लिए धन प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू हो जाएगा।

डीके शिवकुमार ने अन्नामलाई पर साधा निशाना

■ बीएनटी न्यूज

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में भाजपा नेता अन्नामलाई के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी।

अन्नामलाई ने दावा किया था कि 22 मार्च को चेन्नई में हुई दक्षिण भारतीय राज्यों की बैठक बिना योजना के आयोजित की गई थी। इस पर शिवकुमार ने कहा कि अन्नामलाई का बयान महत्वपूर्ण नहीं है।

उन्होंने कहा कि असल सवाल यह है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश को क्या संदेश दे रहे हैं। शिवकुमार ने अन्नामलाई पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें कुछ पता नहीं है और वह सिर्फ अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अन्नामलाई राज्य के प्रति नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के प्रति वफादारी दिखा रहे हैं। उन्हें अपना काम करने दें, लेकिन उनकी प्राथमिकता राज्य नहीं, पार्टी है।

राज्य विधानसभा क्षेत्रों की एकजुटता के सवाल पर शिवकुमार ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का जिक्र किया। उन्होंने कहा, 'रेड्डी ने इस मुद्दे पर पहले चर्चा की है, लेकिन अभी प्राथमिकता

दक्षिण भारत की एकजुट आवाज को मजबूत करने की है। पहले हम अपनी स्थानीय आवाज को ताकत दें, फिर संसद में परिसीमन जैसे मुद्दों पर बात करेंगे।'

शिवकुमार ने कहा कि डीएमके ने शानदार काम किया है और वह उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।

शिवकुमार ने अन्नामलाई पर तंज कसते हुए कहा, 'लोग कार्बन जैसे मुद्दों पर अटके हैं, लेकिन असली विसंगति यह है कि देश के नेतृत्व का संदेश क्या है। अन्नामलाई को कुछ नहीं पता, वह सिर्फ पार्टी के प्रति वफादारी दिखाना चाहते हैं। हमें अपनी एकता पर ध्यान देना है।' उन्होंने कहा कि इस बैठक में दक्षिण भारत के राज्यों ने लोकसभा सीटों के परिसीमन के खिलाफ एकजुटता दिखाई। शिवकुमार ने इसे देश के हित में बताया और कहा कि दक्षिण भारत ने जनसंख्या नियंत्रण में योगदान दिया है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

भाजपा और संघ के बीच सब कुछ ठीकः सरकार्यवाह होसबले

■ बीएनटी न्यूज

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने बेंगलुरु में आयोजित अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के अंतिम दिन भाजपा और आरएसएस के रिश्तों को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान अक्सर इस रिश्ते को लेकर विभिन्न आकलन किए जाते हैं, लेकिन असल आकलन तो देश की जनता ने किया है।

उन्होंने कहा कि आरएसएस भी देश का एक अभिन्न हिस्सा है और अगर वह किसी भूमिका में हैं, तो वे हर सरकार के लिए अभिभावक के रूप में हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई सरकार का हिस्सा नहीं बनता, तो यह अलग बात है, लेकिन फिलहाल आरएसएस और सरकार के बीच कोई संकट नहीं है और सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है।

होसबले ने औरंगजेब के विषय पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने दिल्ली के औरंगजेब मार्ग को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि इसे अब्दुल कलाम मार्ग में बदला गया है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि भारत में औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को कभी भी एक आइकॉन के रूप में क्यों नहीं माना गया, जबकि औरंगजेब को इस श्रेणी में रखा गया है। होसबले के अनुसार, यह उलटा होना चाहिए था।

इसके अलावा, वक्फ से संबंधित मुद्दे पर भी होसबले ने अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि यह केवल आरएसएस का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि समाज के कई लोग भी वक्फ की जमीनों के मामले में

आवाज उठा रहे हैं। इसके समाधान के लिए सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया है और उसके फैसले का इंतजार किया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि संघ समाज से बाहर नहीं है, बल्कि वह समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राम मंदिर का निर्माण आरएसएस की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से समाज के प्रयासों का परिणाम है।

होसबले ने कहा, 'संघ कोई पैरामीटर सेट नहीं करता, और न ही किसी विशेष कार्य को खुद के नाम से जोड़ता है। संघ समाज का हिस्सा है और समाज ही वह शक्ति है, जो परिवर्तन और उपलब्धियां लाती है।' उन्होंने भारत की अस्मिता और संस्कृति के पुनर्निर्माण का श्रेय भी समाज को दिया और कहा, 'भारत की अस्मिता और संस्कृति को पुनः स्थापित करने का काम समाज ने किया है। यह सब भारत के लोगों की मेहनत और प्रयासों का नतीजा है।'

होसबले ने यह स्पष्ट किया कि ऐसे कार्यों को श्रेय समाज के समग्र योगदान को दिया जाना चाहिए, और यह समाज की सामूहिक उपलब्धि है।

उल्लेखनीय है कि इस सभा में देशभर के 1443 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें नॉर्थ ईस्ट से लेकर कन्याकुमारी और जम्मू कश्मीर तक के कार्यकर्ता शामिल थे। सभा में संघ के पिछले एक साल के कार्यकाल की समीक्षा की गई और आगामी समय में संघ के विस्तार और कार्यकुशलता पर जोर देने की बात की गई। होसबले ने कहा, 'विजयादशमी के दिन 100 साल पूरे हो जाएंगे। यह आत्मचिंतन का समय है और समाज तक हमारे काम को पहुंचाने की जरूरत है। साथ ही राष्ट्र निर्माण के लिए आगे का रोड मैप तैयार किया गया है।'

संघ ने 100 साल की इस यात्रा के दौरान समाज के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने का संकल्प लिया। इस संकल्प के तहत विजयादशमी के दिन, 2 अक्टूबर को पूरे देश में 1 लाख स्थानों पर ये पर्व मनाया जाएगा, साथ ही शताब्दी वर्ष समारोह की शुरूआत होगी।

संघ के सरसंघ चालक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में बुद्धिजीवियों के साथ बैठक करेंगे ताकि एक देश, एक संस्कृति के विचार को मजबूती से स्थापित किया जा सके और देश की एकता और संप्रभुता के लिए कार्य किया जा सके। इसके अलावा, 15 से 30 साल के युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

जस्टिस यशवंत वर्मा मामलाः जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित

■ बीएनटी न्यूज

दिल्ली हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के बंगले से कैश मिलने के आरोपों की जांच के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है।

इस समिति में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जी.एस. संधवालिया, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और कर्नाटक हाई कोर्ट की जज अनु शिवरामन शामिल होंगी। इसके अलावा, जस्टिस यशवंत वर्मा को फिलहाल कोई न्यायिक काम नहीं सौंपने का आदेश दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, 'भारत के मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की है, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. संधवालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अनु शिवरामन शामिल हैं।' प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 'दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को फिलहाल न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपने के लिए कहा गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का जवाब और अन्य दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं।'

उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवासीय बंगले में आग लगने से एक बड़ा खुलासा हुआ था। कथित तौर पर उनके घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। इस घटना ने न्यायिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया था। इसने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को भी तत्काल कदम उठाने पर मजबूर कर दिया।

जयराम रमेश ने वक्फ (संशोधन) विधेयक पर भाजपा को घेरा

■ बीएनटी न्यूज

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद और महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस विधेयक को अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ भाजपा की 'रणनीति' का हिस्सा करार देते हुए इसे संविधान और सामाजिक सद्भाव पर हमला बताया।

जयराम रमेश ने अपने बयान में कहा कि यह विधेयक भारत के बहु–धार्मिक समाज में सद्भाव को नुकसान पहुंचाने, अल्पसंख्यकों को बदनाम करने और संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस विधेयक के जरिए समाज को ध्रुवीकृत कर चुनावी लाभ लेने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा कि इसका

उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय की परंपराओं और संस्थाओं को बदनाम करना भी है, ताकि चुनावी लाभ के लिए समाज को स्थायी ध्रुवीकरण की स्थिति में रखा जा सके।

कांग्रेस नेता ने विधेयक को 'गंभीर रूप से दोषपूर्ण' बताते हुए पांच बड़ी खामियां गिनाईं। पहला, वक्फ प्रबंधन के संस्थानों जैसे राष्ट्रीय परिषद, राज्य बोर्ड और ट्रिब्यूनल के अधिकारों को कम किया जा रहा है, ताकि अल्पसंख्यक समुदाय को उनकी धार्मिक परंपराओं और धार्मिक संस्थाओं के प्रशासनिक अधिकार से वंचित किया जा सके।

दूसरा, वक्फ की परिभाषा में जानबूझकर अस्पष्टता लाई गई है। अपनी भूमि को कौन वक्फ उद्देश्यों के लिए दान कर सकता है, यह स्पष्ट नहीं है।

तीसरा, देश की न्यायपालिका द्वारा लंबे समय से निर्बाध चली आ रही परंपरा के आधार पर विकसित किए गए 'वक्फ बाई यूजर' की अवधारणा को समाप्त किया जा रहा है।

चौथा, वक्फ प्रशासन को कमजोर करने और अतिक्रमण को बढ़ावा देने के प्रावधान जोड़े गए हैं। साथ ही, वक्फ की जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों को बचाने के लिए अब कानून में और अधिक सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं।

पांचवां, कलेक्टर और राज्य सरकार के अधिकारियों को वक्फ संपत्तियों पर एकतरफा निर्णय लेने की व्यापक शक्तियां दी गई हैं। राज्य सरकार के अधिकारियों के पास अब किसी की शिकायत पर या वक्फ संपत्ति के सरकारी संपत्ति होने के आरोप मात्र पर अंतिम निर्णय होने तक किसी भी वक्फ की मान्यता रद्द करने का अधिकार होगा।

जयराम रमेश ने यह भी दावा किया कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में 428 पृष्ठों की रिपोर्ट को बिना विस्तृत चर्चा के जबरन पारित करवाया गया, जो संसदीय प्रक्रिया का उल्लंघन है। उन्होंने कहा, 'यह विधेयक मूल रूप से भारत के संविधान पर हमला है।'

बाबासाहेब का सपना आज भी अधूरा उनकी लड़ाई हम पूरी ताकत से लड़ेंगे

■ बीएनटी न्यूज

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि संविधान निमार्ता बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर का सपना आज भी अधूरा है और बराबरी तथा सम्मान उनकी लड़ाई को कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ेगी।

उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के पूर्व प्रमुख और शिक्षाविद् सुखदेव थोराट के साथ आंबेडकर के 1927 के महाड़ सत्याग्रह के बारे में बातचीत का एक वीडियो अपने 'एक्स' हैंडल पर साझा किया।

राहुल गांधी ने पोस्ट किया, 98 साल पहले शुरू हुई हिस्सेदारी की लड़ाई जारी है। 20 मार्च, 1927 को बाबासाहेब आंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह के जरिए जातिगत भेदभाव को सीधी चुनौती दी थी। यह केवल पानी के अधिकार की नहीं, बल्कि बराबरी और सम्मान की लड़ाई थी। उन्होंने कहा, जाने–माने शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, दलित विषयों के जानकार और तेलंगाना में जातिगत सर्वेक्षण

पर बनी अध्ययन समिति के सदस्य प्रोफेसर थोराट से इस सत्याग्रह के महत्व पर चर्चा की। इस दौरान दलितों की शासन, शिक्षा, नौकरशाही और संसाधनों तक पहुंच के लिए अब भी जारी संघर्ष पर भी हमने विस्तार से बातचीत की।

गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना इसी असमानता की सच्चाई को सामने लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जबकि इसके विरोधी इस सच्चाई को बाहर आने देना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा, बाबासाहेब का सपना आज भी अधूरा है। उनकी लड़ाई सिर्फ अतीत की नहीं, आज की भी लड़ाई है। हम इसे पूरी ताकत से लड़ेंगे।

सक्षम महिलाओं को नहीं मांगना चाहिए गुजारा भत्ता, दिल्ली हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी

■ बीएनटी न्यूज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि कानून आलस्य को बढ़ावा नहीं देता है और कहा कि कमाने की क्षमता वाली योग्य महिलाओं को अपने पतियों से अंतरिम भरण–पोषण का दावा नहीं करना चाहिए। न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने 19 मार्च को कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 (पत्नी, बच्चों और माता–पिता के भरण–पोषण का आदेश) में पति–पत्नी के बीच समानता बनाए रखने और पत्न ी, बच्चों और माता–पिता को सुरक्षा प्रदान करने का विधायी इरादा है, लेकिन यह आलस्य को बढ़ावा नहीं देता है।

इसलिए, इस आदेश ने एक महिला की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपने अलग हुए पति से अंतरिम भरण–पोषण देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि एक सुशिक्षित पत्नी, जिसके पास उपयुक्त लाभकारी नौकरी का अनुभव हो, को केवल अपने पति से भरण–पोषण पाने के लिए निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। इसलिए, वर्तमान मामले में अंतरिम भरण–पोषण को हतोत्साहित किया जा रहा है क्योंकि यह न्यायालय याचिकाकर्ता में कमाने और अपनी शिक्षा का लाभ उठाने की क्षमता देख सकता है। हालांकि, अदालत ने उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि उसके पास व्यापक अनुभव है और वह अन्य अशिक्षित महिलाओं के विपरीत दुनियावी मामलों से वाकिफ है, जो बुनियादी जीविका के लिए पूरी तरह से अपने पति पर निर्भर हैं। इस जोड़े ने दिसंबर 2019 में शादी की और सिंगापुर चले गए।

इफ्तार पार्टी में शामिल हुईं सोनिया गांधी

■ **बीएनटी न्यूज**

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) द्वारा आयोजित इफ्तार में शामिल हुए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) द्वारा आयोजित इफ्तार में शामिल हुए। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) द्वारा आयोजित इफ्तार में शामिल होने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हमारी सहयोगी है और संसद के ऊपरी और निचले सदन में उनकी बहुत मजबूत उपस्थिति है।

शशि थरूर ने कहा कि उनके वरिष्ठ नेता केरल और राष्ट्रीय IUML प्रतिष्ठान से आए हैं। हम इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहां आकर प्रसन्न हैं और IUML को रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। सभी को रमजान मुबारक हो। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) द्वारा आयोजित इफ्तार में भाग लेने पर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि मुझे खुशी है कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मैं उनके साथ जश्न मनाकर खुश हूं।

राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने कहा कि मैं एक बहुत ही खुशहाल और शांतिपूर्ण रमजान की कामना करती हूं। हम सभी को हर त्योहार का आनंद लेना चाहिए। कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने कहा कि रमजान एक पवित्र महीना है और आज का दिन बहुत बढ़िया है क्योंकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने एक शानदार इफ़्तार का आयोजन किया है जिसमें सभी पार्टियों के लोग आए हैं।

इफ़्तार शांति और प्रेम के बारे में है। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि आज IUML की ओर से यह इफ्तार पार्टी आयोजित की जा रही है। मैं उनकी पार्टी के लोगों और आज यहां मौजूद सभी लोगों को रमजान की मुबारकबाद देता हूं और सभी से अपील करता हूं कि वे देश में अमन, चैन और खुशहाली के लिए दुआ करें।

मोदी की विदेश यात्राओं पर तीन सालों में करीब 259 करोड़ रुपये का खर्च

■ **बीएनटी न्यूज**

पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं में बीते तीन सालों में करीब 259 करोड़ रुपये का खर्च आया है। यह जानकारी सरकार की तरफ से राज्यसभा में दी गई है। बीते तीन सालों के दिए ब्योरे के अनुसार पीएम मोदी ने कुल 38 यात्राएं की हैं। इनमें अमेरिका, जापान समेत कई देश शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की तरफ से इस संबंध में सवाल पूछा गया था।

कांग्रेस सांसद का सवाल था कि बीते तीन सालों में भारतीय दूतावासों ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं की व्यवस्था में कितना खर्च किया। साथ ही होटल, ट्रांसपोर्ट समेत अलग-अलग खर्चों की जानकारी मांगी गई।विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा की तरफ से इस संबंध में जवाब दिया गया था। उन्होंने ब्योरा दिया है कि पीएम मोदी ने साल 2022 में 8 देश, 2023 में 10 और 2024 में 16 देशों की यात्रा की है। इस दौरान उन्होंने 34 देशों की यात्रा की। ऐसे भी कई देश रहे, जहां वह एक से ज्यादा बार गए थे। 2022 में पीएम मोदी मई में जर्मनी, मई में डेनमार्क, मई में फ्रांस, मई में नेपाल, मई में जापान, जून में संयुक्त अरब अमीरात, जून में जर्मनी, सितंबर में जापान, सितंबर में उज्बेकिस्तान, नवंबर में इंडोनेशिया गए थे।

2023 में वह नवंबर मई में पपुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जून में अमेरिका, मिस्र, जुलाई में फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, अगस्त में दक्षिण अफ्रीका, ग्रीस, सितंबर में इंडोनेशिया, नवंब-दिसंबर में संयुक्त अरब अमीरात गए थे। 2024 में उन्होंने फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मार्च में भूटान, जून में इटली, जुलाई में ऑस्ट्रिया, रूस, अगस्त में पोलैंड, यूक्रेन, सितंबर में ब्रूनेई, अमेरिका, सिंगापुर, अक्तूबर में लाओ पीडीआर, रूस, नवंबर में नाइजीरिया, ब्राजील, गुयाना, दिसंबर में कुवैत की यात्रा की थी।

जब मनमोहन सिंह थे पीएम सरकार ने 2014 से पहले हुईं पीएम की तीन सालों की यात्रा का भी ब्योरा दिया गया है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2011 में हुई अमेरिका यात्रा पर 10 करोड़ 74 लाख 27 हजार 363 रुपये खर्च हुए थे। वहीं, 2013 में रूस की यात्रा पर 9 करोड़ 95 लाख 76 हजार 890 रुपये का खर्च आया था। 2011 में फ्रांस की यात्रा में 8 करोड़ 33 लाख 49 हजार 463 रुपये और 2013 में हुई जर्मनी यात्रा पर 6 करोड़ 2 लाख 23 हजार 484 रुपये खर्च हुए थे।

डीके शिवकुमार का बयान कानूनी रूप से सही, भाजपा को सिर्फ तुष्टिकरण दिखता है

■ **बीएनटी न्यूज**

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बीएनटी न्यूज से बात करते हुए कई मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के 'संविधान बदल रहा है' वाले बयान पर टिप्पणी की।

दरअसल, डीके शिवकुमार ने संविधान में बदलाव की बात की थी, जिस पर भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक बार फिर से मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। हरीश रावत ने इसे नकारते हुए कहा कि भाजपा को हर बात में तुष्टिकरण ही नजर आता है। उनकी सोच सीमित है और शिवकुमार का बयान कानूनी रूप से मान्य है। अगर कुछ गलत होता है, तो अदालत में उसका हल निकाला जाएगा। भाजपा का मकसद केवल समाज में दुर्भावना फैलाना है, वह ऐसे मुद्दों का दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रही है।

दिल्ली हाईकोर्ट के जज मामले पर रावत ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यायपालिका इस मामले की पूरी तह तक जाएगी और उचित कदम उठाएगी। न्यायपालिका पर हमारा विश्वास अडिग है और हम अपने मान-सम्मान के प्रति उनकी समझ पर भरोसा करते हैं।

कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ शिवसेना के बयान पर भी हरीश रावत ने टिप्पणी की। शिवसेना के एक गुट ने कामरा से माफी मांगने को कहा था, नहीं तो चेतावनी दी थी कि उन्हें मुंबई में घूमने नहीं दिया जाएगा। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के शासन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति व्यंग्य करता है, तो वह उस समय की स्थितियों का प्रतिबिंब होता है। कार्टूनिस्ट आरके लक्ष्मण के चित्रों की तरह, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी को दंड देने की धमकी देकर उसकी आवाज दबा दें।

सपा सांसद रामजीलाल के विवादित बयान को लेकर पूछे जाने पर रावत ने कहा कि रामजीलाल को इतिहास का सही अध्ययन करना चाहिए। राणा सांगा वीरता के प्रतीक थे और उन्होंने बाबर से संघर्ष करते हुए शहादत दी थी। ऐसे वीरों के बारे में ऐसी टिप्पणी करना बेहद निंदनीय है।

राजद प्रमुख लालू यादव की लोगों से तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की अपील

■ **बीएनटी न्यूज**

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के जमुनिया गांव में पूर्व विधायक यमुना यादव के पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने लोगों से तेजस्वी यादव को राज्य का मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। लालू यादव ने लोगों से अपील करते हुए कहा, 'बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाइए और उन्हें मुख्यमंत्री बनाइए।' उन्होंने माई-बहिन मान योजना सहित सभी वादों को पूरा करने का भी भरोसा दिया।

इससे पहले, मोतिहारी पहुंचने पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को समर्थन दें। लालू यादव ने विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की घोषणा का समर्थन करते हुए कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए माई-बहिन मान योजना जैसी नई योजनाएं लाई जाएंगी। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। उन्होंने उपस्थित लोगों को यह भी भरोसा दिया कि तेजस्वी की सरकार बनने पर विधायक मनोज यादव को मंत्री बनाया जाएगा।

लालू ने याद करते हुए बताया कि मनोज के पिता यमुना यादव ने उनके मुख्यमंत्री काल में कई योजनाओं की मांग की थी और सभी मांगों को पूरा करने का काम किया गया था।

कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने जमकर राजद और लालू यादव के पक्ष में नारे लगाए। उन्होंने तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए कहा कि युवा ही प्रदेश के भविष्य हैं। राजद सुप्रीमो ने लोगों से अपील की कि वे जागरूक हों और इस 'जनविरोधी सरकार' को हटाएं। पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने स्व. यमुना यादव को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके बेटे और वर्तमान विधायक मनोज यादव को फिर से विजयी बनाने के लिए अभी से लग जाएं। इस मौके पर बड़ी संख्या में राजद के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे।

समाजवाद नहीं, बल्कि पुत्र मोह

दिलीप जायसवाल ने बीएनटी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि यह बयान एक पिता के पुत्र मोह का परिणाम है। यह बिल्कुल गलत है कि एक पिता अपने बेटे के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। यह जनता के बीच गलत संदेश देता है। एक नेता जो समाजवाद का दावा करता है, उसे इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए।

उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि अगर राजद की सरकार बनने का सपना पूरा होता है, तो यादव समाज में कोई दूसरा नेता मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? दिलीप जायसवाल ने लालू यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि समाजवाद का कोई वास्तविक अर्थ है तो उसे सिर्फ अपने बेटे तक सीमित नहीं करना चाहिए। यह समाजवाद नहीं, बल्कि पुत्र मोह है। यह समाजवाद का अपमान है।

■ **बीएनटी न्यूज**

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर अपने देश के संविधान को किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देंगे और जरूरत पड़ने पर बसपा इसके खिलाफ संघर्ष के लिए भी तैयार है। इसके साथ ही मायावती ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के 8 साल को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार जनता की उम्मीद के हिसाब से खरी नहीं उतरी है। बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार एक के बाद एक तीन पोस्ट किए।

बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी पार्टी को उनके राजनैतिक स्वार्थ में खासकर आरक्षण को लेकर अपने देश के संविधान को किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देंगे तथा जरूरत पड़ने पर इसके विरुद्ध बीएसपी संघर्ष के लिए भी तैयार है।'

उन्होंने आगे लिखा, 'साथ ही, यूपी में बीजेपी सरकार का 8 वर्षों का शासनकाल, जनता की उम्मीद के हिसाब से पूरे तौर से खरा नहीं उतरा है। कानून-व्यवस्था के मामले में तो स्थिति काफी ज्यादा खराब रही है, जिससे जनता काफी दुखी है। इस ओर सरकार जरूर ध्यान दे।' मायावती ने मनुस्मृति को लेकर एक्स पोस्ट में लिखा, 'मनुस्मृति का बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर को पूरा ज्ञान था। उनकी अनुयायी और बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इसका पूरा ज्ञान है। तभी इस व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाकर यहां दुखी और पीड़ितों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बीएसपी की स्थापना की गई है, यह भी सर्वविदित है।'

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य निर्णायक दौर में : राष्ट्रपति मुर्मू

■ **बीएनटी न्यूज**

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह में शामिल हुईं। उन्होंने अपने संबोधन की शुरूआत 'जय जोहार' के साथ की। राष्ट्रपति ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में लोकतंत्र के इस उत्सव में आप सबके साथ शामिल होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के असाधारण मार्गदर्शन में संपन्न हुई थी।

उन्होंने कहा कि इस अवसर पर हम सब उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उनके सम्मान में सादर नमन करते हैं। आप सबके बीच आकर मुझे ओडिशा विधानसभा में विधायक के रूप में अपने समय की यादें ताजा हो गई हैं। मैं अपने अनुभव से यह कह सकती हूं कि विधायक की जिम्मेदारी निभाना, जन-सेवा की भावना से प्रेरित व्यक्ति के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है। विधानसभा, राज्य के निवासियों की आकांक्षाओं को व्यक्त करती है और उन्हें कार्यरूप देती है। विधानसभा राज्य की संस्कृति से प्रभावित भी होती है और उसे दिशा भी प्रदान करती है।

रजत जयंती वर्ष समारोह के तहत विधानसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोग विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ को उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त करने के प्रयास में आप सब शीघ्र ही सफलता प्राप्त करेंगे और राज्य के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ेंगे।

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा ने लोकतांत्रिक परंपराओं के सर्वोच्च मानदंड स्थापित किए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सदन की कार्यवाही के दौरान वेल में आने वाले सदस्यों को स्वतः निलंबित करने का असाधारण नियम बनाया है और इसका पालन किया है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि पिछले 25 वर्षों के दौरान यहां के विधानसभा में कभी भी मार्शल का उपयोग नहीं करना पड़ा। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने न केवल देश के लिए बल्कि विश्व की सभी लोकतांत्रिक प्रणालियों के समक्ष उत्कृष्ट संसदीय आचरण का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है।

राष्ट्रपति ने महिला विधायकों से सभी महिलाओं का समर्थन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जब वे विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं को प्रोत्साहित करेंगी, तब सभी का ध्यान उन महिलाओं की ओर जाएगा और उनके विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। चाहे वे शिक्षक हों या अधिकारी, समाजसेवी हों या उद्यमी, वैज्ञानिक हों या कलाकार, मजदूर हों या किसान, अक्सर हमारी बहनें दिन-प्रतिदिन की घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए और कठिन संघर्ष करते हुए बाहरी दुनिया में अपना स्थान बनाती हैं। जब सभी महिलाएं एक-दूसरे को सशक्त बनाएंगी, तो हमारा समाज और अधिक मजबूत और संवेदनशील बनेगा।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास की असीम संभावनाएं हैं। सीमेंट, खनिज उद्योग, इस्पात, एल्युमीनियम और बिजली उत्पादन जैसे क्षेत्रों में विकास के भरपूर अवसर हैं। यह खूबसूरत राज्य हरे-भरे जंगलों, झरनों और अन्य प्राकृतिक सौगातों से भरपूर है। उन्होंने राज्य के नीति निमार्ताओं से विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को आधुनिक विकास की यात्रा से जोड़ने की जिम्मेदारी भी नीति निमार्ताओं की है।

चुनाव में जनता एनडीए को थमाएगी झुनझुना : कन्हैया कुमार

■ **बीएनटी न्यूज**

कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार इन दिनों बिहार में 'पलायन रोको, नौकरी दो' नारों के साथ पदयात्रा कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कन्हैया की यह यात्रा अहम मानी जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पदयात्रा दरभंगा पहुंची।

यहां उन्होंने युवाओं से संवाद किया और मीडिया से बातचीत की। शहर में पदयात्रा के दौरान जगह-जगह लोगों ने मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग, चादर और फूलों की माला से स्वागत किया।

कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर थाली बजाने से कोरोना जैसी महामारी भाग जाती, तो बेरोजगारी भी तो महामारी है, यह भी थाली बजाने से भाग जाती। हम शाम तक थाली पीटते रहे, लेकिन बेरोजगारी भागी नहीं। वास्तव में थाली बजाने से कोरोना भी नहीं भागी थी। उन्होंने कहा कि आज हम दरभंगा में झुनझुना इसलिए बजा रहे थे कि सरकार हमारी पहचान के आधार पर हमें लड़ाकर हमारे हाथों में नफरत का झुनझुना थमा देती है। रोजगार के नाम पर उनके बच्चे बीसीसीआई में नौकरी पा गए, देश से लेकर विदेश तक में नौकरी कर रहे हैं। लेकिन, हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिलीं।

कांग्रेस नेता ने कहा, 'वोट हम लोग देते हैं, तभी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं। आप रोजगार के नाम पर हमारे हाथ में झुनझुना थमाए हैं, तो हम आपके नाम पर आपके हाथ में झुनझुना थमा देंगे। इसके बाद आपके बच्चों के हाथ में खुद-ब-खुद झुनझुना ट्रांसफर हो जाएगा।'

'घर में नकदी': पारदर्शिता की जरूरत, न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रणाली बेकार : हरीश साल्वे

■ **बीएनटी न्यूज**

दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश से जुड़े कथित 'घर पर नकदी' प्रकरण की पृष्ठभूमि में, भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए न्यायिक नियुक्ति की प्रणाली में व्यापक बदलाव का आ'ान किया।

उन्होंने यह भी कहा कि न्यायपालिका के खिलाफ लगाए गए लांछन और अपुष्ट आरोप जनता की आस्था को हिला देते हैं और अंततः लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े प्रकरण को चेतावनी बताते हुए उन्होंने कहा कि आज हमारे पास न्यायिक नियुक्ति की जो प्रणाली है, वह निष्क्रिय है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पिछले सप्ताह जब अग्निशमन विभाग की एक गाड़ी न्यायमूर्ति वर्मा के आवास पर आग बुझाने गई थी, तो वहां भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी।

उन्होंने ताजा विवाद को बदलाव की याद दिलाते हुए कहा, 'हमें चर्चा फिर से शुरू करने की जरूरत है... यह अस्तित्व का संकट है। आपको इस संस्था को बचाना होगा।'

साल्वे ने विधानमंडल, विशेषकर संसद सदस्यों से, न्यायिक नियुक्तियों के लिए एक परिष्कृत और अधिक पारदर्शी प्रणाली के लिए सामूहिक रूप से सुझाव देने का आ'ान किया।

उन्होंने कहा, 'मैं देखता हूं कि जिन 500 लोगों को हमने वोट देकर सत्ता में भेजा है, उन्हें अपने राजनीतिक मतभेदों को एक तरफ रखना होगा। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें उन्हें एक साथ बैठकर विचार-विमर्श करना होगा, संसद में भेजे गए 500 लोगों के सामूहिक विवेक से एक ढांचा तैयार करना होगा।'

उन्होंने न्यायपालिका के खिलाफ लगाए गए आरोपों की भी आलोचना की और कहा कि इससे लोगों की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंच रही है।

उन्होंने अपुष्ट रिपोर्टिंग के खिलाफ सावधानी बरतने का संकेत देते हुए कहा, 'हम बहुत ही अशांत और अलग समय में रह रहे हैं। आज, यह 1960, 70 और 80 का दशक नहीं है, जब खबरें सामने आने में कई हफ्ते और कई हफ्ते लग जाते थे। आज, यह सोशल मीडिया का युग है। कोई घटना होती है। इसे वीडियो में कैद कर लिया जाता है और 15 मिनट में जारी कर दिया जाता है। दुनिया जानती है कि 15 मिनट पहले आपके घर में क्या हुआ था।'

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि लोकतंत्र में न्यायपालिका एक बहुत ही सम्मानित संस्था है। क्या हम बिना कार्यशील न्यायपालिका के रह सकते हैं? हम नहीं रह सकते। और अगर हम बिना कार्यशील न्यायपालिका के नहीं रह सकते, तो हमें इसे मजबूत करना होगा।'

1993 में बनाई गई वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक समूह शामिल है, जो उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर निर्णय लेता है।

इन चिंताओं को दूर करने के प्रयास में, सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) का प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य कॉलेजियम प्रणाली को गैर-न्यायिक सदस्यों वाले निकाय से बदलना था, लेकिन अंततः 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया।

पीएम मोदी ने महाकुंभ को बताया महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़, नदी उत्सवों को बढ़ावा देने की अपील

■ बीएनटी न्यूज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संपन्न महाकुंभ को 1857 के आंदोलत और महात्मा गांधी के दांडी मार्च की तरह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि सबके प्रयास से यह संभव हो सका।

संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में महाकुंभ पर एक बयान में प्रधानमंत्री ने इसे देश की एकता, संस्कृति और सामर्थ्य का जीवंत उदाहरण बताते हुए कहा कि इस आयोजन ने पूरे विश्व को भारत की ताकत दिखाई। उन्होंने देशवासियों, उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर प्रयागराज के लोगों और सभी कर्मयोगियों को इस सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया।

पीएम मोदी ने कहा, 'मैं कोटि-कोटि देशवासियों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से महाकुंभ इतना भव्य हुआ। गंगा को धरती पर लाने के लिए भागीरथ ने जो प्रयास किया था, वैसा ही महाप्रयास इस आयोजन में दिखा। मैंने लाल किले से 'सबका प्रयास' की बात कही थी, और महाकुंभ में यह साकार हुआ। पूरे विश्व ने भारत के विशाल स्वरूप को देखा।'

उन्होंने इसे जनता की श्रद्धा और संकल्प का परिणाम बताया।

प्रधानमंत्री ने महाकुंभ को राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बताते हुए कहा कि इसने देश के सामर्थ्य पर उठने वाली शंकाओं को खत्म कर दिया।

उन्होंने पिछले साल हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जिक्र करते हुए कहा, 'राम मंदिर के बाद महाकुंभ ने यह साबित किया कि भारत अगले एक हजार साल के लिए तैयार है। यह हमारे इतिहास में एक ऐसा मोड़ है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा।'

उन्होंने स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दांडी मार्च जैसे ऐतिहासिक पलों का उल्लेख करते हुए महाकुंभ को भी उसी कड़ी का हिस्सा बताया।

पीएम ने कहा कि महाकुंभ का उत्साह डेढ़ महीने तक दिखा। लोग सुविधाओं और चिंताओं से ऊपर उठकर इसमें शामिल हुए।

उन्होंने अपने हाल के मॉरीशस दौरे का जिक्र किया, जहां वे त्रिवेणी संगम का पवित्र जल लेकर गए थे। उन्होंने कहा, 'जब गंगाजल को वहां अर्पित किया गया, तो श्रद्धा का माहौल देखते बनता था। यह दिखाता है कि हमारी संस्कृति को अपनाने की भावना कितनी मजबूत हो रही है।'

उन्होंने जोर देकर कहा कि आज की युवा पीढ़ी अपनी परंपराओं को गर्व के साथ अपना रही है, जो देश की बड़ी ताकत है।

पीएम मोदी ने महाकुंभ को एकता का सबसे बड़ा उदाहरण बताया। उन्होंने कहा, 'देशभर से लोग प्रयागराज आए। अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग-अलग राज्यों के लोग संगम तट पर जुटे। वहां छोटे-बड़े का कोई भेद नहीं था। 'मैं' नहीं, 'हम' की भावना दिखी। यह एकता आज के दौर में हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, जब दुनिया में बिखराव बढ़ रहा है।' उन्होंने कहा कि महाकुंभ से देश को कई प्रेरणाएं मिली हैं, जिनमें एकता के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण भी शामिल है।

प्रधानमंत्री ने नदियों के संकट पर चिंता जताते हुए कहा, 'हमारे देश में कई नदियां हैं, लेकिन कुछ संकट में हैं। हमें नदी उत्सवों को बढ़ावा देना होगा ताकि आज की पीढ़ी पानी के महत्व को समझे।'

उन्होंने महाकुंभ को सामाजिक भाईचारे और विरासत के गर्व का प्रतीक बताते हुए कहा कि जब समाज अपनी परंपराओं से जुड़ता है, तो ऐसी भव्य तस्वीरें सामने आती हैं, जैसी प्रयागराज में दिखीं।

मोदी ने कहा, 'यह आयोजन हमें नए संकल्पों की ओर ले जाता है। यह हमारी ताकत, एकता और संस्कृति का उत्सव था, जिसे दुनिया ने देखा।'

प्रधानमंत्री ने जिनकी मृत्यु हुई उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद परिसर में प्रधानमंत्री मोदी के महाकुंभ पर दिए गए वक्तव्य पर कहा, 'मैं प्रधानमंत्री मोदी की बात का समर्थन करना चाहता था। कुंभ हमारी परंपरा है, संस्कृति है, इतिहास है। एक शिकायत थी कि प्रधानमंत्री ने, जिनकी मृत्यु हुई, उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी। जो युवा महाकुंभ में गए उन्हें प्रधानमंत्री से रोजगार चाहिए और प्रधानमंत्री को उसपर भी बोलना चाहिए था। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष को तो बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था लेकिन नहीं देते हैं, यह न्यू इंडिया है।'

सरकार मनरेगा योजना को कमजोर कर रही है

■ बीएनटी न्यूज

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने राज्यसभा में मनरेगा योजना का विषय उठाया। उन्होंने शून्यकाल में बोलते हुए कहा कि मनरेगा योजना को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने इस पर अपनी चिंता जाहिर की।

सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर इस योजना को व्यवस्थित रूप से कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संघीय बजट में इस योजना के लिए कम धन आवंटित किया गया है।

सोनिया गांधी ने राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए कहा, 'मैं आपका ध्यान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत रोजगार के अधिकार की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। इस योजना को यूपीए सरकार के कार्यकाल में डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लागू किया गया था। यह ऐतिहासिक कानून लाखों ग्रामीण गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा चक्र साबित हुआ है।'

मनरेगा योजना की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए सोनिया गांधी ने

कहा, 'मुझे इस बात की गहरी चिंता है कि वर्तमान भाजपा सरकार ने इस योजना को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया है और बजट आवंटन 86,000 करोड़ रुपए पर स्थिर रहा है। वास्तविकता में आवंटित बजट में 4,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। इसके अलावा, अनुमान है कि लगभग 20 प्रतिशत आवंटित राशि पिछले सालों के बकाया भुगतान को निपटाने में खर्च हो जाएगी।'

सदन में आगे बोलते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि इस योजना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि आधार-आधारित भुगतान प्रणाली और राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली की अनिवार्यता। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मनरेगा के तहत मिलने वाले वेतन भुगतान में लगातार देरी हो रही है और मुद्रास्फीति के हिसाब से लोगों को मिलने वाली मजदूरी दर अपर्याप्त है।

सोनिया गांधी ने इन समस्याओं के समाधान के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से कुछ मांगें सदन के समक्ष रखीं। इन मांगों में कहा गया है कि मनरेगा के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किए जाएं, योजना को बनाए रखने और विस्तार करने के लिए पर्याप्त धन दिया जाए। न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की जाए। दैनिक न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये हो। समय पर वेतन वितरण हो। सोनिया गांधी ने मनरेगा स्कीम के तहत लागू कई अनिवार्य आवश्यकताओं को हटाने की भी बात कही।

उन्होंने कहा कि आधार-आधारित भुगतान प्रणाली और राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। गारंटीकृत कार्य दिवसों की वृद्धि की जाए। प्रत्येक वर्ष के लिए 100 से 150 कार्य दिवसों की गारंटी दी जाए। सोनिया गांधी ने कहा कि ये उपाय मनरेगा के तहत गरिमापूर्ण रोजगार और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं।

तेलंगाना ने ओबीसी समुदाय के लिए 42 फीसदी आरक्षण की घोषणा की

■ बीएनटी न्यूज

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ओबीसी समुदाय के लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। सीएम रेड्डी ने शिक्षा, नौकरी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में ओबीसी आबादी के लिए 42 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने की घोषणा की।

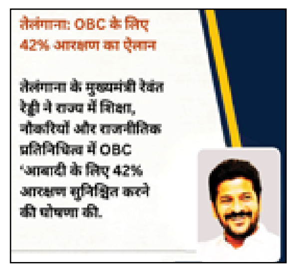

सीएम रेड्डी ने इस ऐतिहासिक कदम को लेकर अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने इसे भारतीय स्वतंत्रता के बाद से पिछड़े वर्गों की सबसे लंबी बहुप्रतीक्षित मांग बताया।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'तेलंगाना को गर्व है कि वह भारत में सामाजिक क्रांति का नेतृत्व कर रहा है।

यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि हम भारतीय स्वतंत्रता के बाद से पिछड़े वर्गों की सबसे लंबी मांग को पूरा कर रहे हैं। हमारे भाई-बहन जो पिछड़े वर्गों से आते हैं, उनकी यह मांग थी कि उन्हें आधिकारिक जनगणना में गिना और पहचाना जाए और आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'आज तेलंगाना विधानसभा के नेता के रूप में और मुख्यमंत्री के रूप में, मैं यह संजीदगी से घोषणा करता हूं कि हमारे लोगों की कड़ी मेहनत और वैज्ञानिक तरीके से की गई सर्वेक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि तेलंगाना में ओबीसी आबादी 56.36 प्रतिशत है। हम अब यह सुनिश्चित करने का संकल्प लेते हैं कि इस समूह को शिक्षा, रोजगार, और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सभी क्षेत्रों में 42 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।'

रेवंत रेड्डी ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह एक बड़ा कदम है, जो राज्य के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में बदलाव लाएगा। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे इस ऐतिहासिक कदम का समर्थन करें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।

सरकार के इस फैसले के बाद तेलंगाना के ओबीसी समुदाय को विभिन्न सरकारी सेवाओं और अवसरों में समान भागीदारी मिलेगी। इस आरक्षण की घोषणा से राज्य में सामाजिक समानता और समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा, और पिछड़े वर्गों के विकास में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की यह घोषणा आने वाले समय में तेलंगाना के सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। इससे राज्य में ओबीसी समुदाय के लिए बेहतर अवसर उत्पन्न हो सकते हैं।

तेलंगाना में ओबीसी को 42 प्रतिशत आरक्षण का राहुल-प्रियंका गांधी ने किया समर्थन

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का वादा पूरा कर दिया है। राज्य में वैज्ञानिक तरीके से हुई जातिगत गिनती से मिली ओबीसी समुदाय की वास्तविक संख्या स्वीकार की गई और शिक्षा, रोजगार और राजनीति में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में 42% आरक्षण का बिल पारित किया गया है। सामाजिक न्याय की दिशा में यह वाकई एक क्रांतिकारी कदम है, जिसके द्वारा राज्य में आरक्षण पर से 50% की दीवार भी गिरा दी गई है।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा, 'तेलंगाना के मेरे भाइयों-बहनों, आपको बहुत-बहुत बधाई। आपकी कांग्रेस सरकार ने आपसे किया एक और वादा पूरा कर दिया है। पिछड़ा वर्ग के हमारे लोगों को अब 42% आरक्षण मिल सकेगा। ये वादा हमने विधानसभा चुनाव में आपसे किया था, अब इसे पूरा कर दिया है। ये सामाजिक न्याय के लिए उठाया गया बेहद जरूरी कदम है, जो आपको सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा। हम हमेशा आपके साथ हैं, आपके लिए हैं। जय हिंद, जय तेलंगाना, जय कांग्रेस।'

राज्यसभा में आतंकवाद पर गरजे अमित शाह

हमले के बाद हमने पाकिस्तान में घुसकर जवाब दिया

■ बीएनटी न्यूज

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा को संबोधित किया। उन्होंने देश की आतंरिक सुरक्षा, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से निपटने की रणनीति, विकास कार्य समेत अन्य मुद्दों का जिक्र किया। शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत हुई है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक साथ सभी समस्याओं पर वार किया।

गृह मंत्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद उरी और पुलवामा में हमले हुए। हालांकि, 10 दिनों के भीतर ही भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके मुंहतोड़ जवाब दिया। केवल दो देश, अमेरिका और इजरायल, अपनी सुरक्षा और सीमाओं के लिए खड़े होते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को भी इस सूची में शामिल कर लिया।

राज्यसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा, 'मैं अपने संविधान निमार्ताओं

को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अनुच्छेद 370 को अस्थायी बनाया और उसी अनुच्छेद के भीतर इसे हटाने का समाधान प्रदान किया। हालांकि, वोट बैंक की राजनीति ने इसे सुरक्षित रखा, लेकिन 5 अगस्त 2019 को, पीएम मोदी ने इसे हटाने का ऐतिहासिक कदम उठाया, जिससे कश्मीर के शेष भारत के साथ एकीकरण के एक नए युग की शुरूआत हुई।'

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर में आए दिन, पड़ोसी देश से आतंकवादी घुसकर बम धमाके करते थे। एक भी त्योहार ऐसा नहीं होता था, जो चिंता के बगैर मनाया जाता था, लेकिन केंद्र सरकार का रवैया लचीला होता था, बोलने में डर लगता था, चुप्पी साध जाते थे, वोट बैंक का डर था। पीएम मोदी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई।

अमित शाह ने कहा कि ये तीन नासूर थे- जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और उत्तर पूर्व का उग्रवाद। इन समस्याओं के कारण चार दशक में देश के करीब 92 हजार नागरिक मारे गए। इसके बावजूद इन समस्याओं के संपूर्ण उन्मूलन के लिए एक सुनियोजित प्रयास कभी नहीं हुआ था, जो नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद हुआ।

सदन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने सबसे पहले देश की आजादी के बाद, देश की आंतरिक सुरक्षा को और देश की सरहदों को सुरक्षित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले राज्य पुलिस और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के हजारों शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

उन्होंने कहा कि इनके बलिदान से ही देश आजादी के 76 साल पार कर विश्व में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मैं बलिदानियों के परिवारजनों को भी मनपूर्वक धन्यवाद करता हूं। उनके सर्वोच्च बलिदान को ये देश, ये सदन कभी भूला नहीं पाएगा।

अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद भारतीय युवाओं का आतंकवादियों से जुड़ाव लगभग खत्म हो गया है। 10 साल पहले आतंकवादियों का महिमामंडन आम बात थी और उनके जनाजे निकाले जाते थे, लेकिन अब जब आतंकवादी मारे जाते हैं तो उन्हें वहीं दफना दिया जाता है। आतंकवादियों के रिश्तेदार जो कभी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाते थे, उन्हें बेरहमी से सरकारी पदों से हटा दिया गया है, ताकि कड़ा संदेश दिया जा सके।

संसद को 'फ्रीबीज' पर विचार करने की आवश्यकता : उपराष्ट्रपति

■ बीएनटी न्यूज

उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का कहना है कि प्रलोभन तंत्रों पर, तुष्टिकरण पर, जिसे अक्सर 'फ्रीबीज' के रूप में जाना जाता है, सदन को विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि देश तभी प्रगति करता है जब पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) उपलब्ध हो।

राज्यसभा में उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया ऐसी हो गई है कि ये 'चुनावी प्रलोभन' बन गए हैं। इसके बाद सत्ता में आई सरकारों को इतनी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा कि वे अपनी सोच पर पुनर्विचार करना चाहती थीं। एक राष्ट्रीय नीति की अत्यंत आवश्यकता है ताकि सरकार के सभी निवेश किसी भी रूप में बड़े हित में उपयोग किए जाएं।

इससे पहले राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने सांसद निधि

को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये प्रति वर्ष किए जाने की मांग सदन में रखी थी। उन्होंने यह भी कहा कि सांसद निधि को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाए। उनका कहना था कि यदि यह संभव नहीं है तो फिर सांसद निधि के प्रावधान को ही खत्म कर दिया जाना चाहिए।

सपा सदस्य का कहना था कि मौजूदा सांसद निधि नाकाफी है, जिसके कारण जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में काम नहीं करवा पाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विधायकों को कुल मिलाकर सांसद से कहीं ज्यादा निधि मिलती है।

इस वक्तव्य के बाद सभापति ने 'फ्रीबीज' के मुद्दे पर सदन को विचार करने की आवश्यकता की बात कही।

सभापति ने कहा, 'हमारे संविधान में विधायिका, सांसदों, विधायकों के लिए प्रावधान किया गया था, लेकिन एक समान तंत्र नहीं था। इसलिए, आप देखेंगे कि कई राज्यों में विधानसभाएं सदस्यों को सांसदों की तुलना में अधिक भत्ते और वेतन देती हैं, और यहां तक कि पूर्व विधायकों की पेंशन में भी एक से 10 तक का अंतर है। यदि एक राज्य में किसी को एक रुपया मिलता है, तो दूसरे राज्य में पेंशन 10 गुना हो सकती है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें कानून के माध्यम से हल किया जा सकता है और इससे राजनेताओं, सरकार, कार्यपालिका को लाभ होगा और यह उच्च गुणवत्ता वाले निवेश को भी सुनिश्चित करेगा।'

उन्होंने कहा, 'यदि कृषि क्षेत्र जैसी आवश्यकताओं के लिए सब्सिडी की जरूरत है, तो इसे सीधे प्रदान किया जाना चाहिए, और यही विकसित देशों में प्रचलित है।

मैंने अमेरिकी प्रणाली की जांच की। अमेरिका में हमारे देश की तुलना में 20 प्रतिशत कृषि परिवार हैं, लेकिन वहां कृषि परिवार की औसत आय अमेरिका के सामान्य परिवार की आय से अधिक है। इसका कारण यह है कि वहां किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी सीधी, पारदर्शी और बिना किसी बिचौलिए के दी जाती है।'

राबड़ी देवी ने कहा- विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा

■ बीएनटी न्यूज

बिहार विधान परिषद में प्रदेश की कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सदन में ही मौजूद थे। विपक्ष इस दौरान वेल भी पहुंच गया और सरकार के विरोध में नारेबाजी की।

सदन के बाहर निकलने पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा, 'सदन के अंदर विपक्ष को सत्ता पक्ष के लोग बोलने नहीं देते हैं और सरकार भी नहीं मान रही है कि सदन के अंदर विपक्ष है। बिहार में इतनी घटनाएं घट रही हैं, हत्या हो रही है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रही है, रेप की घटनाएं घट रही हैं, दलित बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। सदन के अंदर जब हम लोग सवाल उठाते हैं तो सत्ता पक्ष द्वारा सवाल को उठाने नहीं दिया जाता है।'

उन्होंने कहा कि यह बिहार की जनता का सवाल है, जब जनता के सवाल नहीं उठाएंगे तो सदन में क्या उठाएंगे? जो घटनाएं हो रही हैं, उस पर चर्चा करें। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री कहने लगते हैं कि आप और आपके पति ने क्या किया है? सब हमने किया है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल करते हुए कहा कि 20 साल के शासनकाल में आपने अभी तक कितना जिला, कितना प्रखंड बनाया है, कितनी फैक्ट्रियां लगाई हैं? जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने थे तब तीन-चार फैक्ट्रियों यहां लगी। आज इसी कारखाने से रेल का चक्का देश और दुनिया में बनकर जाता है। इस दौरान उन्होंने मंत्री अशोक चौधरी को फालतू का आदमी बताया। राबड़ी देवी ने दावा करते हुए कहा कि हमलोग विपक्ष में रहकर सरकार का सहयोग कर रहे हैं। सरकार प्रश्नों का जवाब देने से भाग रही है।

राहुल गांधी ने लोकसभा में वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया

■ बीएनटी न्यूज

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में मतदाता सूची का मुद्दा उठाया और कहा कि कई राज्यों में वोटर लिस्ट पर सवाल उठे हैं, इसलिए संसद में चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की टिप्पणी पर हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती, यह तो सबको पता है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं तो ऐसे में अच्छा यही होगा कि संसद में इस विषय पर चर्चा हो।

गौरतलब है कि इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपनी एक टिप्पणी में सवाल करते हुए कहा था कि क्या वोटर लिस्ट सरकार बनाती है? इसी बात पर राहुल गांधी ने कहा, कि आपने सही कहा कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है? आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। लेकिन पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष शासित प्रत्येक राज्य में और खासकर महाराष्ट्र में साफ-साफ सवाल उठाए जा रहे हैं। पूरा विपक्ष मिलकर सिर्फ यही कह रहा कि वोटर लिस्ट पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। आप तो बनाते नहीं, ये हम मानते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट पर चर्चा तो हो जाए। इस प्रकार लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और कहा कि पूरा विपक्ष इस विषय पर चर्चा की मांग कर रहा है।

इसके साथ ही सदन में हंगामा जारी रहा। इस पर केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि वे सदन के अध्यक्ष को धमका रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि स्पीकर ने सभी सदस्यों को बराबर का समय दिया है और कभी भी किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया। स्पीकर ने स्पष्ट किया कि जो भी सदस्य सदन की मर्यादा का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर ने बताया कि उन्हें स्थगन प्रस्ताव के कई नोटिस मिले हैं, लेकिन किसी भी नोटिस को स्वीकार नहीं किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली जीत पर टीम इंडिया को बधाई दी।

इसके बाद डीएमके सांसद कनिमोझी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने तमिलनाडु के नेताओं को असभ्य बताया था। इस मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान ने सफाई देते हुए कहा कि यदि उनके शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो तो वे अपने शब्द वापस लेते हैं।

जो पाकिस्तान गए वो कायर: हम भागेंगे नहीं

■ बीएनटी न्यूज

एआईएमआईएम प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से होली के दौरान घर के अंदर रहने या खुद को ढकने के आह्वान के बाद एक तीखा संदेश दिया। उन्होंने समुदाय की ताकत का परिचय देते हुए कहा कि हम भागेंगे नहीं, हम कायर नहीं हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में चौक-ए-मस्जिद में एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप इतने डरे हुए हैं, तो आपको नमाज नहीं पढ़नी चाहिए और घर के अंदर रहना चाहिए। वे कहते हैं कि जैसे हमने अपनी मस्जिदों को ढक रखा है, वैसे ही हमें खुद को भी ढकना चाहिए, या फिर घर के अंदर रहना चाहिए। उनकी टिप्पणी कुछ अधिकारियों के बयानों के जवाब में आई है, जिसमें मुसलमानों को सलाह दी गई है कि अगर वे होली के

दौरान रंग नहीं लगाना चाहते हैं तो उन्हें घर के अंदर रहना चाहिए। उल्लेखनीय है कि 6 मार्च को उत्तर प्रदेश के संभल में सर्किल ऑफिसर अनुज चौधरी ने सुझाव दिया था कि जो लोग रंगों से असहज हैं, उन्हें घर के अंदर रहना चाहिए।

बाद में उनकी टिप्पणी का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समर्थन किया। इसके अलावा, होली के जश्न के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन के आदेश पर उत्तर प्रदेश की कई मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया था। ओवैसी ने कहा कि जो लोग पाकिस्तान चले गए, वे कायर थे। हम भागेंगे नहीं, हम कायर नहीं हैं। एक मुख्यमंत्री ने कहा कि जुम्मा की नमाज घर पर भी अदा की जा सकती है... वे कौन होते हैं जो हमें बताएं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं? इस साल, होली 14 मार्च को रमजान के दूसरे जुम्मा की नमाज (शुक्रवार की नमाज) के साथ हुई।

सुरक्षा बलों ने कई राज्यों में शांतिपूर्ण समारोह सुनिश्चित करने के लिए फ्लैग मार्च किया और चेकपॉइंट स्थापित किए।

यूपी के संभल में होली का त्योहार और जुमे की नमाज कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई। संभल की सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) वंदना मिश्रा ने समुदायों के बीच सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से मनाए गए त्योहारों ने "सद्भाव का एक मजबूत संदेश दिया।

बी टीम कांग्रेस में ही नहीं बल्कि बाकी पार्टियों में भी

■ बीएनटी न्यूज

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा गुजरात में दिए गए बी-टीम वाले बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ए टीम और बी टीम सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं, बल्कि बाकी पार्टियों में भी होती हैं।

संजय राउत ने कहा, कि जो लोग पार्टी में बैठकर अंदरखाने बीजेपी से मिले रहते हैं, वे सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं, बल्कि अन्य पार्टियों में भी मौजूद हैं। अगर राहुल गांधी ने ऐसे लोगों को बाहर करने का फैसला लिया है, तो मैं इसका स्वागत करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि कई लोग पार्टी में रहते हुए चुपचाप गद्दारी करते हैं, जिन्हें नमक हराम कहा जाता है। उन्होंने शिवसेना का उदाहरण देते हुए कहा, हमारे यहां एकनाथ शिंदे और उनके 40 लोग दो साल तक बीजेपी का एजेंडा चलाते रहे और फिर खुलेआम चले गए। उन्होंने कहा कि यह तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब हम अपने ही घर में आजाद हो गए हैं। संजय राउत ने कहा कि पार्टी के भीतर रहकर धोखा देना उसी तरह है जैसे कोई देश में रहते हुए किसी विदेशी ताकत के लिए काम करता है।

उन्होंने आरएसएस के प्रदीप कुरुलकर का उदाहरण दिया और कहा, कि जो डीआरडीओ में रहकर पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था, ऐसे लोग हर जगह होते हैं।

दरअसल गुजरात के अहमदाबाद में राहुल गांधी ने बड़ा बयान देते हुए कहा, मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं और मैं स्टेज से कहना चाहता हूं कि गुजरात को कांग्रेस पार्टी सही दिशा नहीं दिखा पा रही है।

उन्होंने कांग्रेस के भीतर दो तरह के लोगों का जिक्र करते हुए कहा, पहले वो जो जनता के साथ खड़े हैं और जिनके दिल में कांग्रेस की विचारधारा है। दूसरे वो जो जनता से कटे हुए हैं और जिनमें से आधे बीजेपी से मिले हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा, जब तक इन दोनों समूहों को अलग नहीं किया जाता, तब तक गुजरात की जनता कांग्रेस पर विश्वास नहीं कर सकती। गुजरात की जनता विकल्प चाहती है, बी-टीम नहीं चाहती। हमारी जिम्मेदारी इन दो ग्रुप्स को छांटने की है। हमारे पास बब्बर शेर हैं, लेकिन उनके पीछे से चेन लगी हुई है। सब पीछे से बंधे हुए हैं।

राहुल गांधी के इस बयान पर कांग्रेस ही नहीं अन्य पार्टियों में भी राजनीतिक चर्चा आम हो गई है। संजय राउत ने उनके बयान और फैसले को सही बताया है और कहा कि यह कदम कांग्रेस और अन्य पार्टियों में स्वच्छ राजनीति को बढ़ावा देने वाला साबित हो सकता है।

बजट सत्र : एमसीडी की बैठक में जोरदार हंगामा

भाजपा-आप पार्षदों के बीच धक्का-मुक्की

■ बीएनटी न्यूज

एमसीडी सदन में हंगामा, भाजपा और आप पार्षदों ने एक दूसरे के खिलाफ किया प्रदर्शन। कांग्रेस पार्षदों ने भी पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया, जिस पर लिखा था, 'संविधान हमारी पहचान है, संविधान की हत्या बंद करो'।

2024-25 और अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को अंतिम रूप देने के लिए सदन की कार्यवाही बुलाई गई थी। आप और भाजपा पार्षद मेज और कुर्सियों पर खड़े होकर एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस पार्षदों ने भी पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया, जिस पर लिखा था, 'संविधान हमारी पहचान है, संविधान की हत्या बंद करो।'

गौरतलब है कि सदन की बैठक 2024-25 और अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को अंतिम रूप देने के लिए बुलाई गई थी। पार्षदों ने एजेंडा पेपर फाड़ दिए, टेबल पर चढ़ गए और नारेबाजी की, जिससे सदन में अराजकता फैल गई। नारेबाजी के कारण कार्यवाही बाधित हुई और फटे हुए दस्तावेज हवा में लहराए गए, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। एमसीडी मेयर महेश खीची ने आरोप लगाया कि सत्र के दौरान भाजपा पार्षदों ने उनसे माइक छीन लिया।

उन्होंने कहा कि बजट सत्र का अंतिम दिन होने के बावजूद विपक्ष असहयोगी बना रहा और जानबूझकर कार्यवाही को बाधित किया।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खीची ने आरोप लगाया, "विपक्षी पार्षद मेज पर खड़े हो गए और सदन में चर्चा किए जाने वाले मुख्य बिंदुओं की सूची फाड़ दी।" उन्होंने दावा किया कि पिछले दो सालों से विपक्ष लगातार सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहा है और चर्चाओं को रोक रहा है। उन्होंने कहा, "इस बार भी उन्होंने यही किया।" खीची ने कहा, "दलित मेयर के साथ इस तरह का व्यवहार अनुचित है और संविधान के खिलाफ है।" इससे पहले एमसीडी ने दक्षिणी दिल्ली में सड़क विकास परियोजनाओं में तेजी लाने, चार गौशालाओं में मवेशियों को खिलाने के लिए लंबित भुगतान का निपटारा करने और बागवानी विभाग के लिए अतिरिक्त मानव संसाधन की नियुक्ति करने के प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी थी।

कांग्रेस का दावा, मतदाता पहचान-पत्र को आधार से जोड़ने का चुनाव आयोग का 'इरादा' मतदाता सूची पर उसके संदेह की स्वीकृति है

■ बीएनटी न्यूज

भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने कहा कि वह चुनावी फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) या मतदाता पहचान पत्रों को उन लोगों के आधार नंबर से जोड़ने की तैयारी कर रहा है, जिन्होंने स्वेच्छा से इन्हें उपलब्ध कराया है।

कांग्रेस ने चुनाव आयोग के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा, 'कांग्रेस पार्टी के संदिग्ध मतदाता सूचियों के आरोप को स्वीकार करते हुए, चुनाव आयोग आधार का उपयोग करके इसे साफ करना चाहता है।'

पार्टी के आठ सदस्यीय नेताओं और विशेषज्ञों के सशक्त कार्य समूह (ईगल) ने एक बयान में कहा, 'कांग्रेस पार्टी किसी भी व्यक्ति को वोट देने के अधिकार से वंचित न करने के लिए सुरक्षा उपायों के साथ एक रचनात्मक समाधान का स्वागत करती है।'

आपको बता दें कि इस निकाय की स्थापना कांग्रेस द्वारा भारत में चुनावों की सतर्क निगरानी बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखे।

ईगल ने आगे कहा कि ईपीआईसी वोटर-आईडी नंबरों को आधार नंबरों से जोड़ने का ईसीआई का फैसला 'कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा हमारे मतदाता सूचियों की संदिग्ध प्रकृति के बारे में लगाए गए आरोप की स्पष्ट स्वीकृति है, जैसा कि हाल ही में महाराष्ट्र 2024 विधानसभा चुनावों में देखा गया था।'

कांग्रेस के ईगल ने कहा, 'हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि वह महाराष्ट्र के 2024 विधानसभा और लोकसभा चुनावों की पूरी मतदाता सूची सार्वजनिक करे। कांग्रेस पार्टी का मुख्य आरोप यह है कि महाराष्ट्र के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच सिर्फ पांच महीनों में नए मतदाताओं के नामांकन में असामान्य वृद्धि हुई है, जिसका मतलब है कि या तो ये नकली, डुप्लीकेट या भूत मतदाता थे।'

इसमें आगे कहा गया है कि फर्जी या डुप्लीकेट मतदाता एक व्यक्ति के पास कई मतदाता पहचान-पत्र होने की समस्या है। 'चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए गए 'एक व्यक्ति के कई मतदाता पहचान-पत्र' की इस समस्या को स्वीकार किया है, जिसे आधार का उपयोग करके डी-डुप्लीकेशन के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है।'

बयान में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी ऐसे रचनात्मक समाधानों का समर्थन करती है, जो स्वच्छ मतदाता सूचियों को सुनिश्चित करें, जो कि 1949 में डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा दिए गए इस कथन के अनुरूप है कि 'लोकतंत्र में मतदाता सूचियां सबसे मौलिक हैं और चुनाव प्रक्रिया की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है।'

पार्टी ने आगे कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि आधार लिंकेज के कारण किसी भी वयस्क भारतीय नागरिक को वोट देने के अधिकार से वंचित न किया जाए।

मोदी सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई

■ बीएनटी न्यूज

पंजाब में किसान नेताओं जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर को हिरासत में लेने के मामले पर सियासत शुरू हो गई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने मान सरकार पर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ थी, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में बेवजह ही कूद गई।

किसान नेता टिकैत ने कहा, जो भी किसान गिरफ्तार किए गए हैं, उन्हें जल्द से जल्द छोड़ा जाए।

उन्होंने कहा, पंजाब सरकार के रास्ते का मामला है और वे इस मुद्दे पर किसानों के साथ बातचीत कर सकते थे। मोदी सरकार चाहती है कि किसान और पंजाब सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनी रहे। हमारी यही मांग है कि किसानों को रिहा किया जाए।

साथ ही पंजाब के सीएम को किसानों से बातचीत कर समन्वय स्थापित करना चाहिए। हमारी मांगें केंद्र सरकार के पास हैं और पंजाब को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तब पूरा आंदोलन पंजाब में चला जाएगा। आंदोलन के तहत छत्तीसगढ़ और ओडिशा में पहले से ही बैठकें हो रही हैं।

इस पूरे मामले में संयुक्त किसान मोर्चा फैसला लेगा और इस पर हम उनके साथ हैं। हरियाणा पुलिस ने किसानों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए लगे कांक्रीट के बैरिकेड्स हटाना शुरू किया। इसके पहले पंजाब पुलिस ने देर शाम धरना स्थल को खाली करा दिया और अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों को हटा दिया।

नई मुसीबत में फंसे सत्येंद्र जैन

एसीबी ने रिश्वत लेने के मामले में दर्ज की एफआईआर

■ बीएनटी न्यूज

दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व विधायक सत्येंद्र जैन के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी के लिए 571 करोड़ रुपये की सीसीटीवी परियोजना के संबंध में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया। संयुक्त पुलिस आयुक्त (सीपी) और एसीबी के प्रमुख मधुर वर्मा के अनुसार, 7 करोड़ रुपये की रिश्वत लेकर 16 करोड़ रुपये के परिसमाप्त हर्जाने को कथित तौर पर मनमाने ढंग से माफ कर दिया गया।

सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 ए के तहत पूर्व लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। एसीबी ने कहा, "सीसीटीवी लगाने में देरी के लिए 16 करोड़ रुपये का जुमार्ना माफ करने के लिए सत्येंद्र जैन को कथित तौर पर 7 करोड़ रुपये की रिश्वत देने की व्यवस्था की गई थी।" पिछली देरी के बावजूद, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (बीईएल) को परियोजना के तहत 1.4 लाख कैमरों के लिए अतिरिक्त ऑर्डर मिले।

कथित तौर पर रिश्वत का भुगतान ठेकेदारों के माध्यम से किया गया था, जिन्हें अतिरिक्त ऑर्डर से लाभ मिला। अधिकारियों के अनुसार, परियोजना कथित तौर पर "घटिया तरीके" से की गई थी, जिसमें परियोजना सौंपे जाने के समय भी कई कैमरे खराब थे। इसके अलावा, विभिन्न विक्रेताओं से जुड़ी रिश्वत को समायोजित करने के लिए भुगतान को कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया गया था। एसीबी ने पहले ही बीईएल के एक अधिकारी से पूछताछ की है, जिसने आरोपों की पुष्टि की है और विस्तृत शिकायत दी है।

आम आदमी पार्टी ने किया बड़ा संगठनात्मक बदलाव, नेताओं ने जताई खुशी

■ बीएनटी न्यूज

आम आदमी पार्टी (आप) ने 21 मार्च को महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का पार्टी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह अब तक इस पद पर कार्यरत रहे पूर्व मंत्री गोपाल राय की जगह लेंगे। गोपाल राय को पार्टी ने गुजरात का प्रभारी बनाया है। इसके अलावा, पार्टी ने पंजाब की जिम्मेदारी दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सौंप दी है, जो अब पंजाब के प्रभारी के रूप में कार्य करेंगे। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को पंजाब का उप-प्रभारी नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ का प्रभारी राज्यसभा सांसद संदीप पाठक को बनाया गया है, जबकि गोवा के प्रभारी पंकज गुप्ता होंगे। पंकज गुप्ता के साथ अंकुश नारंग, आभाष चंदेला और दीपक सिंगला को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है।

मनीष सिसोदिया ने अपने नए कार्यभार की जिम्मेदारी पर कहा, 'मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे पंजाब का प्रभारी नियुक्त किया है। पंजाब में पिछले कुछ वर्षों में हुई प्रगति ने इस राज्य के लोगों के दिलों में एक मजबूत स्थान बना लिया है। जब से भगवंत मान ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली, वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, और किसानों की भलाई के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। नौकरी के अवसरों से लेकर मोहल्ला क्लीनिकों तक, यहां विकास के कई अहम कदम उठाए गए हैं। पंजाब के गांवों में किसानों के लिए कई योजनाएं लागू की गईं, और इन कामों से पंजाब की तस्वीर बदल रही है। आने वाले समय में, हमारी प्राथमिकता होगी कि पंजाब हर नागरकि को यह विश्वास हो कि वे आम आदमी पार्टी का हिस्सा हैं और हमारी सरकार उनके लिए सही

काम कर रही है।'

इसके बाद, उन्होंने केंद्र और दिल्ली की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 'दिल्ली में सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता से जो वादे किए थे, उन्हें पूरा नहीं किया। उन्होंने वादा किया था कि दिल्ली की महिलाओं को ढाई हजार रुपये दिए जाएंगे, लेकिन वह वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा, उन्होंने होली के मौके पर गैस सिलेंडर मुफ्त देने की बात की थी, लेकिन वह भी सिर्फ एक वादा बनकर रह गया। इन सभी वादों के पूरा न होने से दिल्ली की जनता में असंतोष है।'

आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने अपनी नियुक्ति पर खुशी व्यक्त की और कहा, 'मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल और पार्टी की पॉलीटिकल अफेयर्स कमेटी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लायक समझा। दिल्ली में भाजपा के मुकाबले हमारे वोट शेयर में बहुत कम अंतर है। हम सभी लोगों के बीच यह विश्वास फैलाएंगे कि आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए हैं, उन्हें हम जरूर पूरा करेंगे। हम दिल्ली की जनता के अधिकारों की रक्षा करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे।'

सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर आरोप लगाया कि पार्टी ने चुनावों में लोगों से जो वादे किए थे, वह अब तक पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा, 'भाजपा ने जो वादे किए थे, वे सिर्फ चुनावी सस्ते हथकंडे थे। अब हमें यह देखना होगा कि क्या भाजपा उन वादों को पूरा करेगी या नहीं। दिल्ली में भाजपा ने जो वादे किए थे, उन पर जवाब देना पड़ेगा।'

पार्टी सांसद पाठक ने भी इस बदलाव के बारे में बात करते हुए कहा, 'पार्टी ने विस्तार की प्रक्रिया शुरू कर दी है और यह जारी रहेगी। हमारे बड़े नेताओं को जिम्मेदारियों के अनुसार राज्य-स्तरीय नेतृत्व दिया गया है। गुजरात में आम आदमी पार्टी को अच्छे वोट शेयर मिले थे और वहां के लोगों ने हमारे उम्मीदवारों को चुना था। गोपाल राय की संगठनात्मक क्षमता को ध्यान में रखते हुए उन्हें गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। पंजाब में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की नियुक्ति से हम वहां के विकास को गति देंगे।'

संदीप पाठक ने यह भी बताया कि उनकी जिम्मेदारी अब पहले से बढ़ी है। वे अब राष्ट्रीय महासचिव होने के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में भी संगठनात्मक कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्होंने कहा, 'मेरे पास छत्तीसगढ़ में पहले से कार्य करने का अनुभव है, और मुझे विश्वास है कि वहां भी हम अच्छे परिणाम देंगे। पार्टी का विस्तार चल रहा है और हम अपने कार्यकताओं के साथ मिलकर इसे सफल बनाएंगे।'

क्या केरल के मुख्यमंत्री बनेंगे शशि थरूर

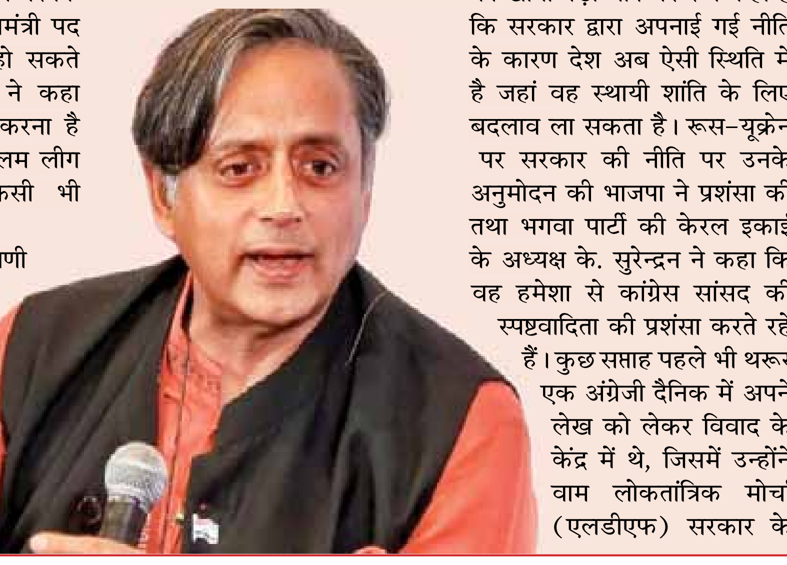

■ **बीएनटी न्यूज**

आईयूएमएल सांसद ई टी मोहम्मद बशीर ने कहा कि शशि थरूर फासीवादी ताकतों के खिलाफ एक बहुत मजबूत योद्धा हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता केरल में यूडीएफ के लिए एक संपत्ति हैं और इस बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि वह कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े होंगे। एक साक्षात्कार में बशीर ने कहा कि थरूर के किसी न किसी बयान को लेकर कहानियां गढ़ी जाती हैं, लेकिन लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह असंतुष्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारा मानना है कि वह कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े होंगे और उस पार्टी में उनकी प्रमुख भूमिका होगी। यह पूछे जाने पर कि क्या थरूर केरल में मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, मलप्पुरम के सांसद ने कहा कि यह कांग्रेस को तय करना है और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ऐसे किसी भी मामले में पक्ष नहीं है।

बशीर की यह टिप्पणी थरूर द्वारा यह स्वीकार किए जाने के बाद आई है कि रूस-यूक्रेन युद्ध छिड़ने पर भारत के रुख का विरोध करने पर उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। थरूर ने कहा है कि सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के कारण देश अब ऐसी स्थिति में है जहां वह स्थायी शांति के लिए बदलाव ला सकता है। रूस-यूक्रेन पर सरकार की नीति पर उनके अनुमोदन की भाजपा ने प्रशंसा की तथा भगवा पार्टी की केरल इकाई के अध्यक्ष के. सुरेन्द्रन ने कहा कि वह हमेशा से कांग्रेस सांसद की स्पष्टवादिता की प्रशंसा करते रहे हैं। कुछ सप्ताह पहले भी थरूर एक अंग्रेजी दैनिक में अपने लेख को लेकर विवाद के केंद्र में थे, जिसमें उन्होंने वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार के तहत केरल में उद्यमशीलता के विकास की प्रशंसा की थी।

पिछले महीने कांग्रेस द्वारा इस टिप्पणी के आधार पर सवाल उठाए जाने और माकपा द्वारा इसका स्वागत किए जाने के बाद राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया था। थरूर ने बाद में स्पष्ट किया कि उन्होंने माकपा नीत सरकार की प्रशंसा नहीं की, बल्कि स्टार्ट-अप क्षेत्र में राज्य की प्रगति पर प्रकाश डाला। अगले साल केरल विधानसभा चुनाव में थरूर की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर बशीर ने कहा, राज्य चुनाव में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे (अतीत में) बहुत मददगार रहे हैं।

सरकार ने किए पासपोर्ट में कई बदलाव
माता-पिता के नाम की अनिवार्यता खत्म

पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया में बड़े बदलाव हुए हैं, जिससे दस्तावेजी प्रक्रिया ज्यादा सख्त और सुरक्षित हो गई है। नए नियमों के तहत जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता, डिजिटल एड्रेस एम्बेडिंग और पासपोर्ट के रंग-कोडिंग जैसी नई शर्तें लगाई गई हैं। इसके अलावा माता-पिता के नाम की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है, जिससे कई आवेदक राहत महसूस करेंगे।

नए नियमों के मुताबिक 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्म लेने वाले सभी नागरिकों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। यह प्रमाण पत्र नगर निगम, जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा जारी होना चाहिए। हालांकि 1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्में लोगों के लिए अन्य दस्तावेज विकल्प के रूप में मान्य होंगे, जिनमें सरकारी सेवा रिकॉर्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र और मैट्रिक सर्टिफिकेट शामिल हैं।

पासपोर्ट में अब आवेदकों का स्थायी पता पासपोर्ट के आखिरी पेज पर नहीं छापा जाएगा। इसके बजाय यह जानकारी डिजिटल रूप से एक बारकोड में एम्बेड होगी, जिसे जरूरत पड़ने पर इमिग्रेशन अधिकारी स्कैन कर सकेंगे। यह बदलाव सुरक्षा और निजता को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिससे व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग की संभावना कम हो जाएगी। सरकार ने पासपोर्ट की पहचान को आसान बनाने के लिए रंग-कोडिंग लागू की गई है। नए नियमों के तहत, सफेद रंग का पासपोर्ट सरकारी अधिकारियों को, लाल रंग का राजनयिकों के लिए, जबकि आम नागरिकों के लिए नीले रंग का पासपोर्ट जारी किया जाएगा। इसके अलावा माता-पिता के नाम की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। पहले पासपोर्ट के आखिरी पेज पर माता-पिता का नाम छापा जाता था, लेकिन अब यह अनिवार्य नहीं होगा। यह बदलाव विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो सिंगल पैरेंट परिवारों से आते हैं या जिनके माता-पिता अलग हो चुके हैं।

जमीनों पर सबसे ज्यादा भाजपा नेताओं ने किया कब्जा, बने भूमाफिया : अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोहिया पार्क में डॉ. राम मनोहर लोहिया की जयंती पर उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा नेताओं ने सबसे ज्यादा जमीनों पर कब्जा किया है और वे भूमाफिया बनकर सामने आए हैं। उन्होंने निलंबित आईएएस अधिकारी को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। सपा प्रमुख ने कहा कि लंबे समय से जमीन का बंटवारा हो रहा था। केवल एक अधिकारी नहीं बल्कि भाजपा के नेता भी भूमाफिया बन गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहनलालगंज और सरोजनी नगर में सबसे ज्यादा जमीनें भाजपा के नेताओं ने कब्जा की हैं। वे जनसेवक नहीं बल्कि भूमाफिया हो गए हैं।

मैं हिंदू हूं: मुझे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं'

■ **बीएनटी न्यूज**

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र स्थायी है, लेकिन कुर्सी नहीं। कुर्सी का सम्मान करें। आप मुस्लिम विधायकों को बाहर निकालने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। वे (बीजेपी) मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं क्योंकि यह रोजा का महीना है, और उन्हें यह पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि वे सांप्रदायिक बयान देकर देश का ध्यान आर्थिक और व्यापार पतन से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक हिंदू हूं, और मुझे बीजेपी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में हिंदू मंदिरों पर हमलों के खिलाफ भाजपा ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के नेता सुवेन्दु अधिकारी ने कहा कि पिछले 4-5 दिनों से बरुईपुर, बशीरहाट में हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने दावा किया कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मना रहे लोगों पर हमला किया गया। इसके खिलाफ भाजपा विधायक ने विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाया, लेकिन उन्हें बोलने तक नहीं दिया गया। विपक्ष के नेता ने दावा किया कि यह गैरकानूनी है और पश्चिम बंगाल की जनता की आवाज को दबाने की कोशिश है, जिसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि मांग यह है कि भेदभाव बंद किया जाना चाहिए। वोट बैंक और मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं को किनारे किया जा रहा है। हमारे मुख्य सचेतक डॉ. शंकर घोष ने हमारे मुद्दे उठाए और हमेशा की तरह उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई। हम इस निरंकुशता को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

यमुना में अब ले सकेंगे क्रूज की सवारी का आनंद

■ **बीएनटी न्यूज**

दिल्लीवासी जल्द ही नाव की सवारी का आनंद ले सकेंगे। दिल्ली सरकार और केंद्र ने सोनिया विहार और जगतपुर के बीच यमुना के 4 किलोमीटर लंबे हिस्से में जल पर्यटन विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। असिता पार्क में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि आने वाले दिनों में इस सुविधा का विस्तार किया जाएगा ताकि दिल्ली की सड़कों पर भीड़भाड़ कम हो और निवासियों को बेहतर यात्रा विकल्प मिल सकें। उन्होंने आगे कहा कि यह पहल नदी, सड़क और मेट्रो परिवहन प्रणालियों को एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और यमुना कॉरिडोर के आगे के विकास के लिए एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल की भी खोज की जाएगी।

उन्होंने यमुना की सफाई में हुई पिछली देरी को स्वीकार करते हुए कहा कि पहले इसे नाले की तरह माना जाता था। सक्सेना ने आश्वासन दिया कि नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद से प्रगति में तेजी आई है और कहा कि सौर ऊर्जा अपनाने और टिकाऊ परिवहन समाधानों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

सरकार ने सार्वजनिक परिवहन में सुधार, यातायात की भीड़ को कम करने और स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देने की योजनाओं की भी घोषणा की। एलजी ने कहा, "यह तो बस शुरूआत है। और भी विकास होने वाले हैं और हम सिस्टम का विस्तार और बेहतर बनाने के लिए निजी खिलाड़ियों के साथ काम करेंगे।"

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहल दिल्ली को स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और विकास पर केंद्रित एक आधुनिक पहचान देगी। उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकार ने बाधाएं पैदा की थीं, लेकिन लोगों ने प्रगति को चुना। गुप्ता ने टिकाऊ यात्रा को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक-सोलर हाइब्रिड नौकाओं की शुरूआत की घोषणा की और वाराणसी जैसे सांस्कृतिक और कलात्मक केंद्रों में यमुना घाटों को बदलने के अपने दृष्टिकोण को साझा किया। उन्होंने यमुना की सफाई और दैनिक विकास प्रयासों के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया, इस परिवर्तन को संभव बनाने के लिए सभी विभागों के समर्पण के लिए धन्यवाद दिया।

● **दिल्ली सरकार और केंद्र ने सोनिया विहार और जगतपुर के बीच यमुना के 4 किलोमीटर लंबे हिस्से में जल पर्यटन विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।**

यमुना नदी पर फेरी सेवा शुरू करने के लिए एमओयू पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, "यह दिल्ली के विकास के लिए एक बड़ा कदम है। हमने यमुना पर फेरी सेवा के लिए केंद्र सरकार के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यह दिल्ली में पर्यटन का एक नया क्षेत्र होगा। आप जल्द ही यह फेरी सेवा देखेंगे।"

बीजेपी मुझे डराने की कोशिश कर रही है

■ **बीएनटी न्यूज**

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य के घर पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दबिश दी। ईडी के अधिकारी सुबह से दस्तावेज खंगाल रहे थे। कार्रवाई के बीच नोट गिनने और सोना जांचने की मशीनें भी मंगाई गई है। 11 घंटे की पूछताछ खत्म होने के बाद भूपेश बघेल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी उनको डराने की कोशिश कर रही है। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि भूपेश बघेल मौत से भी नहीं डरते। मुझे ना हारने का डर है ना मरने का। भूपेश बघेल ने कहा कि उनके परिसरों पर ईडी की छापेमारी भाजपा की हताशा का नतीजा है। बघेल ने दावा किया कि ईडी को उनके घर में 32-33 लाख रुपये नकद मिले हैं।

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि 33 लाख रुपये मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरा परिवार बड़ा है और हम 140 एकड़ में खेती करते हैं और आय के तमाम साधन हैं। बघेल ने दावा किया कि ईडी को भाजपा नेताओं से संबंधित मामलों के दस्तावेजों के अलावा कुछ नहीं मिला है। पूर्व सीएम ने कहा कि पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने के बाद उनको परेशान और निराश करना छापे का मकसद है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने कथित शराब घोटाला मामले में उनके बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत दुर्ग जिले के भिलाई शहर में बघेल के परिसरों पर छापेमारी की। चैतन्य के करीबी सहयोगी लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल और कुछ अन्य लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। बघेल ने कहा कि ईडी के पास कोई प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) संख्या नहीं है। जब हमने इसके लिए पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। सात साल पहले मेरे खिलाफ एक गंभीर आरोप लगाया गया था। उस मामले में कुछ नहीं मिला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया। इस मामले में भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा।

बघेल ने आरोप लगाया कि उन्हें न तो विधानसभा में जाने दिया गया और न ही फोन इस्तेमाल करने दिया गया। मेरी बेटी, मेरा बेटा, बहू और पोते-पोतियां यहीं रहते हैं। हम मुख्य रूप से 140 एकड़ जमीन पर खेती करके कमाते हैं। इससे पहले, केंद्रीय जांच एजेंसी ने कथित शराब घोटाले के सिलसिले में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 14 स्थानों पर छापेमारी की। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में दावा किया कि यह छापेमारी संसद में प्रमुख मुद्दों पर जवाब से बचने के लिए सरकार द्वारा ध्यान भटकाने वाली रणनीति हैं। जब भी संसद सत्र चल रहा होता है, तो लोगों के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन वे इन मुद्दों से भागना चाहते हैं सरकार जन केंद्रित मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती है।

● **11 घंटे की पूछताछ खत्म होने के बाद भूपेश बघेल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी उनको डराने की कोशिश कर रही है। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि भूपेश बघेल मौत से भी नहीं डरते। मुझे ना हारने का डर है ना मरने का।**

दिल्ली में मंत्रियों के आवास का आवंटन शुरू

■ **बीएनटी न्यूज**

दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार 6, फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले को राज्य अतिथि गृह के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रही है, जिसे भाजपा नेता 'शीश महल' कहते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री (सीएम) अरविंद केजरीवाल 2015 से अक्टूबर 2024 तक इस बंगले में रहे और इसके जीर्णोद्धार पर 33.66 करोड़ रुपये खर्च किए। फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने अभियान के दौरान भाजपा ने जनता के पैसे के इस व्यय के लिए केजरीवाल पर हमला किया था और वचन दिया था कि उनके मुख्यमंत्री इस 'शीश महल' में नहीं रहेंगे।

ऐसे में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनने के बाद शालीमार बाग में अपने पारिवारिक घर में रह रही हैं, जबकि भाजपा सरकार 'शीश महल' के संसाधन का उपयोग करने के तरीकों पर विचार कर रही है। एक अधिकारी ने दिल्ली में एक राज्य अतिथि गृह की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, "अन्य राज्यों की तरह शहर में ऐसा कोई भवन नहीं है। संपत्ति (6, फ्लैग स्टाफ रोड) को इस तरह की सुविधा में परिवर्तित करने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र और स्थान पर स्थित है।"

वहीं, दिल्ली में नई भाजपा सरकार के मंत्रियों को सरकारी आवास आवंटित करने का काम शुरू हो गया है, जबकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए उपयुक्त आवास की तलाश अभी भी जारी है। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने सभी मंत्रियों, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और विपक्ष के नेता को सरकारी आवास देने की पेशकश की है। एक सरकारी सूत्र ने बताया कि वे दिल्ली सचिवालय के नजदीक मुख्यमंत्री के लिए उपयुक्त घर की तलाश कर रहे हैं।

दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि उन्हें राज निवास के पास सिविल लाइंस इलाके में एक बंगला आवंटित किया गया है।

क्या कहते हैं आपके सितारे
बीएनटी के सौजन्य से

अप्रैल माह का राशिफल जानें किस राशि के जातकों पर बरसेगा धन, किसको रहना होगा संभल कर

मेष : इस महीने मेष राशि वालों को अच्छे अवसर मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी से बचें। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, पर खर्च भी बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर तनाव से बचें। परिवार में छोटे-मोटे मतभेद संभव हैं, लेकिन मित्रों का सहयोग मिलेगा।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

वृष : वृषभ राशि के लिए यह महीना स्थिरता लेकर आएगा। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नए अवसर मिल सकते हैं। धन लाभ के योग हैं, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर आलस्य से बचें। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी।

उपाय: लक्ष्मी मंत्र का जाप करें।

मिथुन : मिथुन राशि वालों के लिए यह महीना मिला-जुला रहेगा। करियर में प्रगति होगी, लेकिन मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें, अनावश्यक खर्च से बचें। स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव संभव है। परिवार का सहयोग मिलेगा।

उपाय: बुधवार को गणेशजी को दूर्वा चढ़ाएँ।

कर्क : कर्क राशि वालों के लिए यह महीना शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। धन लाभ के योग हैं, पर बचत पर ध्यान दें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन खान-पान का ध्यान रखें। प्रेम और परिवार में सुखद माहौल रहेगा।

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएँ।

सिंह : सिंह राशि के लिए यह महीना ऊर्जावान रहेगा। नौकरी और व्यापार में उन्नति के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पर जोखिम भरे निवेश से बचें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखें। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।

कन्या : कन्या राशि वालों को इस महीने संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में मेहनत रंग लाएगी। धन के मामले में सावधानी बरतें, खर्च बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य में छोटी-मोटी परेशानी संभव है। परिवार और प्रेम में संतुलन बनाए रखें।

उपाय: बुधवार को हरी मूंग का दान करें।

तुला : तुला राशि के लिए यह महीना सकारात्मक रहेगा। करियर में नए अवसर मिलेंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आर्थिक लाभ होगा, पर बजट बनाकर चलें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी।

उपाय: सफेद फूल मंदिर में चढ़ाएँ।

वृश्चिक : वृश्चिक राशि वालों के लिए यह महीना चुनौतीपूर्ण लेकिन फलदायी रहेगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत से सफलता मिलेगी। धन की स्थिति ठीक रहेगी, पर उधार देने से बचें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर पेट से संबंधित समस्याएँ। परिवार में सहयोग मिलेगा।

उपाय: हनुमानजी को लाल चंदन चढ़ाएँ।

धनु : धनु राशि के लिए यह महीना शुभ रहेगा। करियर में प्रगति और मान-सम्मान में वृद्धि होगी। धन लाभ के योग हैं, पर खर्च पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। परिवार और प्रेम में सुखद अनुभव होंगे।

उपाय: गुरुवार को पीली वस्तु का दान करें।

मकर : मकर राशि वालों के लिए यह महीना औसत रहेगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत करनी पड़ेगी, पर सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन बड़े निवेश से बचें। स्वास्थ्य में सुधार होगा। परिवार में थोड़ा तनाव संभव है।

उपाय: शनि मंदिर में तेल चढ़ाएँ।

कुंभ : कुंभ राशि के लिए यह महीना लाभकारी रहेगा। नौकरी और व्यापार में उन्नति होगी। धन के नए स्रोत खुल सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पर थकान से बचें। परिवार और प्रेम में सुखद माहौल रहेगा।

उपाय: काले तिल का दान करें।

मीन : मीन राशि वालों के लिए यह महीना सामान्य रहेगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, पर बचत पर ध्यान दें। स्वास्थ्य में छोटी-मोटी परेशानी संभव है। परिवार का सहयोग मिलेगा।

उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें।

सपा-बसपा-कांग्रेस को जनता वापस नहीं आने देगी : केशव प्रसाद मौर्य

■ **बीएनटी न्यूज**

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आठ साल पूरे होने पर जश्न मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के सामने प्रदेश का पूरा विजन रखा। इसी कड़ी में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी के आठ साल उत्कर्ष के हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस को अब जनता वापस नहीं आने देगी।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से कहा कि भाजपा सरकार के आठ साल पूरे होने के एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी ने आपके साथ संवाद किया है। यह आठ वर्ष यूपी के उत्कर्ष के साल हैं। 2027 में तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। 2027 में 2017 दोहराने जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि 2027 ही नहीं, बल्कि 2047 तक कमल खिलाएंगे। सपा, बसपा और कांग्रेस को जनता वापस नहीं आने देगी, ऐसा हमें भरोसा है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव के उस नारे पर भी मौर्य ने टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपी बदहाल है। मौर्य ने इस पर कहा कि 8 साल में समाजवादी पार्टी बुरी तरह से बदहाल और बर्बाद हो चुकी है। भाजपा निरंतर आगे बढ़ रही है। जनता लगातार प्रगति कर रही है। गरीब, मजदूर और किसान के उत्थान के लिए अनेकों कार्य हो रहे हैं।

महाराष्ट्र में भाजपा का शासन औरंगजेब से भी बदतर

■ बीएनटी न्यूज

शिवसेना नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार के शासन को औरंगजेब से भी बदतर बताया और दावा किया कि इस सरकार के कारण किसान अपनी जान दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य में किसान, बेरोजगार लोग और महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं।

राउत ने कहा, औरंगजेब को दफनाए 400 साल हो गए हैं। उसे भूल जाइए। क्या महाराष्ट्र में किसान औरंगजेब के कारण आत्महत्या कर रहे हैं? उनका कहना था, वे आपकी (भाजपा) वजह से ऐसा कर रहे हैं।

राउत ने सवाल किया कि यदि मुगल शासक ने अत्याचार किए, तो यह सरकार क्या कर रही है? भाजपा राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन का नेतृत्व करती है, जिसमें शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी शामिल हैं। राउत ने कहा, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। भाजपा का कार्यकाल औरंगजेब से भी बदतर है। वह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की टिप्पणी पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि हर कोई महसूस करता है कि छत्रपति संभाजीनगर में मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन इसे कानूनी दायरे में किया जाना चाहिए क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार ने इस स्थल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में रखा था।

आरएसएस-भाजपा के लिए काम करने वाले नेताओं को राहुल गांधी कांग्रेस से बाहर निकालें

■ बीएनटी न्यूज

हरियाणा विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने वाली कांग्रेस पार्टी को निकाय चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा है। हरियाणा निकाय चुनाव के परिणाम सामने आए। भाजपा ने 10 में से नौ नगर निकायों में जीत दर्ज की। भाजपा जहां इस जीत से गदगद है, वहीं कांग्रेस के भीतर कार्रवाई के स्वर उठने लगे हैं।

निकाय चुनाव के परिणाम में पार्टी के प्रदर्शन पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए जो भाजपा और आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं।

राशिद अल्वी ने कहा कि संगठन के तौर पर कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत है।

कांग्रेस की जो विचारधारा है, उसे जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। कांग्रेस की सरकारों ने जो कार्य किए, उन्हें जनता तक पहुंचाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "अभी हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में भाजपा-आरएसएस की सोच वाले लोग शामिल हैं, यह सही बात है। इलाहाबाद कोर्ट का जब राम मंदिर को लेकर फैसला आया था, तब कांग्रेस के एक नेता ने मिठाइयां बांटी थीं। मैंने तब ऐतराज भी जताया था। मैं समझता हूं कि यह सभी की जिम्मेदारी है कि कांग्रेस को मजबूत करें। इसलिए राहुल गांधी को ऐसे लोगों को चिह्नित करना चाहिए जो भाजपा-आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं।"

शिवसेना नेता संजय निरुपम के जलियांवाला बाग वाले बयान पर राशिद अल्वी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के बयान दिए जाते हैं। संजय निरुपम जब कांग्रेस पार्टी में थे, तो कुछ और बोलते थे। आज दूसरी पार्टी में चले गए तो यू-टर्न ले लिया। ऐसे लोगों के बयान का कोई मतलब नहीं है जो वक्त-वक्त पर बदल जाते हैं।

दरभंगा की मेयर अंजुम आरा के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि यह पहली होली नहीं है जिस पर विवाद हो रहा है। अगर दोनों समुदाय के लोग एक-दूसरे का सम्मान करेंगे, तो कोई झगड़ा नहीं होगा। मिल-जुलकर होली मनानी चाहिए। नमाज अदा करने वाले लोगों की इज्जत करनी चाहिए।

'आप' संयोजक अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की एक अदालत द्वारा एफआईआर करने के आदेश पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि कोर्ट का जो फैसला है, हम सम्मान करते हैं।

तेलंगाना विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस ने अभिनेत्री विजयशांति को मैदान में उतारा

■ बीएनटी न्यूज

तेलंगाना विधान परिषद चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख से ठीक पहले कांग्रेस और सीपीआई ने अपने चार उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। खास बात है कि कांग्रेस ने लेडी अमिताभ के नाम से मशहूर अभिनेत्री विजयशांति को मैदान में उतारा है। एमएसएल कोटे के तहत पांच एमएलसी सीटों के लिए 20 मार्च को चुनाव होने हैं। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीन एमएलसी सीटों के लिए अड्डंकी दयाकर, केथावत शंकर नायक और विजयशांति के नामों पर मुहर लगा दी। साथ ही, उन्होंने सहयोगी पार्टी सीपीआई को एक सीट आवंटित की। कुछ ही घंटों बाद, सीपीआई ने राज्य कार्यकारी सदस्य एन सत्यम को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया।

वे बीते दो दशक पहले राजनीति के मैदान में आई थीं। वे कई दल बदल चुकी हैं। अब विजयशांति ने 20 मार्च को तेलंगाना एमएलसी चुनावों के लिए कांग्रेस के तीन उम्मीदवारों के बीच आश्चर्यजनक वापसी की है। कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषाओं में 180 से अधिक फिल्मों में काम कर चुकीं विजयशांति को अपने राजनीतिक करियर में शायद ही इतनी सफलता मिली हो।

हालांकि, कांग्रेस में उन्हें हमेशा आलाकमान का आशीर्वाद प्राप्त रहा है।

सूत्रों ने बताया कि तेलंगाना कांग्रेस ने एआईसीसी को जो नामों की अंतिम सूची भेजी थी, उसमें विजयशांति का नाम नहीं था। एआईसीसी सूत्र ने बताया कि पार्टी आलाकमान खासकर सोनिया गांधी विजयशांति को एमएलसी बनाने के पक्ष में थीं।

विजयशांति ने 1998 में बीजेपी के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरूआत की थी। फिर उन्होंने तल्ली तेलंगाना पार्टी बनाई। बाद में वे बीआरएस में शामिल हो गईं और मेडक से लोकसभा सदस्य के रूप में जीतीं। इसके बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गईं। हालांकि, उन्होंने नवंबर 2020 में कांग्रेस छोड़कर 6 दिसंबर, 2020 को फिर से बीजेपी में शामिल हुई। नवंबर 2023 में, उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और तभी कांग्रेस में फिर से शामिल हो गईं। मौजूदा विधायकों की संख्या के हिसाब से कांग्रेस आसानी से तीन सीटें और बीआरएस एक सीट जीत सकती है। लेकिन कांग्रेस के पास चौथी सीट जीतने का भी मौका है।

नीतीश को आश्रम चले जाना चाहिए: वह सरकार चलाने में सक्षम नहीं

■ बीएनटी न्यूज

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ताजा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि उनका प्रशासन राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में विफल रहा है। तेजस्वी यादव ने आज आरोप लगाया कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अपहरण और डकैती जैसी घटनाएं ताबड़तोड़ हो रही हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अपराधियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। वे अपना विवेक खो चुके हैं।

राजद नेता ने कहा कि मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि लालू जी ने पहले पीएम बनाया और मैंने उन्हें दो बार सीएम बनाया। नीतीश कुमार और लालू यादव में कोई तुलना नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश

कुमार से पहले भी मेरे पिता (लालू यादव) सांसद बने थे। उन्होंने कहा कि हमारे समर्थन पत्र के बिना वह सीएम नहीं बन सकते थे। उन्हें आश्रम चले जाना चाहिए क्योंकि वह सरकार चलाने में सक्षम नहीं हैं। वह 14 करोड़ लोगों के भविष्य के साथ क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार की हालत स्थिर नहीं है।

इससे पहले तेजस्वी यादव उस समय नाराज हो गए जब उनसे बिहार के मुख्यमंत्री और जद (यू) अध्यक्ष नीतीश कुमार के साथ फिर से गठबंधन की संभावना के बारे में पूछा गया। नीतीश कुमार राजद के साथ गठबंधन तोड़ पिछले साल भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल हो गए थे। पूर्व उपमुख्यमंत्री यादव यहां कथित तौर पर राजग द्वारा आरक्षण की चोरी और उसे हजम कर जाने के खिलाफ राजद द्वारा आयोजित धरने के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

जब उनसे पूछा गया कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले उनके जद (यू) प्रमुख के साथ हाथ मिलाने की संभावना है, तो यादव ने कहा, हम हाथ क्यों मिलाएंगे? आप मौजूदा मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उनसे कहा गया कि मीडिया के एक वर्ग में ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि हाल ही में 74 साल के हुए नीतीश कुमार को इस बात की चिंता है कि चुनाव के बाद भाजपा नेतृत्व परिवर्तन के लिए दबाव डाल सकती है और राजद इस स्थिति का फायदा उठाकर उसके साथ गठबंधन का 'प्रस्ताव' देने को तैयार है।

संविधान बदलने की बात कांग्रेस का 'हिडन एजेंडा'

■ बीएनटी न्यूज

कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के 'संविधान बदल रहा है' बयान के बाद से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। शिवकुमार के इस बयान पर भाजपा के तमाम नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। इसी कड़ी में विधान परिषद के नेता विपक्ष चलवाडी नारायण स्वामी की भी एंट्री हो गई।

उन्होंने बीएनटी न्यूज से बात करते हुए कहा कि डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का बयान उनकी पार्टी का 'हिडन एजेंडा' खोलने वाला है। उन्होंने कहा कि कल तक कांग्रेस भाजपा पर संविधान बदलने का आरोप लगा रही थी, लेकिन अब डीके शिवकुमार का बयान यह साबित करता है कि उनका असली मकसद क्या है।

नारायण स्वामी ने कहा कि साल 1975 में संविधान को दो साल के लिए सस्पेंड करके इमरजेंसी लगाई गई थी। क्या यह फैसला देश के हित में लिया गया था? नहीं, इस फैसले का उद्देश्य केवल सत्ता में बने रहना था। अब यही बात कांग्रेस का 'हिडन एजेंडा' साबित कर रही है।

उन्होंने आगे कहा कि अब समय बदल चुका है, यह डिजिटल युग है। जो कुछ भी हम बोलते हैं, वह तुरंत वायरल हो जाता है। जो डीके शिवकुमार ने कहा है, उसे समझना बहुत जरूरी है। अब यह समय संविधान को बदलने का नहीं, बल्कि नई सोच और विकास के लिए काम करने का है।

संभल में होली खेलने में किसी को समस्या नहीं : अनुज चौधरी

■ बीएनटी न्यूज

उत्तर प्रदेश समेत देश के सभी राज्यों में होली धूमधाम से मनाई जा रही है। होली के दिन रमजान का जुमा होने के कारण यूपी प्रशासन अलर्ट है। प्रदेश के संवेदनशील जिलों में से एक संभल में होली को लेकर सुरक्षा की विशेष तैयारी रखी गई है। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने बताया कि जिले में कोई समस्या नहीं हो रही है और सभी आराम से होली खेल रहे हैं। सीओ अनुज चौधरी ने बीएनटी न्यूज को बताया, 'संभल बिल्कुल ठीक है, जिले के लोग आराम से होली खेल रहे हैं। किसी को कोई भी समस्या नहीं हो रही है।'

संभल में मस्जिद को ढकने के आदेश को लेकर अनुज चौधरी ने बताया, 'सभी ने अपनी मर्जी से मस्जिदों को ढका है।'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उनकी बातों के समर्थन के लिए अनुज चौधरी ने कहा, 'वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसके लिए उन्हें धन्यवाद।' अनुज चौधरी अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। होली और जुमा एक दिन पड़ने के कारण पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक बयानबाजी तेज है।

इसी बीच अनुज चौधरी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की थी कि अगर किसी को होली के रंग से परहेज है तो वो घर पर नमाज अदा करें।

संभल यूपी के संवेदनशील जिलों में से एक है। 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद से ही संभल चर्चाओं में है।

कांग्रेस पार्टी 'आप' के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती

■ बीएनटी न्यूज

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने साफ किया है कि उनकी पार्टी आगामी गुजरात और गोवा विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी (आप) के साथ गठबंधन नहीं करेगी।

हाल ही में आम आदमी पार्टी (आप) की नेता और दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने मडगांव में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा था कि 'आप' गुजरात और गोवा विधानसभा चुनाव अपने दम पर अकेले लड़ेगी।

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बात करते हुए कहा, "इसमें नया क्या है? वास्तव में उनके साथ गठबंधन कौन कर रहा है? खुद ही अपने मियां मिट्ठू बन रहे हैं, उनसे कौन गठबंधन कर रहा है? अगर वे गठबंधन करना चाहते हैं, तो तृणमूल कांग्रेस या समाजवादी पार्टी (सपा) जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन कर सकते हैं,

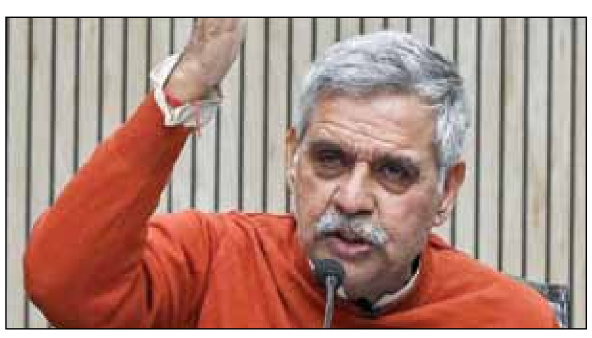

जिनका मुख्य एजेंडा कांग्रेस के वोटों को काटना है। कांग्रेस उनके साथ कोई गठबंधन नहीं कर रही है।" अवैध बैनर को लेकर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश पर संदीप दीक्षित ने कहा, "अगर क्राइम हुआ है तो उस पर केस चलना चाहिए, ऐसी चीजें बहुत कम होती है कि कोर्ट इस पर फैसला लेता है। लेकिन, अगर कानून का उल्लंघन हुआ है तो केस होना चाहिए। मैं इस पर दिल्ली पुलिस, एमसीडी और डीडीए से एक और बात कहूंगा कि इस कानून या ऑर्डर का संज्ञान लेते हुए, पूरी दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर-होर्डिंग लगाए जाते हैं, चाहे सरकारी जगह हो या प्राइवेट, यहां तक कि खंभों पर भी लग जाते हैं, इस पर भी ध्यान दें क्योंकि कोर्ट ने इस बात को कहा है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी पर अपने होर्डिंग या पोस्टर नहीं लगा सकते। ये धड़ल्ले से होता है। ऐसा सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने ही नहीं किया है, ठीक है, वो पकड़े गए हों, उन पर सजा होगी। लेकिन, बाकी जितने हैं, कभी जन्मदिन के लगते हैं, कभी सार्वजनिक जगहों पर लोग झाड़े लगाते हैं, उस पर भी एक

● कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बात करते हुए कहा, ₹इसमें नया क्या है? वास्तव में उनके साथ गठबंधन कौन कर रहा है? खुद ही अपने मियां मिट्ठू बन रहे हैं, उनसे कौन गठबंधन कर रहा है?

तरीके से रोक लगनी चाहिए।"

संदीप दीक्षित ने उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह के होली पर दिए विवादित बयान 'रंगों से दिक्कत है तो हिजाब की तरह तिरपाल ओढ़कर निकलें' पर भी रिएक्शन दिया। उन्होंने रघुराज सिंह के बयान को गलत बताते हुए कहा कि होली हमेशा से खेली गई है, होली के दिन चाहें रमजान हो या कोई त्योहार हो या न हो। कई लोग होली खेलने से परहेज करते हैं। हिंदू समाज में लोग अलग-अलग तरीके से होली मनाते हैं, कोई सिर्फ टीका लगवाते हैं। कुछ रंग से परहेज करते हैं। समाज में हजारों सालों से अलग-अलग समुदायों ने अलग-अलग धर्म के त्योहारों को मनाना सीखा है, लेकिन भाजपा इस पर राजनीति कर रही है, यह बहुत गलत बात है।

उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर कहा कि इसमें सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, इसमें बीजेडी, तृणमूल कांग्रेस भी है। तमाम पार्टियां पूछ रही हैं कि महाराष्ट्र में दो महीने में 80 लाख वोटर कैसे बढ़ गए, दिल्ली और हरियाणा में कैसे बढ़ गए, अचानक बढ़ जाते हैं, जो चीज आज तक नहीं होती है, वह दो-दो महीने में इलेक्शन कमीशन कर देता है। इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है, इलेक्शन कमीशन तो पब्लिक इंस्टीटूशन है। इनकम टैक्स भी अचानक बढ़ जाता है तो वो पूछते हैं कि अचानक कैसे बढ़ गया? लेकिन, इलेक्शन कमीशन किस अहंकार में घूम रही है?

प्रवेश वर्मा-वीरेंद्र कादियान ने एनडीएमसी के सदस्य के रूप में शपथ ली

■ बीएनटी न्यूज

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने अपनी परिषद की प्रारम्भिक बैठक की अध्यक्षता सांसद-नई दिल्ली, सुश्री बांसुरी स्वराज ने की । सुश्री बांसुरी स्वराज ने बैठक प्रारम्भ होते ही प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, विधायक-नई दिल्ली और दिल्ली सरकार के मंत्री, वीरेंद्र सिंह कादियान विधायक-दिल्ली कैंट और रवि कुमार अरोड़ा, अतिरिक्त सचिव, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार को संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा की शपथ भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी 3 मार्च, 2025 के राजपत्र अधिसूचना के अनुसरण में नई दिल्ली नगरपालिका के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई ।

इसके बाद, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की अध्यक्षता में

परिषद की बैठक में सांसद नई दिल्ली, सुश्री बांसुरी स्वराज, अध्यक्ष - एनडीएमसी, केशव चंद्रा, उपाध्यक्ष- कुलजीत सिंह चहल, विधायक और सदस्य एनडीएमसी, वीरेंद्र सिंह कादियान, परिषद के सदस्य झ अनिल वाल्मीकि, श्रीमती सरिता तोमर, दिनेश प्रताप सिंह और रवि कुमार अरोड़ा की उपस्थिति में एजेंडे में शामिल विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया गया और उन्हें मंजूरी दी गई।

जिन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को परिषद् द्वारा बैठक में मंजूरी दी गई, वे निम्नलिखित हैंः-

वैक्सीनेटर कैडर के पद के लिए भर्ती विनियम (आरआर)

टीकाकरण संवर्ग यानी वैक्सीनेटर, निरीक्षक और टीकाकरण अधीक्षक के पद के लिए मौजूदा भर्ती नियम वर्ष 1972 और 1973 में तैयार किए गए थे। अब, परिषद ने इन पदों के लिए भर्ती नियम बनाने/संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

एनडीएमसी में जनसंपर्क कैडर के पदों के लिए मौजूदा भर्ती नियम वर्ष 2008 में बनाए गए थे। अब, कैडर के पदों को संयुक्त निदेशक (सूचना एवं प्रचार), सहायक निदेशक (सूचना एवं प्रचार), सूचना एवं प्रचार अधिकारी और सूचना एवं प्रचार सहायक के रूप में पुनः नामित किया गया है।

सहायक निदेशक और संयुक्त निदेशक (जनसंपर्क विभाग) के रूप में पदोन्नति के लिए अतिरिक्त पात्रता मानदंड शामिल करने के लिए भर्ती नियमों के मसौदे को संशोधित किया गया है। परिषद ने जनसंपर्क कैडर के पदों के लिए भर्ती नियम बनाने/संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी ।

एनडीएमसी में पशु चिकित्सा अस्पतालों में पदों की आवश्यकता और नियमित आधार पर पदों के सृजन के कारण, विभाग की बेहतरी और जनहित में नियमित आधार पर पदों को भरने के लिए भर्ती नियम बनाने की अत्यधिक मांग रही ।

1994 से पहले, प्रशासक द्वारा अनुमोदित भर्ती नियमों के आधार पर भर्ती की जाती थी, जिसे कभी आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया था। उसके बाद अधिसूचित भर्ती नियमों की अनुपलब्धता के कारण, पद नियमित आधार पर नहीं भरा जा सका।

इसलिए अन्य सरकारी संगठनों के आधार पर समान पदों के आरआर से संदर्भ लेते हुए और सलाहकार (कार्मिक) के परामर्श से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीएंडटी) के मौजूदा निदेशों के अनुसार भर्ती नियम तैयार किए गए हैं।

भारत के बड़े मंदिर करते हैं जमकर कमाई : सरकार को देते हैं भारी भरकम टैक्स

■ बीएनटी न्यूज

भारत में लाखों मंदिर हैं और इनसे होने वाले करोड़ों की कमाई और उस पर टैक्स को लेकर इन दिनों एक बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार मंदिरों को जीएसटी बकाया का नोटिस भेज रही है। उधर, बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस पर हमला बोला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक विश्लेषण के बाद पता चला है कि भारत का सबसे अमीर मंदिर ट्रस्ट तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम है, जो वित्त वर्ष 2025 में अपनी 4,774 करोड़ रुपए की वार्षिक आय पर 1.5 फीसदी से कम जीएसटी का भुगतान करेगा। नवंबर 2024 में, देश के सबसे धनी मंदिरों में से एक तिरुवनंतपुरम के श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर को बकाया टैक्स भुगतान के लिए नोटिस भेजा

था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल साल की अवधि के लिए मांग केवल 1.57 करोड़ रुपए की थी, जबकि मंदिर ने अकेले 2014 में 700 करोड़ रुपए कमाए थे।

वहीं वैष्णो देवी मंदिर ने वित्त वर्ष 2024 में 683 करोड़ रुपए कमाए, जिसमें से 255 करोड़ रुपए चढ़ावे से आए, जो टैक्स-फ्री हैं और 133.3 करोड़ रुपए ब्याज से आए। टीटीडी के मामले में 4,800 करोड़ रुपए की कमाई में से एक तिहाई से ज्यादा हुंडी संग्रह से आए हैं। इस मामले में जीएसटी के तहत टैक्स लायबिलिटी वित्त वर्ष 2021 से पांच सालों में करीब 130 करोड़ रुपए रही है। हालांकि, इस मामले में मंदिरों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन भारत के दो सबसे बड़े मंदिर ट्रस्टों की आय पिछले सात सालों में दोगुनी हो गई है।

साल दर साल मंदिरों की आय बढ़ रही है जिसमें तिरुपति ट्रस्ट का वित्त वर्ष 2017 में बजट 2,678 करोड़ था, जो इसकी वेबसाइट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 5,145 करोड़ रुपए हो गया। वैष्णो देवी ट्रस्ट की आय वित्त वर्ष 2017 में 380 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 683 करोड़ रुपए हो गई है। संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक तिरुपति मंदिर ने वित्त वर्ष 2017 में 14.7 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2022 में 15.58 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2023 में 32.15 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2024 में 32.95 करोड़ रुपए का जीएसटी भुगतान किया गया। वहीं प्रसाद और धार्मिक समारोह जीएसटी संग्रह से मुक्त होते हैं। टीटीडी और वैष्णो देवी के मामले में यह आय एक तिहाई से ज्यादा थी।

वित्त वर्ष 2024 में वैष्णो देवी मंदिर ट्रस्ट ने अपनी आय का 37 फीसदी दान से अर्जित किया। वहीं, वित्त वर्ष 2025 में टीटीडी को दान से करीब 4,800 करोड़ रुपए अर्जित करने की उम्मीद है। यदि कमरे का शुल्क एक हजार रुपए से ज्यादा है और यदि सामुदायिक हॉल या खुले क्षेत्र का शुल्क 10 हजार रुपए से ज्यादा है, तो परिसर के किराए पर जीएसटी लगाया जाता है। व्यवसाय के लिए किराए पर दी गई दुकानों और अन्य स्थानों पर भी जीएसटी नहीं लगता है, यदि मासिक किराया 10 हजार रुपए से कम है।

धरती पर सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी, समुद्र में डॉल्फिन्स ने किया स्वागत

■ बीएनटी न्यूज

अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर, साथ ही नासा के निक हैग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोबुनोव, नौ महीने के लंबे मिशन के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे हैं।

एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान द्वारा सुरक्षित रूप से फ्लोरिडा के तट पर उतारा गया था।

धरती पर लौटे अंतरिक्ष यात्रियों को एक सुंदर और अप्रत्याशित अनुभव हुआ। उनका स्वागत डॉल्फिन्स ने किया। ड्रैगन कैप्सूल के समुद्र में उतरते ही डॉल्फिन कैप्सूल के आसपास तैरते हुए देखे गए।

यह एक लगभग जादुई क्षण था जब डॉल्फिन ने ड्रैगन

कैप्सूल के चारों ओर चक्कर लगाया, इससे पहले कि इसे रिकवरी पोत पर रखा जाता। रिकवरी टीम ने कैप्सूल के साइड हैच को सावधानी से खोला, जो सितंबर के बाद से पहली बार खुला था।

अंतरिक्ष यात्रियों को कैप्सूल से बाहर निकाला गया और 45 दिनों के पुनर्वास कार्यक्रम के लिए 'स्ट्रेच' ले जाया गया। क्रू-9 की पृथ्वी पर वापसी में अपनी चुनौतियां थीं।

मूल रूप से, यह मिशन (जो बोइंग के स्टारलाइनर की पहली चालक दल वाली उड़ान होने वाला था) केवल आठ दिनों तक चलने वाला था।

हालांकि, स्टारलाइनर कैप्सूल के साथ तकनीकी समस्याओं के कारण, विलियम्स और विलमोर अंतरिक्ष में फंस गए थे। स्टारलाइनर के प्रणोदन समस्याओं के चलते सितंबर में इसकी वापसी बिना चालक दल के हुई।

वापसी की अनिश्चितता के कारण, नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेसएक्स के क्रू-9 मिशन में फिर से सौंप दिया।

भारत की बेटी सुनीता विलियम्स समेत सभी अंतरिक्ष यात्रियों ने रचा इतिहास : राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी चालक दल के सदस्यों की अंतरिक्ष में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रशंसा की।

रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए लिखा, नासा के क्रू-9 की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी से प्रसन्न हूं। भारत की बेटी सुनीता विलियम्स और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों वाले चालक दल ने अंतरिक्ष में मानव धीरज और दृढ़ता के इतिहास को फिर से लिखा है।

उन्होंने कहा, सुनीता विलियम्स की अविश्वसनीय यात्रा, अटूट समर्पण, दृढ़ता और संघर्ष की भावना दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करेगी। उनकी सुरक्षित वापसी अंतरिक्ष प्रेमियों और पूरी दुनिया के लिए जश्न का क्षण है। उनकी हिम्मत और उपलब्धियां हम सभी को गौरवान्वित करती हैं। उन्हें सुरक्षित रूप से धरती पर वापस लाने के लिए सभी हितधारकों को बधाई और बहुत-बहुत धन्यवाद।

सितंबर में, स्पेसएक्स ने उन्हें वापस लाने के लिए एक ड्रैगन अंतरिक्ष यान भेजा, जिसमें चार के बजाय केवल दो चालक दल के सदस्य थे, ताकि फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को समायोजित किया जा सके।

■ **समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने बीएनटी न्यूज से बात करते हुए कहा, यह सभी के लिए खुशी की बात है, क्योंकि सुनीता विलियम्स को लेकर सारा देश चिंतित था। वह पिछले 9 महीनों से अंतरिक्ष में फंसी हुई थीं। नासा और एलन मस्क के ड्रैगन ने बहुत ही कमाल का काम किया। वे सभी बधाई के पात्र हैं।**

फाल्कन 9 रॉकेट पर ड्रैगन कैप्सूल को मिशन के लिए लॉन्च किया गया था। क्रू-10 ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर क्रू-9 की जगह ले ली है।

पीएम मोदी ने तुलसी गबार्ड को दिया महाकुंभ का पवित्र जल

■ बीएनटी न्यूज

अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रयागराज के महाकुंभ से लाया गया गंगाजल गबार्ड को भेंट किया।

मुलाकात के दौरान पीएम मोदी गबार्ड को महाकुंभ की संक्षिप्त जानकारी भी देते हैं। वह बताते हैं कि इस आयोजन के दौरान 66 करोड़ लोगों ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई।

प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने भी त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई थी। वहीं

अमेरिकी खुफिया प्रमुख ने पीएम मोदी को एक 'तुलसी माला' भेंट की।

इससे पहले गबार्ड ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान सिंह ने अमेरिकी धरती पर भारतीय हितों के खिलाफ काम कर रहे खालिस्तानी चरमपंथियों का मुद्दा उठाया।

बातचीत में राजनाथ सिंह ने खालिस्तानी संगठन एसएफजे (सिख फॉर जस्टिस) की भारत विरोधी गतिविधियों पर प्रकाश डाला। एसएफजे को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ काम करने के लिए देश में प्रतिबंधित किया गया है।

मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया, "भारत ने अपनी चिंता व्यक्त की और अमेरिकी प्रशासन से गैरकानूनी संगठन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा।"

अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक (डीएनआई) तुलसी गबार्ड ने राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय चर्चा की, जिसमें दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

तुलसी गबार्ड ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। डोभाल और गबार्ड के बीच बैठक में मुख्य रूप से खुफिया जानकारी साझा करने और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा हुई।

गबार्ड हिंद-प्रशांत क्षेत्र की बहु-राष्ट्रीय यात्रा के तहत भारत की ढाई दिन की यात्रा पर हैं। उन्होंने 11 मार्च को 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'मैं हिंद-प्रशांत की बहु-राष्ट्रीय यात्रा पर हूं, एक ऐसा क्षेत्र जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूं क्योंकि मैं प्रशांत क्षेत्र में पली-बढ़ी हूं। मैं जापान, थाईलैंड और भारत की यात्रा करूंगी। अमेरिका लौटते समय फ्रांस में कुछ देर के लिए रुकूंगी।'

'इस्लामी आतंकवाद' को बढ़ावा देने वाली विचारधारा को हराने के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध : तुलसी गबार्ड

■ बीएनटी न्यूज

अमेरिकी इंटेलिजेंस प्रमुख तुलसी गबार्ड भारत दौरे पर हैं। उन्होंने बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल और अशांति पर चिंता जाहिर की साथ ही कहा कि ट्रंप प्रशासन 'इस्लामी आतंकवाद' की विचारधारा को हराने के लिए प्रतिबद्ध है।

एनडीटीवी से कई मुद्दों पर विशेष बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया प्रमुख ने बांग्लादेश की बिगड़ती स्थिति की आलोचना की। उन्होंने चरमपंथी ताकतों और इस्लामी आतंकवाद से निपटने में ट्रंप प्रशासन के दृढ़ संकल्प पर प्रकाश डाला।

गबार्ड ने कहा कि ट्रंप प्रशासन वैश्विक स्तर पर 'इस्लामी आतंकवाद' को बढ़ावा देने वाली विचारधारा को हराने के लिए प्रतिबद्ध है।

नेशनल इंटेलिजेंस की निदेशक तुलसी गबार्ड ने आगे कहा, "हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का लंबे समय से उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और हत्या, अमेरिकी सरकार, राष्ट्रपति ट्रंप के लिए चिंता का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है।"

गबार्ड के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के साथ बातचीत शुरू कर दी है।

अमेरिकी खुफिया प्रमुख ने बांग्लादेश सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में 'इस्लामिक खिलाफत' का मंच तैयार करने के लिए चरमपंथी तत्वों और आतंकवादियों की ओर से की जा रही नापाक साजिशों के बारे में भी बात की। उन्होंने इसे 'वैश्विक पैटर्न' बताया और समझाया कि कैसे ट्रंप प्रशासन इस तरह के खतरे से निपटने में अपनी नीतियों को प्राथमिकता दे रहा है।

गबार्ड ने कहा, इस्लामिक चरमपंथी और विभिन्न आतंकवादी समूहों के वैश्विक प्रयास एक ही विचारधारा और उद्देश्य से प्रेरित हैं – वह है एक इस्लामिक खिलाफत का शासन। अमेरिकी खुफिया प्रमुख ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने 'कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद' के मंसूबों को हराने के लिए अपना रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप इस्लामी आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली विचारधारा की पहचान करने और इस विचारधारा को हराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

बांग्लादेश : चुनाव को लेकर उलझे राजनीतिक दल, चुनाव आयोग ने रखी अपनी राय

■ बीएनटी न्यूज

बांग्लादेश चुनाव आयोग (ईसी) ने चेतावनी दी है कि राष्ट्रीय चुनाव से पहले स्थानीय सरकार के चुनाव कराने से संसदीय चुनाव में देरी होगी। आयोग ने राष्ट्रीय और सभी स्थानीय सरकारों के चुनाव चार महीने की समय-सीमा के भीतर पूरे करने के प्रस्ताव का विरोध किया।

आयोग ने तर्क दिया कि सिर्फ स्थानीय चुनाव पूरे होने में ही लगभग एक साल का समय लग जाता है क्योंकि ये चुनाव चरणों में होते हैं।

चुनाव आयोग ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय सहमति आयोग को अपनी राय भेजी, जिसमें चुनाव से संबंधित कई सुधार प्रस्तावों का विरोध किया गया।

बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट यूएनबी ने चुनाव आयोग के वरिष्ठ सचिव

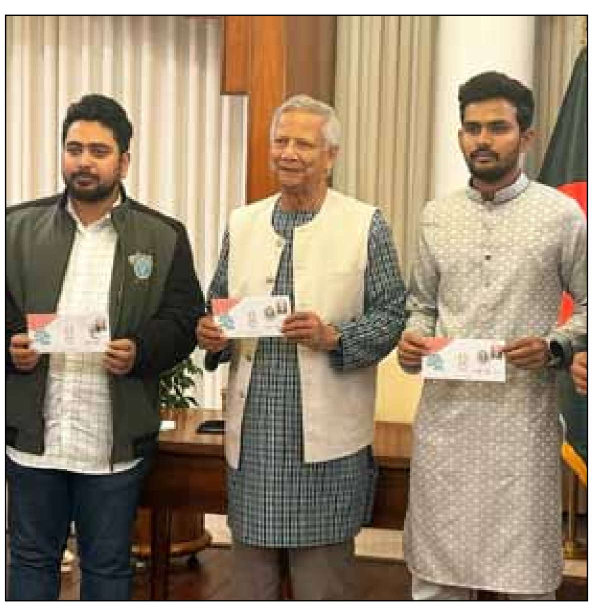

अख्तर अहमद के हवाले से कहा, "अली रियाज (राष्ट्रीय सहमति आयोग के उपाध्यक्ष) को संबोधित करते हुए, हमने कुछ प्रस्तावों पर अलग-अलग विचार व्यक्त करते हुए अपनी राय भेजी है।"

देश के प्रमुख समाचार पत्र 'डेली स्टार' ने बताया कि चुनाव आयोग ने कई सुधार प्रस्तावों पर आपत्ति जताई है, इनमें निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, चुनाव आयुक्तों के खिलाफ जांच, स्थानीय सरकार और राष्ट्रीय चुनाव का समय जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।

अखबार के मुताबिक ईसी ने प्रस्तावित चुनाव आयोग अध्यादेश 2025 का विरोध किया है। चुनाव आयोग ने कहा कि यह आयुक्तों की स्वतंत्रता को खत्म कर देगा और उन्हें राजनीतिक दबाव के सामने ला खड़ा करेगा।

इस महीने की शुरुआत में भी चुनाव आयोग ने कहा था कि राष्ट्रीय चुनाव से पहले स्थानीय चुनाव कराना संभव नहीं होगा। दरअसल बांग्लादेश में प्रमुख राजनीतिक दल इस बात पर उलझे हुए हैं कि पहले कौन सा चुनाव कराया जाए।

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने भी दिसंबर में राष्ट्रीय संसदीय चुनाव होने की संभावना पर संदेह जताया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि चुनाव में देरी के लिए कथित तौर पर मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के भीतर से एक 'साजिश' चल रही है।

बांग्लादेश में विभिन्न राजनीतिक संगठनों की बहुप्रचारित एकता, जो अगस्त 2024 में शेख हसीना के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई अवामी लीग सरकार को हटाने के दौरान पूरी तरह व्यक्त हुई अब धीरे-धीरे फीकी पड़ती दिख रही है। कई राजनीतिक नेता जो पहले यूनुस का समर्थन करते थे, अब खुलकर उनकी आलोचना कर रहे हैं, खासकर राष्ट्रीय चुनाव कराने में हुई लंबी देरी को लेकर।

शेख हसीना का समर्थन करने वाले शिक्षक 'अवांछित' घोषित, कक्षाएं लेने से रोका गया

ढाका यूनिवर्सिटी के कई शिक्षक कक्षाएं नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया है। शेख हसीना सरकार का कथित रूप से समर्थन करने के कारण उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने जुलाई के विद्रोह के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए विभिन्न विभागों के लगभग 50 शिक्षकों को 'अवांछित' घोषित कर दिया।

अफगान नागरिकों को 31 मार्च तक छोड़ना होगा देश, नहीं बढ़ेगी समय सीमा : पाकिस्तान

■ बीएनटी न्यूज

इस्लामाबाद ने पाकिस्तान में रह रहे अफगान नागरिक कार्ड (एसीसी) धारकों के लिए निर्वासन की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया और कहा कि सभी बिना दस्तावेज वाले विदेशियों को 31 मार्च तक देश छोड़ना होगा।

पाकिस्तान ने प्रत्यावर्तन की समग्र प्रक्रिया को लेकर संयुक्त राष्ट्र, कई मानवाधिकार समूहों और प्रासंगिक एजेंसियों की ओर से उठाई गई चिंताओं, आपत्तियों को भी दरकिनार कर दिया।

पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने पुष्टि करते हुए कहा कि अवैध विदेशियों और एसीसी धारकों के लिए स्वेच्छा से पाकिस्तान छोड़ने की समय सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया।

पाकिस्तान सरकार ने एसीसी धारकों और अवैध विदेशियों के लिए स्वेच्छा से देश छोड़ने की समय सीमा 31 मार्च तय की थी। यह पाकिस्तान से अवैध विदेशी नागरिकों की वापसी प्रक्रिया का दूसरा चरण है, इनमें अधिकांश अफगान नागरिक

शामिल हैं। इस निर्णय की आलोचना करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान से कहा है कि वह हजारों बिना दस्तावेज वाले अफगान नागरिकों को वापस भेजने से परहेज करे। हालांकि, इस्लामाबाद ने इन चिंताओं को खारिज कर दिया और याद दिलाया कि उसने लाखों अफगान शरणार्थियों के प्रति स्वेच्छा से अंतरराष्ट्रीय दायित्व पूरा किया है।

खान ने कहा, "हम यूएनएचसीआर से बंधे नहीं हैं। सबसे पहले, पाकिस्तान रिफ्यूजी कन्वेंशन का सदस्य नहीं है। इसलिए हमने पिछले 50 वर्षों से अफगान शरणार्थियों के लिए जो कुछ भी किया है, वह स्वेच्छा से किया है। जहां तक अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का सवाल है तो, हमने अफगानों को इस तरह का आतिथ्य प्रदान करके अपने हिस्से से अधिक काम किया है। हम उनका स्वागत करना जारी रखते हैं लेकिन उनके पासपोर्ट पर पाकिस्तानी वीजा होना चाहिए, और फिर उनका स्वागत किया जाएगा।"

अधिकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे पूरे देश में एसीसी धारकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करेंगे, जिसके तहत पाक-अफगान तोरखम सीमा से उनके बड़े पैमाने पर निर्वासन की शुरुआत की जाएगी।

पाकिस्तान अफगान शरणार्थियों को उनके देश भेजने का प्रक्रिया ऐसे समय में शुरू कर रहा है जब दोनों देशों के संबंध काफी तनावपूर्ण चल रहे हैं।

पाकिस्तान अफगान तालिबान पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और अन्य आतंकवादी समूहों को पाकिस्तान में अशांति फैलाने के लिए समर्थन देने का आरोप लगता रहा है। पाकिस्तान यह शक जता चुका है कि आतंकवादी और उग्रवादी शरणार्थियों के बीच छिपकर देश में आतंकवादी हमले करते हैं।

पाकिस्तान द्वारा 1.7 मिलियन से अधिक अफगान नागरिकों को देश से वापस भेजने के एकतरफा निर्णय को अफगान तालिबान शासन ने पूरा समर्थन नहीं दिया। काबुल ने इस्लामाबाद से पाकिस्तान से अफगान शरणार्थियों को धीरे-धीरे वापस भेजने की अपील की।

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा, "शरणार्थियों का सम्मान किया जाना चाहिए और उनकी वापसी क्रमिक और सम्मानजनक होनी चाहिए। हमारे देश में सुरक्षा संबंधी कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुछ अन्य समस्याएं हैं, जिनके कारण सभी शरणार्थियों के एक साथ आने के लिए तैयारी करना मुश्किल हो जाता है। उम्मीद है कि यह काम धीरे-धीरे लागू होगा।"

इजरायली सेना गाजा में और अंदर घुसी

इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में और घुसने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने राफाह के दक्षिण में तेल अल-सुल्तान इलाके को घेर लिया है।

इजरायली रक्षा बलों (आईडीएफ) के अनुसार, सैनिकों ने रातभर इस इलाके को घेरने के बाद कई आतंकवादियों को मार गिराया और हमास के कमांड और नियंत्रण केंद्र पर हमला किया।

सेना ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य दक्षिणी गाजा में सुरक्षा क्षेत्र का विस्तार करना और आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना है। सेना द्वारा जारी किए गए वीडियो में सैनिकों को टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के साथ इलाके में आगे बढ़ते हुए और क्षतिग्रस्त इमारतों में प्रवेश करते हुए दिखाया गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें राफाह से महिलाओं, बच्चों और पुरुषों को भागते हुए देखा गया है।

पीएम मोदी-लक्सन बैठक

न्यूजीलैंड में खालिस्तानी और भारत विरोधी तत्वों का उठा मुद्दा

■ बीएनटी न्यूज

भारत ने न्यूजीलैंड के सामने उसकी धरती पर सक्रिय कट्टरपंथी और चरमपंथी खालिस्तानी समूहों का मुद्दा उठाया, जो देश में राजनयिकों और बड़े भारतीय समुदाय के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं।

यह मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की उपस्थिति में हैदराबाद हाउस में दोनों पक्षों के बीच हुई चर्चा के दौरान उठा। लक्सन इस समय भारत दौरे पर हैं।

विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) जयदीप मजूमदार ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद मीडिया को बताया, "निश्चित रूप से, यह मुद्दा उठा। हम अपने मित्रों को उनके देशों में भारत विरोधी तत्वों की गतिविधियों और आतंकवाद को महिमामंडित करने, धमकी देने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अन्य लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं के गलत इस्तेमाल के बारे में सचेत करते हैं। न्यूजीलैंड की सरकार ने अतीत में भी हमारी चिंताओं को ध्यान में रखा है। आज भी हमें यही प्रतिक्रिया मिली।"

भारत-न्यूजीलैंड संयुक्त वक्तव्य में दोनों प्रधानमंत्रियों की तरफ से बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर सहमति

जताए जाने का उल्लेख किया गया।

इसमें कहा गया, "दोनों नेताओं ने न्यूजीलैंड में छात्रों सहित भारतीय समुदाय, भारत में न्यूजीलैंड के लोगों और भारत आने वाले आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर सहमति जताई।" उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की 'पूर्ण निंदा' दोहराई।

बयान के मुताबिक दोनों नेताओं ने सभी देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल, निरंतर, और ठोस कार्रवाई करने की जरूरत पर बल दिया।"

प्रधानमंत्री मोदी और पीएम लक्सन ने आतंकवाद के फंडिंग नेटवर्क, सुरक्षित ठिकानों को नष्ट करने, आतंकवाद के बुनियादी और ऑनलाइन ढांचे को नष्ट करने, आतंकवाद के अपराधियों को जल्द न्याय के कटघरे में लाने की अपील की।

दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय तंत्रों के माध्यम से आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करने में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की।

प्रतिबंधित अमेरिका स्थित कट्टरपंथी खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित कई देशों में अपने अलगाववादी एजेंडे को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। यह एक तथाकथित 'जनमत संग्रह' आयोजित कर रहा है जिसमें एक स्वतंत्र सिख देश की मांग की जा रही है।

'मेरे राष्ट्रप्रथम विश्वास जैसी ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट भावना, चीन के साथ हमारी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा' : मोदी

■ बीएनटी न्यूज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी पॉडकास्टर लैक्स फ्रिडमैन के कार्यक्रम में शामिल हुए। तीन घंटे से भी अधिक समय तक चलने वाले पॉडकास्ट में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपने रिश्ते के बारे में चर्चा की। इस दौरान उन्होंने ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट भावना की तारीफ की और चीन के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की वकालत की।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताते हुए पीएम मोदी ने एक वाकया याद किया। उन्होंने बताया, 'ूस्टन में हमारा एक कार्यक्रम था, हाउडी मोदी। मैं और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों वहां पर थे। भारतीय प्रवासी बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे। राजनीतिक रैली के लिए इतनी ज्यादा भीड़ असाधारण थी। हम दोनों ने भाषण दिए और वह नीचे बैठकर मेरी बात सुनते रहे। अब, यह उनकी विनम्रता है। जब मैं मंच से बोल रहा था, तब अमेरिका के राष्ट्रपति दर्शकों में बैठे थे, यह उनकी ओर से एक उल्लेखनीय इशारा था। अपना भाषण समाप्त करने के बाद, मैं नीचे उतरा और जैसा कि हम सभी जानते हैं, अमेरिका में सुरक्षा बेहद सख्त और गहन है। मैं उनका शुक्रिया अदा करने गया और सहजता से कहा, "अगर आपको कोई आपत्ति न हो, तो हम स्टेडियम का एक चक्कर क्यों न लगा लें? यहां बहुत सारे लोग हैं। चलो चलें, हाथ हिलाएं और उनका अभिवादन करें।"

उन्होंने बताया, "अमेरिकी जीवन में, राष्ट्रपति के लिए हजारों की भीड़ में चलना लगभग असंभव है, लेकिन बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के, वह सहमत हो गए और मेरे साथ चलने लगे। उनका पूरा सुरक्षा दल चौंक गया, लेकिन मेरे लिए वह क्षण वास्तव में दिल को छू लेने वाला था। इसने मुझे दिखाया कि इस आदमी में साहस है। वह अपने फैसले खुद लेता है, लेकिन उसने उस पल में मुझ पर और मेरे नेतृत्व पर इतना भरोसा किया कि वह मेरे साथ भीड़ में चला गया। यह आपसी विश्वास की भावना थी, हमारे बीच एक मजबूत बंधन था जिसे मैंने उस दिन वास्तव में देखा और जिस तरह से मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को उस दिन हजारों लोगों की भीड़ में बिना सुरक्षा के पूछे चलते हुए देखा, वह वास्तव में आश्चर्यजनक था।"

डोनाल्ड ट्रंप के दृढ़ता की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "जब हाल ही में अभियान के दौरान उन्हें गोली मारी गई थी, तो मैंने उसी दृढ़ निश्चयी और दृढ़ राष्ट्रपति ट्रंप को देखा, जो उस स्टेडियम में मेरे साथ हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे। गोली लगने के बाद भी, वे अमेरिका के लिए अडिग रहे। उनका जीवन उनके राष्ट्र के लिए था। उनके प्रतिबिंब में उनकी अमेरिका फर्स्ट भावना दिखाई दी, ठीक वैसे ही जैसे मैं राष्ट्र प्रथम में विश्वास करता हूं। मैं भारत प्रथम के लिए खड़ा हूं और इसलिए हम इतने अच्छे से जुड़ते हैं।"

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपने रिश्ते के बारे में उन्होंने बताया, "भारत और चीन के बीच संबंध कोई नई बात नहीं है। दोनों देशों की संस्कृतियां और सभ्यताएं प्राचीन हैं। आधुनिक दुनिया में भी, वे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आप ऐतिहासिक रिकॉर्ड देखें, तो सदियों से भारत और चीन एक दूसरे से सीखते आए हैं। साथ मिलकर, उन्होंने हमेशा किसी न किसी तरह से वैश्विक भलाई में योगदान दिया है। पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि एक समय पर भारत और चीन अकेले दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा थे। भारत का योगदान इतना बड़ा था। अगर हम सदियों पीछे देखें, तो हमारे बीच संघर्ष का कोई वास्तविक इतिहास नहीं है। यह हमेशा एक दूसरे से सीखने और एक दूसरे को समझने के बारे में रहा है। एक समय में, चीन में बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव था, और वह दर्शन मूल रूप से यहीं से आया था।"

● **अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीब तीन घंटे का लंबा पॉडकास्ट शेयर किया। अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ उनका यह पॉडकास्ट चर्चा का विषय बना हुआ है। बातचीत के दौरान, पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ अपने सौहार्दपूर्ण संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने ट्रंप की 'विनम्रता' की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ट्रंप अपने पहले कार्यकाल की तुलना में दूसरे कार्यकाल के लिए कहीं अधिक तैयार दिखाई दिए।**

उन्होंने कहा, "हमारे रिश्ते भविष्य में भी ऐसे ही मजबूत बने रहने चाहिए। इसे आगे भी बढ़ना चाहिए। बेशक, मतभेद स्वाभाविक हैं। जब दो पड़ोसी देश होते हैं, तो कभी-कभी असहमति होना लाजिमी है। यहां तक कि एक परिवार के भीतर भी, सब कुछ हमेशा सही नहीं होता। लेकिन हमारा ध्यान यह सुनिश्चित करने पर है कि ये मतभेद विवाद में न बदल जाएं। हम इसी दिशा में सक्रिय रूप से काम करते हैं। कलह के बजाय, हम संवाद पर जोर देते हैं, क्योंकि केवल संवाद के माध्यम से ही हम एक स्थिर सहकारी संबंध बना सकते हैं जो दोनों देशों के सर्वोत्तम हितों की सेवा करता है।" हालिया सीमा विवाद के कारण भारत और चीन के बीच बढ़े तनाव पर पीएम मोदी ने कहा, "राष्ट्रपति शी के साथ मेरी हालिया बैठक के बाद, हमने सीमा पर सामान्य स्थिति में वापसी देखी है। हम अब 2020 से पहले की स्थितियों को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से, विश्वास, उत्साह और ऊर्जा वापस आ जाएगी। लेकिन निश्चित रूप से, इसमें कुछ समय लगेगा, क्योंकि पांच साल का अंतराल हो गया है। हमारा सहयोग सिर्फ फायदेमंद ही नहीं है, यह वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए भी जरूरी है। और चूंकि 21वीं सदी एशिया की सदी है, इसलिए हम चाहते हैं कि भारत और चीन स्वस्थ और स्वाभाविक तरीके से प्रतिस्पर्धा करें। प्रतिस्पर्धा कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन इसे कभी भी संघर्ष में नहीं बदलना चाहिए।"

यूएन में भारत की पाकिस्तान को दो टूक

कश्मीर पर बड़बड़ाने से सीमा पार आतंकवाद को उचित नहीं ठहरा सकते

■ बीएनटी न्यूज

पाकिस्तान की 'कट्टर मानसिकता' की निंदा करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने इस्लामाबाद से कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर को लेकर राग अलापने से सीमा पार आतंकवाद को उचित नहीं ठहराया जा सकता या इस क्षेत्र के भारत का अभिन्न अंग होने की वास्तविकता को नहीं बदला जा सकता।

वे पाकिस्तान की पूर्व विदेश सचिव तहमीना जंजुआ द्वारा इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए महासभा की एक अनौपचारिक बैठक के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे।

हरीश ने कहा, जैसा कि उनकी आदत है, पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव ने आज भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का अनुचित संदर्भ दिया है। बार-बार संदर्भ देने से न तो उनका दावा मान्य होगा और न ही सीमा पार आतंकवाद को लेकर उनकी प्रैक्टिस को उचित ठहराया जा सकेगा।

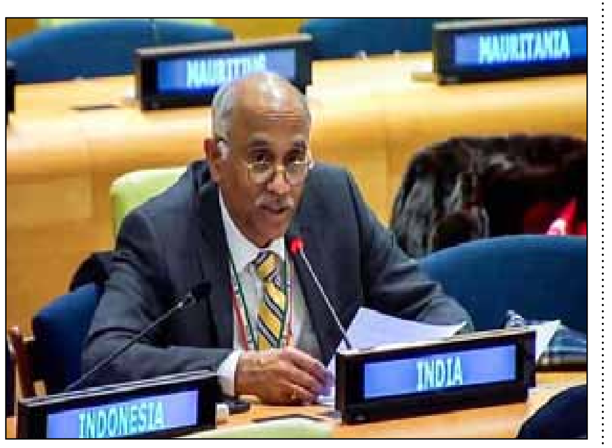

उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा, इस देश की कट्टर मानसिकता और कट्टरता का रिकॉर्ड जगजाहिर है।

उन्होंने कहा, "ऐसे प्रयास इस वास्तविकता को नहीं बदलेंगे कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा।"

जब कश्मीर की बात आती है तो पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में एक आवाज बनकर रह जाता है।

जब भी उसके प्रतिनिधियों को बोलने का मौका मिलता है, तो वह कश्मीर का मुद्दा उठाता है, लेकिन किसी अन्य देश ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। 2017 से 2019 तक पाकिस्तान की विदेश सचिव रहीं जंजुआ ने बैठक में बतौर आमंत्रित सदस्य अपनी बात रखी।

उन्होंने कश्मीर को गाजा से जोड़ने की कोशिश की – जो पाकिस्तान की एक चाल है – और जोर देकर कहा, "इस्लामोफोबिया कब्जे वाले क्षेत्रों, जैसे कि भारतीय कब्जे वाले कश्मीर और फिलिस्तीन में मुसलमानों की भयानक हत्याओं का एक महत्वपूर्ण कारण है।"

उन्होंने परोक्ष रूप से "लव जिहाद" और "गौरक्षकों" से जुड़ी "लिंचिंग" का भी उल्लेख किया।

अवामी लीग की बांग्लादेश में कोई जगह नहीं : यूनुस सरकार

■ बीएनटी न्यूज

मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के एक प्रमुख सलाहकार ने ऐलान किया कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी को बांग्लादेश में कोई जगह नहीं दी जाएगी।

स्थानीय मीडिया ने बताया कि दिसंबर में राष्ट्रीय चुनाव कराने के बारे में बोलते हुए सूचना एवं प्रसारण सलाहकार महफूज आलम ने अवामी लीग को विदेश से लाई गई एक 'शक्ति' कहा।

देश के प्रमुख बंगाली दैनिक प्रथम आलो ने आलम के हवाले से कहा, "अवामी लीग कोई घरेलू ताकत नहीं है... बल्कि यह अनिवार्य रूप से विदेश से लाई गई ताकत है। इस पतंग (अवामी लीग) की डोर दिल्ली में है। इस पतंग को अब बांग्लादेश में उड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

यूनुस ने हाल ही में कहा था कि अंतरिम सरकार की अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना नहीं है। पिछले महीने एक अन्य बयान में उन्होंने कहा था

कि अवामी लीग को यह तय करना है कि वह चुनाव लड़ेगी या नहीं, चाहे वे कभी भी हों।

स्थानीय मीडिया के मुताबिक ब्रिटिश सार्वजनिक सेवा प्रसारक को दिए इंटरव्यू में यूनुस ने कहा, "उन्हें (अवामी लीग को) यह तय करना है कि वे ऐसा करना चाहते हैं या नहीं, मैं उनके लिए फैसला नहीं कर सकता। चुनाव आयोग तय करता है कि चुनाव में कौन भाग लेगा।"

यूनुस के बयान उनके पिछले बयान से अलग थे जब उन्होंने कहा था कि अवामी लीग का बांग्लादेश की राजनीति में 'कोई स्थान नहीं' है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरिम सरकार के विरोधाभासी बयान अवामी लीग को चुनावी राजनीति से दूर रखने की एक साजिश को दर्शाते हैं।

पीएम मोदी की 'सकारात्मक टिप्पणियों' से चीन खुश

■ बीएनटी न्यूज

चीन ने कहा कि वह बीजिंग-नई दिल्ली संबंधों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया 'सकारात्मक टिप्पणियों' की 'सराहना' करता है।

अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ बातचीत में, प्रधानमंत्री मोदी ने उन प्रयासों पर जोर दिया जो यह सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे हैं कि दोनों देशों के बीच मतभेद संघर्ष में न बदल जाएं।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए भारत और चीन के बीच सहयोग जरूरी है। उन्होंने संघर्ष के बजाय स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की वकालत की।

पीएम मोदी ने कहा, "एक स्थिर और सहयोगात्मक संबंध बनाने के लिए संवाद महत्वपूर्ण है, जिससे दोनों देशों को लाभ हो।"

चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने बीजिंग में नियमित मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, "हम चीन-भारत संबंधों पर प्रधानमंत्री मोदी की हाल की सकारात्मक टिप्पणियों की सराहना करते

हैं। पिछले अक्टूबर में, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजान में सफलतापूर्वक मुलाकात की और चीन-भारत संबंधों को सुधारने के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान किया।'

निंग ने कहा, "दोनों पक्षों ने दोनों देशों के नेताओं की साझा सहमति को ईमानदारी से लागू किया है, सभी स्तरों पर आदान-प्रदान और व्यावहारिक सहयोग को मजबूत किया है और कई सकारात्मक परिणाम हासिल किए हैं।"

प्रवक्ता ने कहा, "दोनों देशों को एक-दूसरे को समझना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। यह दोनों देशों के 2.8 बिलियन से अधिक लोगों के मौलिक हितों के अनुरूप है, क्षेत्रीय देशों की साझा अपेक्षाओं के अनुरूप है, वैश्विक दक्षिण के उत्कृष्ट विकास की ऐतिहासिक प्रवृत्ति के अनुरूप है, और विश्व शांति, स्थिरता, विकास और समृद्धि के लिए अनुकूल है।"

बीजिंग ने यह भी कहा कि चीन हमेशा मानता है कि दोनों देशों को ऐसे भागीदार बनना चाहिए जो एक-दूसरे की सफलता में योगदान दें।

निंग ने कहा, "चीन दोनों देशों के नेताओं की साझा सहमति को पूरी तरह से लागू करने के लिए भारत के साथ काम करने को तैयार है।"

फ्रिडमैन के साथ बातचीत के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने माना कि पड़ोसियों के बीच मतभेद स्वाभाविक हैं लेकिन उन्होंने विवादों को बढ़ने से रोकने की जरुरत पर बल दिया।

ट्रेन हाईजैक : क्वेटा पहुंचे पीएम शहबाज शरीफ, बीएलए ने सेना के दावे को किया खारिज

■ बीएनटी न्यूज

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान प्रांत का दौरा किया जहां अलगाववादी चरमपंथियों ने एक ट्रेन पर हमला कर 400 से अधिक यात्रियों को बंधक बना लिया था।

सरकार ने बताया कि शरीफ क्वेटा के एक दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्हें क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी जाएगी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चरमपंथियों से बचाए गए कई लोग क्वेटा पहुंच हैं।

प्रधानमंत्री शरीफ ने एक्स पर एक पोस्ट में हमले की निंदा की और कहा, "ऐसी कायरतापूर्ण हरकतें पाकिस्तान के शांति के संकल्प को हिला नहीं पाएंगी।" शरीफ का दौरा ऐसे समय में हुआ जब अलगाववादी ग्रुप बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने सेना के इस दावे को खारिज कर दिया कि संघर्ष समाप्त हो गया है। उसने कहा कि 'लड़ाई' जारी है और उसने अभी भी लोगों को बंधक बनाया हुआ है।

पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि 300 यात्रियों को बचा लिया गया. सेना के प्रवक्ता ने कहा कि यात्रियों को बचाने के लिए चलाए गए उसके अभियान में 33 चरमपंथियों की मौत हो गई।

सेना के अनुसार, कुल 21

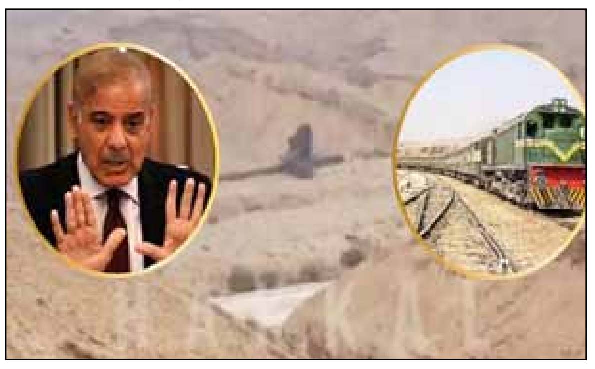

बंधकों और चार सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई। हालांकि बीएलए ने कहा कि 50 बंधकों को मार दिया गया।

चरमपंथियों ने मंगलवार दोपहर को बलूचिस्तान प्रांत में क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस पर हमला कर यात्रियों को बंधक बना लिया था। ट्रेन में 400 यात्री सवार थे। बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) इसकी जिम्मेदारी ली जिसका कहना था कि अगर सरकार ने 48 घंटों के अंदर बलूच राजनीतिक कैदियों को नहीं छोड़ा तो वो सभी बंधकों को मार देंगे। बीएलए ने कहा कि पाकिस्तान ने जिन लोगों को बचाने का 'दावा' किया है, उन्हें वास्तव में समूह ने ही छोड़ा था।

बीएलए बलूचिस्तान की आजादी चाहता है। यह कई जातीय विद्रोही समूहों में से सबसे बड़ा है, जिसने दशकों से पाकिस्तान सरकार से लड़ाई लड़ी है। संगठन का कहना है कि सरकार बलूचिस्तान के समृद्ध गैस और खनिज संसाधनों का अनुचित तरीके से दोहन कर रही है।

● **प्रधानमंत्री शरीफ ने एक्स पर एक पोस्ट में हमले की निंदा की और कहा, ऐसी कायरतापूर्ण हरकतें पाकिस्तान के शांति के संकल्प को हिला नहीं पाएंगी।**

बीएलए को पाकिस्तान, ईरान, चीन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ ने आतंकी संगठन घोषित किया है।

बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। इसे भू-आर्थिक और भू-रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है फिर भी यह अशांत रहता है। बलूचिस्तान को प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर माना जाता है। इसके बावजूद विकास की दौड़ में सबसे पीछे रह गया है।

नेशनल असेंबली में विपक्षी आलोचना पर पाक सरकार ने साधी 'चुप्पी'

बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस अपहरण की घटना को पाकिस्तान की संघीय सरकार की तीखी आलोचना हो रही है लेकिन उसने इस मुद्दे पर खामोश रहने की रणनीती बनाई है। नेशनल असेंबली में विपक्ष के हमलों के बीच सरकार ने चुप्पी साधे रखी।

गठबंधन सरकार ने अपहरण की घटना का कोई भी उल्लेख करने से परहेज किया। हालांकि विपक्षी नेता उमर अयूब खान ने सरकार की प्रतिक्रिया की आलोचना की थी।

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी और कानून मंत्री आजम नजीर तरार सहित प्रमुख पाकिस्तानी मंत्री सदन में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई नीतिगत बयान देने से परहेज किया।

बोलन जिले में जाफर एक्सप्रेस पर बड़े पैमाने पर हमले के बाद बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के मजीद ब्रिगेड के चरमपंथियों और पाकिस्तानी सेना के बीच टकराव आखिरकार 24 घंटे से अधिक समय बाद बुधवार शाम को खत्म हुआ।

सेना ने दावा किया कि हमलावरों को बेअसर करने और बंधकों को बचाने का अभियान सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है।

एक विश्वसनीय सुरक्षा सूत्र ने बताया, "ऑपरेशन समाप्त हो गया है, घटनास्थल को खाली करा लिया गया है। सभी बंधकों को रिहा कर दिया गया है। कुल 346 लोगों को बचाया गया। 50 आतंकवादियों को मार गिराया गया।"

अधिकारियों ने यह भी खुलासा किया कि आतंकवादी हमले के दौरान महिलाओं और बच्चों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे।

क्वेटा से पेशावर जा रही इस ट्रेन को बीएलए के उग्रवादियों ने हाईजैक कर 400 से ज्यादा यात्रियों को बंधक बना लिया था।

हालांकि, संकट की गंभीरता के बावजूद, संघीय सरकार ने इस मामले को सुलझाने में कोई तत्परता नहीं दिखाई।

नेशनल असेंबली सत्र के दौरान, उमर अयूब खान ने मांग की कि जाफर एक्सप्रेस अपहरण पर बहस के लिए नियमित कार्यवाही को निलंबित किया जाए।

हालांकि, पीपीपी के अब्दुल कादिर पटेल, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, ने अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय प्रश्नकाल को आगे बढ़ाया।

पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक 'डॉन' की रिपोर्ट के अनुसार, इस निर्णय का पीटीआई सांसदों ने जोरदार विरोध किया। उन्होंने विरोध में नारे लगाने के बाद सदन से वॉकआउट कर दिया।

प्रश्नकाल पूरा होने के बाद, पीटीआई सदस्य सदन में वापस आए, जहां उमर अयूब ने सरकार की निष्क्रियता की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा, "बलूचिस्तान जल रहा है और सरकार हमेशा की तरह काम कर रही है।"

अनौपचारिक बातचीत में लगे ट्रेजरी सदस्यों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी गंभीरता की कमी आतंकवाद के प्रति सरकार की उदासीनता को दर्शाती है।

जाफर एक्सप्रेस हमले को 'एक बड़ी खुफिया विफलता' बताते हुए खान ने सवाल उठाया कि कैसे दर्जनों आतंकवादी खुफिया एजेंसियों की नजर में आए बिना दिनदहाड़े इकट्ठा होकर ऑपरेशन को अंजाम देने में कामयाब हो गए।

खान ने आरोप लगाया कि देश में 13 खुफिया एजेंसियों का प्राथमिक ध्यान आतंकवादियों का पता लगाने के बजाय विपक्षी नेताओं को निशाना बनाना था।

दुनिया जानती है वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहां है

■ बीएनटी न्यूज

भारत ने पाकिस्तान के इस आरोप को खारिज कर दिया है कि पड़ोसी देश में भड़की जातीय हिंसा के पीछे नई दिल्ली का हाथ है। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने कहा पाकिस्तान को अपने अंदर झांकना चाहिए, दुनिया जानती है कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहां है।

विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में कहा, "हम पाकिस्तान के निराधार आरोपों को दृढ़ता से खारिज करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहां है। पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं और विफलताओं के लिए दूसरों पर उंगली उठाने और दोष मढ़ने के बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए।"

सरकार की यह प्रतिक्रिया तब आई जब एक वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी ने भारत पर 'आतंकवाद को प्रायोजित करने' और अपने पड़ोसी देशों को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

दरअसल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने क्वेटा से पेशावर की यात्रा के दौरान जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था। सुरक्षाबलों और चरमपंथियों के बीच लगभग 30 घंटे तक चले

संघर्ष चला।

पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि 300 यात्रियों को बचा लिया गया। सेना के प्रवक्ता ने कहा कि यात्रियों को बचाने के लिए चलाए गए उसके अभियान में 33 चरमपंथियों की मौत हो गई।

सेना के अनुसार, कुल 21 बंधकों और चार सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई।

पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने कहा कि ट्रेन पर हमले में विदेशी ताकत के हाथ होने का आरोप लगाया हालांकि सीधे तौर पर भारत का नाम नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि विद्रोही ट्रेन की घेराबंदी के दौरान अफगानिस्तान में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में थे। प्रवक्ता से जब पूछा गया कि क्या पाकिस्तान ने बीएलए गतिविधि के लिए अतीत में भारत को दोषी ठहराने की अपनी नीति बदल दी है, तो उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ उसके आरोप आज भी कायम हैं।

वैश्विक अस्थिरता के दौर में 6-7 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर शानदार : बिड़ला

■ बीएनटी न्यूज

आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के दौर में देश तेजी से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है।

बिड़ला के मुताबिक, देश की जीडीपी का 6-7 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ना एक बड़ी उपलब्धि है।

बिड़ला ने एक मीडिया इवेंट में कहा, "भारत एक ऐसे चरण में है जहां विश्व में देश की स्वीकार्यता बढ़ रही है।"

साथ ही कहा कि वह भारत के भविष्य को लेकर न केवल आशान्वित हैं बल्कि आश्वस्त भी हैं।

बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन ने आगे, "नीतिगत स्थिरता, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास और अच्छा बिजनेस माहौल, भारत की लंबी अवधि की वृद्धि दर को बढ़ा रहे हैं।"

हालांकि, बिड़ला ने ट्रंप की ओर से ट्रेड टैरिफ लगाए जाने को लेकर कोई बातचीत नहीं की।

हाल ही में आई मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा टैरिफ की घोषणा के चलते पैदा हुई वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत को एशिया में सबसे अच्छी स्थिति वाला देश बाताया था। इसकी वजह देश का गुड्स एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेश्यो कम होना और आर्थिक आधार का मजबूत होना था।

बिड़ला आगे कहा कि ग्रुप के यूएस ऑपरेशंस वहां के स्थानीय बाजार पर केंद्रित हैं। इस वजह से अमेरिका और भारत के बीच आयात-निर्यात में होने वाले बदलाव का उन ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं होगा।

बिड़ला ने आदित्य बिड़ला समूह के पेंट, ज्वेलरी और कॉस्मेटिक जैसी इंडस्ट्री में नए निवेश के बारे में बातचीत भी की। बिड़ला ने कहा कि कंपनी सावधानी से सेक्टरों का चयन कर रही है जहां उसे सफलता मिलने की प्रबल संभावना होती है और हम स्केल और मार्केट लीडरशीप पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, समूह ने पेंट्स व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए अपने मौजूदा व्हाइट सीमेंट वितरण नेटवर्क का उपयोग किया।"

उनका मानना है कि अगली पीढ़ी के लिए नेतृत्व की भूमिका में आने से पहले अपनी पहचान विकसित करने के लिए व्यवसाय से बाहर अनुभव प्राप्त करना आवश्यक है।

सेंट्रल बैंकिंग, लंदन ने आरबीआई को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड के लिए चुना

■ बीएनटी न्यूज

यूनाइटेड किंगडम (यूके) के लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग की ओर से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को बधाई दी।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरबीआई की पोस्ट को कोट करते हुए लिखा कि यह सराहनीय उपलब्धि है, जो शासन में इनोवेशन और दक्षता को दिखाती है।

उन्होंने आगे लिखा कि डिजिटल इनोवेशन भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत बना रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन सशक्त हो रहा है।

आरबीआई को 'प्रवाह' और 'सारथी' नामक अपनी डिजिटल पहलों के लिए सम्मानित किया गया, जिन्हें केंद्रीय बैंक की इन-हाउस डेवलपर टीम द्वारा विकसित किया गया था।

पुरस्कार समिति ने स्वीकार किया कि कैसे इन डिजिटल पहलों ने कागज-आधारित सबमिशन के उपयोग को कम कर दिया है, जिससे आरबीआई की आंतरिक और बाहरी प्रक्रियाओं में बदलाव आया है।

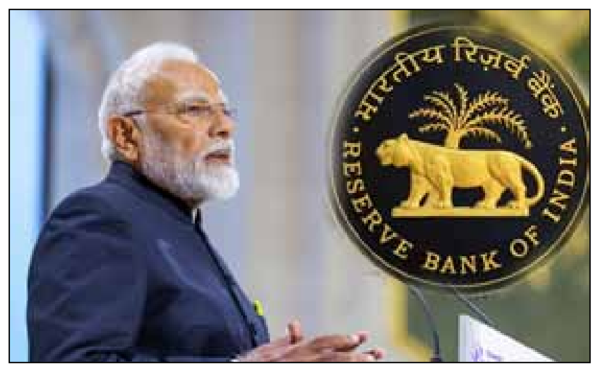

जनवरी 2023 में लॉन्च किए गए सारथी ने आरबीआई के आंतरिक वर्कफ्लो को डिजिटल कर दिया, जिससे कर्मचारी सुरक्षित रूप से दस्तावेजों को जमा और साझा कर सकते हैं। इससे रिकॉर्ड मैनेजमेंट में सुधार आया है। साथ ही कर्मचारी रिपोर्ट और डैशबोर्ड के माध्यम से डेटा विश्लेषण कर सकते हैं।

सारथी ने प्रक्रियाओं को स्वचालित करके आरबीआई को परिचालन दक्षता बढ़ाने में मदद की है। जहां पहले आरबीआई के कई विभाग मैनुअल और डिजिटल प्रक्रियाओं के खंडित मिश्रण पर निर्भर थे, वहीं सारथी केंद्रीय बैंक की जानकारी के लिए एक यूनिफाइड ग्लोबल रिपॉजिटरी बनाता है।

मई 2024 में प्रवाह लॉन्च किया गया, जो बाहरी यूजर्स के लिए आरबीआई को विनियामक आवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक डिजिटल माध्यम है।

पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत और संसाधित किए गए दस्तावेजों को सारथी डेटाबेस में प्लग किया जाता है, जहां उन्हें केंद्रीकृत साइबर सुरक्षा प्रणालियों और डिजिटल ट्रैकिंग के साथ आरबीआई कार्यालयों में डिजिटल रूप से संभाला जा सकता है।

प्रवाह ने अब तक 70 से अधिक विभिन्न विनियामक अनुप्रयोगों को डिजिटल बना दिया है, यह आरबीआई के नौ विभागों के काम में मदद करता है। मई में इसके लॉन्च और 2024 के अंत के बीच, इस सिस्टम के माध्यम से 2,000 से अधिक आवेदन दायर किए गए थे, जो मासिक आवेदनों में 80 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इसकी वजह पोर्टल का उपयोग में आसान होना है।

तमिलनाडु को पीएलआई स्कीम से हुआ सबसे अधिक फायदा

■ बीएनटी न्यूज

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि तमिलनाडु प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक के रूप में उभरा है।

राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में आए प्रोजेक्ट्स में भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त हुआ है।

चेन्नई सिटीजन फोरम के द्वारा आयोजित एक इवेंट में बोलते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने उन सभी दावों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा जाता है कि केंद्र सरकार ने फंडिंग के मामले में तमिलनाडु की

अनदेखी की है।

उन्होंने कहा कि राज्य में कई बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई है।

वित्त मंत्री ने कहा, "तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और ऑटोमोबाइल में पीएलआई योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी है।"

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और ऑटोमोबाइल में पीएलआई योजना के तहत सबसे अधिक स्वीकृतियां हासिल की हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "जिन 27 कंपनियों को केंद्र से मंजूरी मिली है, उनमें से सात तमिलनाडु से हैं।"

वित्त मंत्री सीतारमण के अनुसार, पीएलआई योजना से लाभान्वित होने वाली लगभग 25 प्रतिशत कंपनियां राज्य में स्थित हैं।

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि तमिलनाडु भारत के दो प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टरों में से एक का घर है, जबकि दूसरा गुजरात में स्थित है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने आगे कहा कि तमिलनाडु ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट निर्माण के लिए पीएलआई इंसेंटिव में दूसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए पीएलाई योजना के तहत स्वीकृत 82 आवेदनों में से 46 तमिलनाडु से हैं। एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी निर्माण के लिए पीएलआई योजना के तहत राज्य की चार कंपनियों को मंजूरी मिली है।"

वित्त मंत्री ने कहा, केंद्र के सहयोग से तूतीकोरिन में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट की योजना बनाई जा रही है।

राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के विकास के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 1,303 किलोमीटर नई रेलवे लाइनें जोड़ी गई हैं।

स्टार हेल्थ को टैक्स अथॉरिटीज से मिला 49 करोड़ रुपये का जीएसटी डिमांड नोटिस

■ बीएनटी न्यूज

स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को कई राज्यों के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) अथॉरिटीज से 25 टैक्स डिमांड नोटिस प्राप्त हुए हैं।

जुमार्ने सहित इन नोटिस में 49 करोड़ रुपये के टैक्स की मांग की गई है। यह सभी टैक्स नोटिस कंपनी के हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी किए गए हैं।

अधिकारियों ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस पर आरोप लगाया है कि कंपनी को-इंश्योरेंस से संबंधित कुछ लेनदेन पर जीएसटी का भुगतान करने में विफल रही है।

कंपनी द्वारा किए गए उल्लंघनों में वैधानिक दस्तावेजों में इन लेनदेन का

खुलासा न करना और ऐसी सेवाओं के लिए चालान जारी करने में विफलता भी शामिल है।

हरियाणा में स्टार हेल्थ के कार्यालय को 4.9 करोड़ रुपये के पांच टैक्स डिमांड मिले हैं। ये आदेश गुरुग्राम में जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज के एडिशनल कमिश्नर द्वारा जारी किए गए थे।

इसी तरह कंपनी के दिल्ली कार्यालय को 4.7 करोड़ रुपये के चार टैक्स डिमांड नोटिस दिए गए हैं। महाराष्ट्र के जोनल कार्यालय से पांच नोटिस के जरिए सबसे ज्यादा 19.4 करोड़ रुपये की टैक्स की डिमांड की गई है।

ये नोटिस मुंबई ईस्ट, अंधेरी ईस्ट और मुंबई साउथ-वेस्ट के जीएसटी अधिकारियों ने जारी किए हैं। तमिलनाडु में कंपनी को चेन्नई नॉर्थ जीएसटी ऑफिस से कुल 16.2 करोड़ रुपये के पांच टैक्स नोटिस मिले हैं।

तेलंगाना कार्यालय को भी 3.8 करोड़ रुपये की राशि के पांच टैक्स नोटिस प्राप्त हुए हैं। वहीं, कर्नाटक कार्यालय को 12.8 लाख रुपये की मांग वाला एक टैक्स नोटिस प्राप्त हुआ है।

स्टार हेल्थ ने कहा है कि कानूनी सलाहकार की सलाह के आधार पर वह इन टैक्स डिमांड नोटिस को चुनौती देने के लिए अपील दायर करेगी। कंपनी इस मामले को सुलझाने के लिए उचित कानूनी कदम उठा रही है।

सोनभद्र में 309 महिलाओं को दिए सौर चूल्हे

■ बीएनटी न्यूज

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 309 महिलाओं में 'सूर्य नूतन' चूल्हा के तहत सौर चूल्हे वितरित किए। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से संवाद भी किया।

हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर साल 2017 में सूर्य नूतन चूल्हा कार्यक्रम चलाया गया था।

किचन में क्रांति ला रहे सोलर कुकटॉप से ग्रीन और क्लीन कुकिंग को नया आयाम मिल रहा है। यह मोदी सरकार की इच्छाशक्ति और देश में ऊर्जा क्रांति के लिए किए जा रहे उपायों का भी प्रतीक है।

हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "सोनभद्र में मुझे लगभग 309 बहनों को सूर्य नूतन चूल्हा प्रदान करने और लाभार्थियों से संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ। सोलर चूल्हे के इनोवेशन का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में किया था और नया भारत 2023 में एक रिमार्केबल

सॉल्यूशन के साथ खड़ा हो गया।"

उन्होंने लिखा, "किचन में क्रांति ला रहा सोलर कुकटॉप ग्रीन और क्लीन कुकिंग को नया आयाम दे रहा है। यह मोदी सरकार की इच्छाशक्ति और देश में ऊर्जा क्रांति के लिए किए जा रहे उपायों का भी प्रतीक है।"

केंद्रीय मंत्री ने लिखा, "इको फ्रेंडली और यूजर फ्रेंडली यह चूल्हा एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए थर्मल स्टोरेज मटेरियल में सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को एकत्र करता है और एकत्रित ऊर्जा को खाना पकाने के लिए रसोई के अंदर उपयोग किया जाता है।

यह चूल्हा हर मौसम में दिन और रात खाना बनाने में सक्षम है। रसोई में खाना पकाने के दौरान यह डिस्चार्ज होने के साथ चार्ज भी हो सकता है।"

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर 25 सितंबर 2017 को इंडियन ऑयल तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक स्वदेशी सोलर कुक टॉप 'सूर्य नूतन' विकसित किया।

यह एक स्थान पर स्थापित, रिचार्जेबल और रसोई से हमेशा जुड़ी हुई एक इनडोर सोलर कुकिंग प्रणाली है। यह सूर्य की रोशनी से चार्ज करते समय ऑनलाइन कुकिंग मोड प्रदान करता है जो सिस्टम की दक्षता को अधिकतम करता है और सूर्य से ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग सुनिश्चित करता है।

2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में ऊर्जा की होगी अहम भूमिका

■ बीएनटी न्यूज

2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में ऊर्जा की अहम भूमिका होगी और पर्याप्त ट्रांसमिशन सिस्टम की उपलब्धता से ऊर्जा उत्पादन का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। यह बयान केंद्रीय ऊर्जा और आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने दिया।

मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान (एनईपी) में 2023 से 2032 की अवधि के दौरान देश में जोड़े जाने वाले आवश्यक ट्रांसमिशन सिस्टम का विवरण दिया गया है, जो देश में बिजली की मांग में वृद्धि और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के अनुरूप है।

एनईपी-ट्रांसमिशन के

अनुसार, 10 वर्ष की अवधि (2023 से 2032) के दौरान लगभग 1.91 लाख सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) की ट्रांसमिशन लाइनें और 1,274 जीवीए (गीगा वोल्ट एम्पीयर) की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता जोड़ने की योजना है।

एनईपी-ट्रांसमिशन को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा तैयार किया गया है। इसमें वर्ष 2031-32 तक की ट्रांसमिशन योजना को कवर किया गया है।

उच्च स्तरीय बैठक में ट्रांसमिशन में नई टेक्नोलॉजीज और साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी बातचीत की गई।

केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करने के लिए उचित कार्रवाई करें और लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दें।

सरकार ने पिछले महीने बताया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में औसत बिजली आपूर्ति 2014 में 12.5 घंटे से बढ़कर 2025 में 22.6 घंटे हो गई है और शहरी क्षेत्रों में इस वर्ष 23.4 घंटे हो गई है।

मनोहर लाल ने कहा कि हमारा लक्ष्य सभी को हर समय बिजली उपलब्ध कराना है और देश भर में शत-प्रतिशत घरों तक बिजली पहुंचाना है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जीवाश्म आधारित बिजली क्षमता 2014 में 168 गीगावाट से बढ़कर जनवरी 2025 में 246 गीगावाट हो गई है, जो लगभग 46 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। उन्होंने आगे कहा कि गैर-जीवाश्म आधारित बिजली क्षमता 2014 में लगभग 80 गीगावाट से बढ़कर 2025 में लगभग 220 गीगावाट (31 जनवरी तक) हो गई है, जो लगभग 180 प्रतिशत की वृद्धि है।

अजंता फार्मा के सह-संस्थापक और उपाध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल को 'काउंसलर ऑफ द ईयर' पुरस्कार से किया सम्मानित

■ बीएनटी न्यूज

मुंबई में युगांडा के मानद वाणिज्य दूत और एक प्रसिद्ध परोपकारी व्यक्ति मधुसूदन अग्रवाल को हाल ही में 'काउंसलर ऑफ द ईयर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें मानद काउंसलर कॉर्प्स डिप्लोमैटिक-इंडिया (एचसीसीडी) द्वारा दिया गया।

अग्रवाल अजंता फार्मा के सह-संस्थापक और उपाध्यक्ष हैं। वह एचसीसीडी मुंबई के महासचिव और एचसीसीडी इंडिया के निदेशक भी हैं। उन्हें भारत-युगांडा संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान, कूटनीति और सामाजिक कल्याण के लिए समर्पण, और मानवीय प्रयासों को मान्यता देते हुए यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला।

अग्रवाल ने इस पुरस्कार को लेकर कहा, "एचसीसीडी से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाकर मैं वास्तव में सम्मानित महसूस कर रहा हूं। यह सम्मान सिर्फ.मेरे लिए नहीं है – यह मेरे परिवार, अजंता फार्मा में मेरे सहकर्मियों और ममता और मधुसूदन अग्रवाल फाउंडेशन की मेरी टीम का है, जो समाज की बेहतरी के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। मैं युगांडा की सरकार और लोगों को भी उनकी सेवा करने का अवसर देने के लिए दिल से धन्यवाद देता हूं।"

उन्होंने यह भी कहा कि यह सम्मान उन्हें अपने कार्यों के प्रति और अधिक प्रतिबद्ध करने का एक मौका देता है।

उन्होंने आगे कहा,"यह पुरस्कार याद दिलाता है कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं अपनी स्वास्थ्य सेवा पहलों का विस्तार करने, भारत-युगांडा संबंधों को मजबूत करने और एक स्वस्थ, बेहतर दुनिया की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। जैसा कि भारत 'वसुधैव कुटुम्बकम' – दुनिया एक परिवार है – में विश्वास करता है, मैं इसी भावना के साथ सेवा करना जारी रखूंगा।"

अग्रवाल ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। उन्होंने युगांडा में कैंसर जागरूकता और उपचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान युगांडा कैंसर संस्थान को 'होप एक्सप्रेस' नामक एक मैमोग्राफी वैन दान करना है। यह

मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का समय से पता लगाने में मदद करती है। इस वैन के माध्यम से 300,000 से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है, और 1,500 से अधिक लोगों की जान बचाई जा चुकी है। यह पहल युगांडा में कैंसर से संबंधित उपचार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है।

अग्रवाल ने युगांडा से 100 से अधिक बच्चों को जीवन रक्षक हृदय शल्य चिकित्सा के लिए भारत लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि इन बच्चों को बिना किसी खर्च के सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल मिले। यह मिशन लगातार जारी रहेगा, और वे भविष्य में और अधिक बच्चों को जीवनदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इसके अलावा, उन्होंने युगांडा में एक कृत्रिम अंग कार्यक्रम भी शुरू किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बारूदी सुरंगों और दुर्घटनाओं से प्रभावित लोगों को कृत्रिम अंग प्रदान किए जा रहे हैं। उनका लक्ष्य 1,000 कृत्रिम अंग दान करने और लगाने का है, जिससे प्रभावित व्यक्तियों को गतिशीलता और स्वतंत्र जीवन जीने में मदद मिल सके। यह कार्यक्रम युगांडा के नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रहा है, और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद कर रहा है।

भारत में, अग्रवाल ने ममता एंड की एक इकाई, उनके संजीवनी ममता अस्पताल के माध्यम से अंधेरी (ई), मुंबई में मधुसूदन अग्रवाल फाउंडेशन की स्थापना की है। इस फाउंडेशन के तहत, वे स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के रोगियों के लिए प्रारंभिक पहचान और रियायती उपचार प्रदान करते हैं। उन्होंने निःशुल्क कैंसर जांच शिविर लगाए हैं, ताकि वित्तीय बाधाओं के बावजूद कोई भी व्यक्ति महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा से वंचित न रहे।

अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आयुष्मान भारत योजना की भी सराहना की, जो किफायती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। उनके अनुसार, यह योजना 6.8 मिलियन से अधिक कैंसर रोगियों को बिना किसी लागत के उपचार प्रदान करने में सफल रही है और इसके परिणामस्वरूप कैंसर की शुरूआती पहचान दर में 36 प्रतिशत का सुधार हुआ है।

अग्रवाल का दृष्टिकोण स्पष्ट है, "पीएम मोदी के नेतृत्व में, भारत स्वास्थ्य सेवा में एक वैश्विक नेता बन गया है, जो सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करता है, चाहे उनकी वित्तीय पृष्ठभूमि कुछ भी हो। 'विकसित भारत 2047' का उनका दृष्टिकोण मुझे जन कल्याण के अपने मिशन को जारी रखने के लिए प्रेरित करता है।"

व्यापार, कूटनीति और परोपकार के क्षेत्र में उनके योगदान ने उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मान दिलाए हैं। इनमें युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार – गोल्डन जुबली मेडल, दुबई में एशियाई व्यापार नेतृत्व मंच द्वारा प्रस्तुत एबीएलएफ बिजनेस इनोवेटर पुरस्कार और यूएई के सहिष्णुता और सह-अस्तित्व मंत्री महामहिम शेख नाहयान मुबारक अल नाहयान द्वारा प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार, उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा प्रदान किया जाने वाला सेवा भूषण सम्मान और रतन टाटा द्वारा मान्यता प्राप्त औरंगाबाद के प्रतीक पुरस्कार शामिल हैं।

स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सेवा और कूटनीति में अपने निरंतर प्रयासों के माध्यम से, अग्रवाल समाज पर एक स्थायी प्रभाव बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मोदी, लक्सन ने भारत-न्यूजीलैंड व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने पर जताई सहमति

■ **बीएनटी न्यूज**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने, अप्रयुक्त क्षमता का एहसास करने और इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान देने पर सहमति जताई।

बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार, "दोनों नेताओं ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच निरंतर व्यापार और निवेश बनाए रखने की बात का स्वागत किया और द्विपक्षीय सहयोग में चल रही मजबूत गति को दशार्ते हुए अधिक से अधिक दोतरफा निवेश का आह्वान किया।"

दोनों ही नेताओं ने गहन आर्थिक एकीकरण प्राप्त करने के लिए एक संतुलित, महत्वाकांक्षी, व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते के लिए मुक्त

व्यापार समझौता (एफटीए) वार्ता शुरू करने का स्वागत किया।

दोनों ही नेताओं ने सहमति व्यक्त की कि एक व्यापक व्यापार समझौता व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

दोनों देश की ताकत का लाभ उठाकर, उनकी संबंधित चिंताओं को संबोधित कर और चुनौतियों से निपटकर, एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार और निवेश वृद्धि को बढ़ावा दे सकता है, जिससे दोनों पक्षों के लिए समान लाभ और पूरकता सुनिश्चित हो सकती है।

बयान में कहा गया है कि नेताओं ने इन वाताओं को शीघ्र समाधान की ओर ले जाने के लिए वरिष्ठ प्रतिनिधियों को नामित करने की प्रतिबद्धता जताई।

एफटीए वार्ता को लेकर नेताओं ने डिजिटल भुगतान क्षेत्र में सहयोग के शीघ्र कार्यान्वयन का पता लगाने के लिए दोनों पक्षों के संबंधित अधिकारियों के बीच चर्चा पर सहमति व्यक्त की।

उन्होंने दोनों पक्षों के व्यवसायों को संबंध विकसित करने, दोनों अर्थव्यवस्थाओं की पूरकताओं पर निर्माण करने के लिए उभरते आर्थिक और निवेश अवसरों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया।

दोनों नेताओं ने (एईओ-एमआरए) पर हस्ताक्षर का भी स्वागत किया, जो सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से संबंधित विश्वसनीय व्यापारियों द्वारा दोनों देशों के बीच माल की आसान आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

दोनों लीडर्स ने बागवानी और वानिकी पर नए सहयोग का स्वागत किया, जिसमें बागवानी पर सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर शामिल हैं जो ज्ञान और अनुसंधान के आदान-प्रदान, कटाई के बाद और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा देकर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाएगा।

दोनों लीडर्स ने आर्थिक विकास उत्पन्न करने, व्यापारिक जुड़ाव बढ़ाने और दोनों देशों के लोगों के बीच बेहतर समझ पैदा करने में पर्यटन द्वारा निभाई गई सकारात्मक भूमिका को भी मान्यता दी।

उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के बीच पर्यटकों के बढ़ते प्रवाह का स्वागत किया और दोनों देशों के बीच सीधी (नॉन-स्टॉप) उड़ान संचालन शुरू करने के लिए अपने वाहकों को प्रोत्साहित करने पर सहमति व्यक्त की।

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री 16-20 मार्च तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वे मुंबई भी जाएंगे और उनके साथ उनके कैबिनेट सहयोगी भी होंगे।

आरबीआई ने जेएम फाइनेंशियल प्रो. लिमिटेड पर लगाया जुर्माना

■ **बीएनटी न्यूज**

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड पर गैर-अनुपालन के लिए 3.10 लाख रुपये का मौद्रिक जुमार्ना लगाया है।

यह जुमार्ना केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मास्टर डायरेक्शन - नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी - सिस्टेमैटिकली इम्पोर्टेंट नॉन-डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए लगाया गया है।

आरबीआई ने 31 मार्च, 2023 तक कंपनी की वित्तीय स्थिति को लेकर कंपनी का वैधानिक निरीक्षण किया।

आरबीआई ने कहा, "आरबीआई के निदेर्शों का अनुपालन न करने और इस संबंध में पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर, कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया

था, जिसमें कंपनी को कारण बताने की सलाह दी गई थी कि निदेर्शों का अनुपालन न करने के लिए कंपनी पर जुमार्ना क्यों न लगाया जाए।"

नोटिस पर कंपनी के जवाब, अतिरिक्त सबमिशन और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत सबमिशन पर विचार करने के बाद, केंद्रीय बैंक ने पाया कि कंपनी के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप सही साबित हुए, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना उचित है।

बैंक ने कहा, "यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लागू करना आरबीआई द्वारा कंपनी के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।"

इस बीच, आरबीआई ने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज (रेगुलेशन) एक्ट, 2005 [सीआईसी (आर) एक्ट] और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रूल्स, 2006 [सीआईसी रूल्स] के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए एक्सपेरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया पर 2 लाख रुपये का मौद्रिक जुमार्ना लगाया।

नोटिस पर कंपनी के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कंपनी द्वारा दिए गए मौखिक सबमिशन पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने पाया कि कंपनी ने अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से सातवें दिन तक क्रेडिट संस्थानों को क्रेडिट जानकारी के संबंध में विसंगति के बारे में सूचना नहीं भेजी।

आरबीआई के अनुसार, कंपनी ने न तो क्रेडिट जानकारी को अपडेट/संशोधित किया और न ही उधारकर्ताओं को अपडेट/संशोधन के लिए अनुरोध प्राप्त होने की निर्धारित 30 दिनों की अवधि के भीतर ऐसा करने में अपनी असमर्थता के बारे में सूचित किया।

तेलंगाना सरकार ने पेश किया तीन लाख करोड़ से ज्यादा का बजट

■ **बीएनटी न्यूज**

तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3.04 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया।

कांग्रेस सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश करते हुए विक्रमार्क ने राजस्व व्यय 2.26 लाख करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 36,504 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया।

उन्होंने कहा, "वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मैं कुल 3,04,965 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित कर रहा हूं, जिसमें राजस्व व्यय 2,26,982 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 36,504 करोड़ रुपये होगा।"

पिछले साल जुलाई में वित्त मंत्री ने 2024-25 के लिए 2.91 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था।

मौजूदा कीमतों पर तेलंगाना के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 2024-25 के दौरान 10.1 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जबकि राष्ट्रीय विकास दर 9.9 प्रतिशत है। तेलंगाना का जीएसडीपी 16,12,579 करोड़ रुपये है।

वित्त वर्ष 2024-25 में तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय 3,79,751 रुपये थी, जो 9.6 प्रतिशत की वृद्धि दशार्ती है।

उन्होंने कहा, "इसकी तुलना में देश की प्रति व्यक्ति आय 2,05,579 रुपये है, जिसमें 8.8 प्रतिशत की वृद्धि दर है। स्पष्ट रूप से, तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय (राष्ट्रीय औसत से) 80 प्रतिशत यानी 1,74,172 रुपये अधिक है। यह राज्य की मजबूत आर्थिक प्रगति को दशार्ता है।"

वित्त वर्ष 2024-25 में, सेवा क्षेत्र ने तेलंगाना के सकल राज्य मूल्य वर्धित

(जीएसवीए) में 66.3 प्रतिशत, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों ने 17.3 प्रतिशत और औद्योगिक क्षेत्र ने 16.4 प्रतिशत का योगदान दिया।

वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार की पहल जैसे कि मुफ्त बिजली, रायथु भरोसा, कृषि ऋण माफी और सिंचाई परियोजनाओं में निवेश ने किसानों का आत्मविश्वास बढ़ाया है और कृषि क्षेत्र को मजबूत किया है। साथ ही, कृषि क्षेत्र को और बढ़ाने के लिए, सरकार सक्रिय रूप से बागवानी, पशुपालन और जलीय कृषि को बढ़ावा दे रही है, जिससे किसानों के लिए विविध और सतत विकास सुनिश्चित हो रहा है।

उन्होंने कहा कि तेलंगाना में औद्योगिक क्षेत्र 22.5 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार प्रदान करता है। "चाइना प्लस 1" (चीन पर निर्भरता घटाने की) रणनीति को अपनाकर, सरकार का लक्ष्य तेलंगाना को फार्मास्यूटिकल्स, जैव प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना है।

विक्रमार्क ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही तेलंगाना सहित दक्षिणी राज्यों के लिए कर हस्तांतरण के घटते हिस्से पर चिंता व्यक्त की है। 14वें वित्त आयोग के तहत, तेलंगाना को 2.437 प्रतिशत धन प्राप्त हुआ, जो 15वें वित्त आयोग के तहत घटकर 2.102 प्रतिशत रह गया।

उन्होंने बताया, "हमारी सरकार ने कहा कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को कम धनराशि आवंटित करना अनुचित है और अधिक तर्कसंगत कर वितरण प्रणाली की वकालत की, जो राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करती है।"

राज्य सरकार ने क्षैतिज कर हस्तांतरण में सुधार का प्रस्ताव दिया है, जो वर्तमान "प्रति व्यक्ति आय अंतर" मानदंड से हटकर है। इसकी बजाय, यह राष्ट्रीय आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने वाले राज्यों के लिए संसाधनों का अधिक न्यायसंगत आवंटन सुनिश्चित करने के लिए जीएसडीपी को 50 प्रतिशत भारांश देने की सिफारिश करता है।

वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में तेलंगाना ने कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन अब यह विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। 'तेलंगाना राइजिंग 2050 विजन' के साथ सरकार स्थायी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को आकार दे रही है।

उन्होंने कहा, "अगले दशक के लिए हमारा रणनीतिक रोडमैप मौजूदा 200 अरब डॉलर की राज्य अर्थव्यवस्था को पांच गुना बढ़ाकर एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की कल्पना करता है।"

देश में 55 करोड़ से अधिक जनधन खाते खुले

■ **बीएनटी न्यूज**

देश में 7 मार्च 2025 तक 55.05 करोड़ जनधन खाते खुले हैं। इसमें से 36.63 करोड़ या 66.57 प्रतिशत ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में खुले हैं। यह जानकारी सरकार द्वारा दी गई।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत 7 मार्च तक कुल नामांकन की संख्या बढ़कर 50.30 करोड़ हो गई है।

अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना और अन्य वित्तीय समावेशन योजनाओं में भी मजबूत प्रगति हुई है।

अटल पेंशन योजना में कुल नामांकन की संख्या 7.49 करोड़ हो गई है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

(पीएमएमवाई) के अंतर्गत 28 फरवरी तक 33.19 लाख करोड़ रुपये के 52.07 करोड़ लोन स्वीकृत किए जा चुके हैं।

स्टैंड अप इंडिया योजना (एसयूपीआई) के तहत योजना की शुरूआत से लेकर अब तक (7 मार्च तक) 60,504 करोड़ रुपये के 2.67 लाख लोन स्वीकृत किए गए हैं।

सरकार ने वित्तीय समावेशन के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) की शुरूआत अगस्त 2014 में की थी, जिसका उद्देश्य बैंकिंग सुविधा से वंचित प्रत्येक वयस्क को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है।

पीएमएसबीवाई एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है, जिसका हर साल रिन्यूएबल किया जा सकता है। इसमें 20 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये और स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये का कवरेज दिया जाता है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) एक जीवन बीमा योजना है, जिसे हर साल रिन्यू किया जा सकता है। यह 436 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का कवरेज प्रदान करती है।

केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, पीएमजेजेबीवाई में अब तक 23.21 करोड़ से अधिक नामांकन हो चुके हैं।

अटल पेंशन योजना का उद्देश्य 18 से 40 वर्ष की आयु के पात्र ग्राहकों को मासिक पेंशन प्रदान करना है, जो किसी भी संगठित पेंशन योजना के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं।

इस योजना के तहत ग्राहकों को योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु में 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये और 5,000 रुपये प्रति माह की निर्धारित न्यूनतम पेंशन मिलेगी।

ग्लोबल हेल्थ और विकास में बदलाव लाने के लिए डिजिटल समाधान तैयार कर रहा भारत : बिल गेट्स

■ **बीएनटी न्यूज**

गेट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष और बोर्ड सदस्य बिल गेट्स ने कहा कि भारत न केवल अपने नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल इनोवेशन का निर्माण कर रहा है, बल्कि ऐसे समाधान भी बना रहा है, जिनमें ग्लोबल हेल्थ और विकास को बदलने की क्षमता है।

गेट्स फाउंडेशन और महिला सामूहिक मंच के सहयोग से सीआईआई द्वारा आयोजित एक वैश्विक मंच पर बोलते हुए, बिल गेट्स ने इनोवेशन, हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी में भारत के लीडरशिप की सराहना की।

इस मंच के साथ वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए स्केलेबल, सस्टेनेबल और टेक-ड्रिवन सॉल्यूशन को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका के मध्यनजर ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर, पॉलिसी मेकर्स और इन्वेस्टर्स एक साथ आए।

गेट्स ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत किफायती स्वास्थ्य सेवा, एआई-संचालित निदान और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी लीडिंग भूमिका के साथ भविष्य का निर्माण कर रहा है।

उन्होंने उभरती अर्थव्यवस्थाओं में दबाव वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए वैश्विक स्तर पर भारत के इनोवेटिव सॉल्यूशन को बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया।

गेट्स ने भारत की तीव्र प्रगति पर भी प्रकाश डालते हुए देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव आर्थिक विकास और तकनीकी सफलताओं को दुनिया के लिए एक मॉडल बताया।

उन्होंने कहा, "भारत ने

कम लागत वाले इनोवेशन के जरिए स्वास्थ्य और विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है।"

भविष्य की ओर देखते हुए, गेट्स ने वैश्विक स्तर पर एआई, स्वास्थ्य सेवा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सफलताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय इनोवेटर्स, पॉलिसी मेकर्स और उद्यमियों के साथ मिलकर काम करने के लिए अपने फाउंडेशन के कमिटमेंट की पुष्टि की।

अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी की अध्यक्ष स्मृति ईरानी ने फाउंडेशन और गेट्स के नेतृत्व की सराहना की। साथ ही सोशल इनोवेशन के लिए निवेश की भी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

ईरानी ने कम लागत वाले, टेक्नोलॉजी-ड्रिवन समाधान लाने में भारत की शक्ति के बारे में बात की, जो स्वास्थ्य, पोषण और खाद्य सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं।

सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की लीडिंग भूमिका पर जोर दिया और इसे ग्लोबल साउथ के लिए एक ब्लू प्रिंट बताया।

सीआईआई के अध्यक्ष संजीव पुरी ने कहा, "आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्यक्रम और डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूसन, एआई-पावर्ड कृषि समाधान जैसी पहलों की सफलता यह साबित करती है कि जब नीति और टेक्नोलॉजी एक साथ आती है तो हम ऐसे स्केलेबल, सस्टेनेबल सॉल्यूशन बना सकते हैं जो ग्लोबल बेंचमार्क के रूप में काम करते हैं।"

10.05 करोड़ ग्रामीण महिला परिवारों को 90.90 लाख स्वयं सहायता समूहों में किया गया संगठित : केंद्र

■ **बीएनटी न्यूज**

केंद्र सरकार ने जानकारी देते हुए कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत कम से कम 10.05 करोड़ ग्रामीण महिला परिवारों को 90.90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित किया गया है।

वित्त वर्ष 2013-14 से, डीएवाई-एनआरएलएम के तहत महिला एसएचजी द्वारा 10.20 लाख करोड़ रुपये की बैंक क्रेडिट राशि का इस्तेमाल किया गया।

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि 28 फरवरी, 2025 तक एसएचजी और उनके संघों को कुल 51,368.39 करोड़ रुपये की पूंजीकरण सहायता (रिवॉलविंग फंड और कम्युनिटी इंवेस्टमेंट फंड) प्रदान की गई है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 28 फरवरी तक यह मिशन 28 राज्यों और छह केंद्र शासित प्रदेशों के 745 जिलों के 7,144 ब्लॉकों में लागू किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय केवल दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर पूरे देश में डीएवाई-एनआरएलएम को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिला परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना और उन्हें तब तक लगातार पोषित और सहायता प्रदान करना है, जब तक कि वे समय के साथ आय में वृद्धि प्राप्त न कर लें। इसी के साथ डीएवाई-एनआरएलएम का उद्देश्य गरीब महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और उन्हें गरीबी से बाहर निकालना है।

केंद्रीय मंत्री के अनुसार, इस योजना ने

महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए मार्केटिंग सहायता को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं।

इसमें शहरी बाजारों में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आयोजित किए जाने वाले सरस मेले शामिल हैं।

मंत्रालय ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए जीईएम में स्टोर फ्रंट के रूप में सरस कलेक्शन बनाया है।

केंद्रीय मंत्री के अनुसार, कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों सहित स्वयं सहायता समूहों के उत्पादकों को फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम, अमेजन सहेली पहल और स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन के लिए मीशो के जरिए राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने में सुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय और फ्लिपकार्ट, अमेजन और फैशनियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (मीशो) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए मंत्रालय द्वारा एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है।

इसके अलावा, ई-सरस ओएनडीसी नेटवर्क पर विक्रेता नेटवर्क भागीदार के रूप में भी सक्रिय है।

9 करोड़ से अधिक लोगों ने 28 फरवरी तक जमा किए आईटीआर: आयकर विभाग

■ **बीएनटी न्यूज**

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अब तक 9 करोड़ से अधिक लोग इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) जमा कर चुके हैं। आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों से यह जानकारी मिली।

आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में जमा किए गए आईटीआर में चार लाख से अधिक करदाताओं ने एक करोड़ रुपये से अधिक आय घोषित की है।

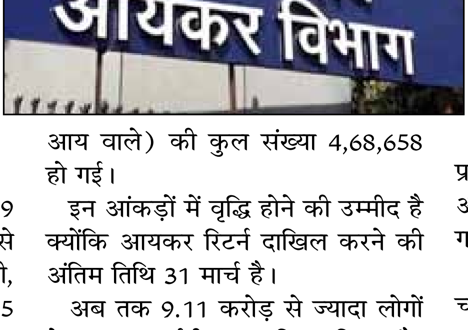

आंकड़ों से मुताबिक, लगभग 3.89 लाख करदाताओं ने 1 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये के बीच आय घोषित की, जबकि लगभग 36,274 व्यक्तियों ने 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये के बीच आय की रिपोर्ट की है।

इसके अलावा, 43,004 लोगों ने 10 करोड़ रुपये से अधिक की आय का खुलासा किया। इससे उच्च आय वाले करदाताओं (1 करोड़ रुपये से अधिक आय वाले) की कुल संख्या 4,68,658 हो गई।

इन आंकड़ों में वृद्धि होने की उम्मीद है क्योंकि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है।

अब तक 9.11 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना आईटीआर दाखिल किया है। भारत में पंजीकृत करदाताओं की कुल संख्या 13.96 करोड़ है। इसका मतलब है कि लगभग 65 प्रतिशत ने अपना रिटर्न दाखिल कर दिया है।

इसके अलावा, लगभग 8.56 करोड़ कर रिटर्न ई-वेरिफाइड किए जा चुके हैं और आयकर विभाग द्वारा 3.92 लाख करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया है।

महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1.38 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए। उत्तर प्रदेश में 90.68 लाख रिटर्न जमा किए गए, जबकि गुजरात में 87.90 लाख रिटर्न दाखिल किए गए।

दिल्ली में 44.45 लाख लोगों ने आईटीआर जमा किए हैं। वहीं, आंध्र प्रदेश और पंजाब में क्रमशः 30.76 लाख और 43.79 लाख रिटर्न दाखिल किए गए।

इससे पहले, विभाग ने कहा था कि चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2024-25) की 1 अप्रैल, 2024 - 16 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 24) की इसी अवधि की तुलना में 16.2 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि के साथ 25.86 लाख करोड़ रुपये हो गया।

100 दिवसीय सघन अभियान ने 'टीबी मुक्त' भारत के लिए तैयार किया मजबूत आधार

■ बीएनटी न्यूज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 100 दिवसीय सघन टीबी मुक्त भारत अभियान ने 'टीबी मुक्त' भारत के लिए मजबूत आधार तैयार किया है।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "टीबी के खिलाफ भारत की लड़ाई में उल्लेखनीय प्रगति देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हाल ही में संपन्न 100 दिवसीय सघन टीबी मुक्त भारत अभियान पर महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिसने टीबी मुक्त भारत के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है।" स्वास्थ्य मंत्रालय ने 100 दिवसीय अभियान 7 दिसंबर को शुरू किया, जो 24 मार्च 2025 को संपन्न हुआ।

इस अभियान में 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 455 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों को लक्षित किया गया, जिसका उद्देश्य टीबी के मामलों का पता लगाने में तेजी लाना, मृत्यु दर को कम करना और नए मामलों को रोकना था।

जेपी नड्डा ने लेख में कहा, "यह अभियान देश के कोने-कोने तक पहुंचा और कमजोर वर्ग के 12.97 करोड़ लोगों की जांच की गई।" उन्होंने कहा कि सघन अभियान के कारण 7.19 लाख टीबी मरीजों की पहचान की गई, जिनमें से 2.85 लाख मामले बिना लक्षण वाले थे।"

उन्होंने कहा कि 100 दिवसीय 'टीबी मुक्त' भारत अभियान को समर्थन देने के लिए 13.46 लाख से अधिक निक्षय शिविर आयोजित किए गए। इसके अलावा 30 हजार से ज्यादा निर्वाचित प्रतिनिधि, कॉरपोरेट पार्टनर और आम नागरिक भी इस अभियान में शामिल हुए।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "इसके अलावा जेलों, खदानों, चाय बागानों, निर्माण स्थलों और कार्यस्थलों जैसे सामूहिक स्थानों पर 4.17 लाख से अधिक संवेदनशील आबादी की स्क्रीनिंग और परीक्षण किया गया।"

जनभागीदारी का हवाला देते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि 'अभियान अवधि के दौरान त्योहारों पर 21 हजार से अधिक टीबी जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं, जिनमें सभी वर्ग के नेताओं और सामुदायिक प्रभावशाली लोगों को शामिल किया गया।'

उन्होंने कहा, "केवल 100 दिनों में 1 लाख 5 हजार 181 नए नि-क्षय मित्र नामांकित किए गए, जहां व्यक्तियों और संगठनों ने टीबी प्रभावित परिवारों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान की।"

अभियान को केवल शुरुआत बताते हुए नड्डा ने कहा कि देश इन प्रयासों को राष्ट्रव्यापी स्तर पर आगे बढ़ाएगा, ताकि सभी नागरिकों को आधुनिक निदान, गुणवत्तापूर्ण उपचार और अटूट सामुदायिक समर्थन तक समान पहुंच मिले।

स्वास्थ्य निधि का पूरा पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकी पंजाब सरकार, कैग रिपोर्ट में खुलासा

■ बीएनटी न्यूज

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा आवंटित बजट में से 6.5 से 20.74 प्रतिशत तक स्वास्थ्य निधि का उपयोग नहीं किया गया।

विधानसभा में रखी गई सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन की 2024 की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार 2021-22 के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं पर अपने कुल व्यय का केवल 3.11 प्रतिशत और जीएसडीपी का 0.68 प्रतिशत ही खर्च कर सकी, जो बजट के आठ प्रतिशत और जीएसडीपी के 2.50 प्रतिशत से काफी कम है।

प्रत्येक वर्ष के लिए राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाएं 10 से 108 दिनों की देरी के साथ केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गईं, जिससे अंततः अनुमोदन में देरी हुई और इसके परिणामस्वरूप धन की प्राप्ति में देरी हुई।

कैग ने कहा कि मार्च 2022 तक पंजाब निरोगी योजना के तहत पंजाब निरोगी सोसायटी (4.92 करोड़ रुपये) और मुख्यमंत्री पंजाब कैंसर राहत कोष योजना (76.81 करोड़ रुपये) के पास सरकारी खाते के बाहर भारी मात्रा में सरकारी धन अप्रयुक्त पड़ा

हुआ था। इसके अलावा, राजिंदरा अस्पताल, पटियाला द्वारा 2021-22 तक एकत्र किए गए 1.94 करोड़ रुपये के उपयोगकर्ता शुल्क और पंजाब स्वास्थ्य प्रणाली निगम को हस्तांतरित 85.70 करोड़ रुपये की रियायती शुल्क राशि भी कोडल प्रावधानों के उल्लंघन में सरकारी खाते के बाहर पड़ी हुई थी।

पंजाब में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, परिवार कल्याण, कायाकल्प और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) आदि जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं था।

इसमें कहा गया है कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवंटित धनराशि के उपयोग में कमी थी। परिवार कल्याण योजना और जननी सुरक्षा योजना के तहत वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन का भुगतान न किए जाने के मामले भी सामने आए हैं।

कायाकल्प का दर्जा पाने की आकांक्षा रखने वाले स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है और राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों से प्रमाणित स्वास्थ्य संस्थानों में भी स्थिर वृद्धि नहीं देखी गई है।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मोबाइल स्वास्थ्य टीमें अपर्याप्त कर्मचारियों के साथ काम कर रही थीं, जिससे बच्चों की जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।

केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने के बावजूद मोबाइल स्वास्थ्य टीमों के पास आयरन और फोलिक एसिड तथा एल्बेंडाजोल को छोड़कर कोई भी आवश्यक दवा, ड्रॉप्स और मलहम उपलब्ध नहीं थे।

कैग ने कहा कि लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का जिम्मेदारीपूर्ण प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए परिकल्पित नियामक तंत्र प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहा है।

भोपाल एम्स के जेपी शर्मा को हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए भेजा चेन्नई

■ बीएनटी न्यूज

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्राध्यापक प्रो. (डॉ.) जेपी शर्मा को गंभीर अवस्था में हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए पीएमश्री एयर एंबुलेंस सेवा के माध्यम से चेन्नई भेजा गया है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि एम्स, भोपाल में प्राध्यापक के पद पर पदस्थ प्रो. (डॉ.) जेपी शर्मा को गंभीर अवस्था में हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान अंतर्गत पीएमश्री एयर एंबुलेंस सेवा के माध्यम से चेन्नई भेजा जा रहा है। वे अति गंभीर स्थिति में कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर से पीड़ित हैं, जिसमें हार्ट ट्रांसप्लांट ही अंतिम विकल्प होता है। डॉ. शर्मा की गंभीर स्थिति संज्ञान में आते ही, तत्काल प्रभाव से उन्हें भोपाल से चेन्नई भिजवाने के लिए पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए। प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की सेवा के लिए राज्य सरकार तत्पर है।

सीएम ने कहा कि पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा ऐसी गंभीर स्थितियों में देवदूत सिद्ध हो रही है। गंभीर मरीजों के लिए यह सेवा संकटमोचक बन रही है। बाबा महाकाल से सीएम ने डॉ. शर्मा के स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की है। बताया गया है कि डॉ. शर्मा की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री यादव की ओर से एयर एंबुलेंस का इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। उसके बाद उन्हें चेन्नई के लिए भेजा गया है।

बता दें कि राज्य सरकार द्वारा बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के मकसद से पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। इसका लाभ प्रदेश के गरीब तबके से नाता रखने वाले परिवारों को भी मिल रहा है। छोटे शहरों के मरीज उपचार के लिए इस सेवा का लाभ लेकर बड़े शहरों के प्रमुख अस्पतालों में उपचार करा पा रहे हैं और उनके जीवन की रक्षा हो रही है।

उल्लेखनीय है कि भोपाल में हृदय रोगी जेपी शर्मा को समय पर इलाज उपलब्ध कराने के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। इस कॉरिडोर के जरिए गंभीर हालत में भर्ती एक मरीज को भोपाल के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से एयरलिफ्ट कर चेन्नई एम्स पहुंचाया गया। यातायात पुलिस भोपाल ने एम्स अस्पताल से हवाई अड्डे तक इस विशेष कॉरिडोर का निर्माण किया, जिसके तहत व्यस्ततम ट्रैफिक के दौरान 24 किलोमीटर की दूरी को महज 16 मिनट में तय किया गया। इस व्यवस्था ने मरीज को समय पर चेन्नई पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, जहां उसे बेहतर इलाज मिल सकेगा।

इस ग्रीन कॉरिडोर को सफल बनाने के लिए यातायात पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसमें 1 सहायक पुलिस आयुक्त, 4 निरीक्षक, 5 उप-निरीक्षक, 10 सहायक उप-निरीक्षक और 55 प्रधान आरक्षक/आरक्षक सहित कुल 75 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने हिस्सा लिया। अधिकारियों ने ट्रैफिक को नियंत्रित कर एंबुलेंस के लिए निर्बाध रास्ता सुनिश्चित किया।

झारखंड के साहिबगंज के आदिम जनजाति बहुल गांव में ब्रेन मलेरिया से पांच बच्चों की मौत

■ बीएनटी न्यूज

झारखंड के साहिबगंज जिला अंतर्गत मंडरो प्रखंड के नगरभीठा गांव में ब्रेन मलेरिया से मिलते-जुलते लक्षण वाली बीमारी ने कहर बरपा दिया है। पिछले 12 दिनों के अंदर इस बीमारी से पांच बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 12 अन्य बीमार हैं।

इसकी सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर कैंप लगाया है। बीमारी से प्रभावित लोगों के बीच दवाइयों का वितरण किया गया है। उनके रक्त एवं अन्य सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए दुमका भेजे गए हैं। साहिबगंज के उपायुक्त हेमंत सती ने सिविल सर्जन को बीमारी से प्रभावित लोगों के इलाज की समुचित व्यवस्था का निर्देश दिया है।

बताया गया कि गांव में 12 मार्च को चांदु पहाड़िया के दो वर्षीय पुत्र जीता पहाड़िया की मौत सबसे पहले हुई। उसे तेज बुखार था और लगातार उल्टी हो रही थी। उसका गांव में ही जड़ी-बूटी से उपचार करने की कोशिश की गई थी। इसके बाद 19 मार्च को असना पहाड़िया के पांच वर्षीय पुत्र विकास पहाड़िया, 20 मार्च को गुल्ली पहाड़िया के पुत्र बेफरे पहाड़िया, 22 मार्च को बिजु पहाड़िया की दो वर्षीय पुत्री एतवारी पहाड़िया और 23 मार्च को सोमरा पहाड़िया की तीन वर्षीय बेटी सजनी पहाड़िन की भी मौत हो गई।

नगर भीठा गांव के प्रधान ने झामुमो के स्थानीय नेताओं को इसकी जानकारी दी। इसके बाद यह मामला जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में लाया गया। सभी मृतक आदिम जनजाति समुदाय के हैं।

प्रभावितों में गांव की रुती पहाड़िन, दिनेश पहाड़िया, रूपा पहाड़िया, मीना पहाड़िया, जोनी पहाड़िन, दानियाल पहाड़िया, मनोज पहाड़िया, गुलाबी पहाड़िया, पति पहाड़िया, चूनी पहाड़िन एवं कुछ अन्य शामिल हैं। इनके अलावा 30 से ज्यादा लोगों के खून के सैंपल कलेक्ट किए गए हैं।

उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को प्रभावित गांव सहित आस-पास के इलाकों में भी स्थिति का जायजा लेने का निर्देश दिया है।

जन औषधि केंद्रों ने बचाए गरीब रोगियों के 30 हजार करोड़ : जेपी नड्डा

■ बीएनटी न्यूज

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने कहा कि जनऔषधि केंद्रों के माध्यम से अब तक गरीबों के 30 हजार करोड़ रुपये बचे हैं। इसके अलावा, आयुष्मान योजना तथा स्वास्थ्य क्षेत्र के अन्य कार्यक्रमों से भी गरीबों को भारी राहत मिली है।

राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा के जवाब देते हुए जे.पी. नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम और आयुष्मान जन आरोग्य योजना के जरिए गरीब रोगियों के 16 हजार करोड़ रुपये बचे हैं।

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि देश में अभी 15 हजार जन औषधि केंद्र हैं। दो साल के अंदर 25 हजार और जन औषधि केंद्र हो जाएंगे। इनके माध्यम से गरीब रोगियों के 30 हजार करोड़ रुपये बचे हैं।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम देश के 748 जिलों में चल रहा है। इसके तहत 1,575 केंद्र खोले गए हैं जिनमें 26 लाख 49 हजार रोगियों को लाभ मिला है। यहां तीन करोड़ 17 लाख डायलिसिस सेशन हो चुके हैं।

बजट का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि 2014-15 में स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 38 हजार करोड़ रुपये था जो अब बढ़कर करीब एक लाख करोड़ रुपये हो गया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश में टीबी की बीमारी में 17.7 प्रतिशत कमी आई है जो कि वैश्विक कमी से दोगुनी है। टीबी से मृत्यु दर में 21 प्रतिशत की कमी आई है। उपचार के दायरे में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उन्होंने बताया कि 30 साल की उम्र में हर किसी के ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की जांच की जाएगी। अब तक 100 करोड़ से अधिक लोगों के ब्लड प्रेशर की जांच की जा चुकी है। वहीं, 88.5 करोड़ लोगों की डायबिटीज की स्क्रीनिंग हो चुकी है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि हम एनएचएम में तीन तरह के कैंसर की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिनकी संख्या एक लाख 76 हजार है, 30 साल की उम्र में हर एक के ओरल कैंसर, महिलाओं के स्तन कैंसर और सर्विक्स कैंसर की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अब तक 26.9 करोड़ लोगों की ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इनमें से एक लाख 63 हजार लोग ओरल कैंसर से पीड़ित पाए गए हैं जिनका उपचार शुरू हो गया है।

इसी तरह स्तन कैंसर के लिए 14 करोड़ 60 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। इनमें से 57 हजार कैंसर से पीड़ित पाई गई हैं। सर्विक्स कैंसर के लिए नौ करोड़ चार लाख लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। इनमें से 97 हजार लोग सर्विक्स कैंसर से पीड़ित पाए गए हैं। उनका भी उपचार प्रारंभ हो चुका है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हरियाणा के झज्जर में विश्व स्तरीय कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया गया है। यह विश्व के सर्वोत्तम कैंसर इंस्टीट्यूट में से एक है। चितरंजन कैंसर इंस्टीट्यूट, कोलकाता के लिए भी 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि सिकल सेल एलिमिनेशन प्रोग्राम यानी वंशानुगत लाल रक्त कोशिका विकार के लिए चार करोड़ 80 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। इसके लिए विशेष किस्म के कार्ड एक करोड़ 65 लाख लोगों को जारी किए जा चुके हैं। इस कार्ड की खासियत यह है कि यदि ये कार्ड आपस में मैच करते हैं तो वे दोनों व्यक्ति आपस में शादी कर सकते हैं, यदि मैच नहीं करते हैं तो शादी नहीं हो सकती। इसका लाभ यह होगा कि पैदा होने वाला बच्चा इस बीमारी से ग्रसित नहीं होगा।

जे.पी. नड्डा ने बताया कि 225 ऐसी दुकानें खोली गई हैं, जहां ब्रांडेड दवाइयां 50 प्रतिशत से अधिक की छूट पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनमें कैंसर की दवाइयां भी शामिल हैं। अब तक 4.25 करोड़ लोगों ने इसका लाभ लिया है जिससे उनके चार हजार करोड़ रुपये बचे हैं। यहां अब तक 7,800 करोड़ रुपये की दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 157 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं और देश में मेडिकल सीटों की संख्या 1.11 लाख हो गई है। इनके अलावा, 75 हजार और नई मेडिकल सीटों की व्यवस्था की जा रही है। इस वर्ष 40 हजार सीटें बढ़ाई गई हैं, 75 नए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक खोले गए हैं।

सुधार लें अपनी ये आदतें नहीं तो हो जाएंगे अंधे

इन आदतों की वजह से जा सकती हैं आंखों की रोशनी, कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां?

आज के समय में लोग तेजी से अपनी आंखों की रोशनी खोते जा रहे हैं। आंखों की रोशनी कमजोर होना आनुवांशिकी, उम्र और आपके पर्यावरण समेत कई कारणों पर निर्भर करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में दुनियाभर में कम से कम 2.2 बिलियन लोगों की रोशनी कमजोर है। आंखों की रोशनी के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार आज की लाइफ स्टाइल है जिसके चलते लोगों को कम उम्र में ही चश्मा लग जाते हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि किन आदतों में सुधार करने से आपकी आंखों की रोशनी उम्र भर बनी रहेगी।

1) बहुत ज्यादा डिजिटल डिवाइस का यूज

आज के समय में बच्चे हो या बड़े हर कोई जरूरत से ज्यादा स्मार्टफोन, लैपटॉप और टीवी का यूज करते हैं। इन सभी डिवाइस की स्क्रीन से UV rays निकलती हैं जो सीधे तौर पर आपकी आंखों पर प्रभाव डालती है। वहीं अगर आप रोजाना घंटों तक लैपटॉप पर काम करते हैं तो आपकी आंखों में ड्राईनेस, आने लगती है और धीरे-धीरे आपकी आंखों की रोशनी धुंधली हो जाती है।

2) हेल्दी डाइट ना लेना

आज के समय में बदलती लाइफस्टाइल के साथ लोगों के खान-पान में भी काफी बदलाव आया है. आज लोग उल्टा-सीधा जंक और फास्ट फूड का सेवन अधिक करने लगे हैं। इस तरह का खान-पान ना सिर्फ आपकी आंखों की कमजोर रोशनी के लिए जिम्मेदार होता है बल्कि इससे शरीर में तमाम बीमारियां भी पैदा होती है। इतना ही नहीं आजकल सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना लोग शान मानते हैं लेकिन इससे ना सिर्फ शरीर में शुगर लेवल तेजी से बढ़ता है बल्कि इससे डायबिटीज भी हो जाती है। वहीं आपको एक बार डायबिटीज की समस्या हो गई तो आपकी आंखों की रोशनी धीरे-धीरे धंधली हो जाएगी। आप सोच रहें होंगे कि ऐसे में क्या करें?

3) बार-बार आंखों को मलना

अगर आप सोच रहें है कि आंखों को मलने से भला रोशनी कैसे जा सकती है या कमजोर हो सकती है तो हम आपको बता दे कई रिसर्च में पाया गया है कि आंखों को रगड़ने से कॉर्निया पतला होकर कमजोर हो जाता है। इससे केराटोकोनस की समस्या पैदा हो सकती है जिससे आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है। ऐसे में अगर आपकी आंखों में बार-बार जलन या खुजली होती है तो आप आंखों को रगड़ना छोड़िए और नीचे दिए उपायों का प्रयोग करें।

4) डिहाइड्रेशन की समस्या

अक्सर लोग कम पानी पीतें हैं इससे शरीर को आवश्यकता के अनुसार पानी नहीं मिल पाता जिससे बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है। आंखों में नमी रहने, आंसू बनने और आंखों में चिकनाई रखने के लिए आपको बॉडी का हाइड्रेट होना जरूरी है। डिहाइड्रेशन के कारण आंखों में खिंचाव जैसे थकी हुई आंखें, धुंधली दृष्टि, सिरदर्द और दोहरी दृष्टि की समस्या पैदा हो सकती है। ढेर सारा पानी पीने से शरीर से अतिरिक्त नमक को बाहर निकालने में मदद मिलेगी और आंखों की थकान को कम करने में मदद के लिए आपकी आंखों को ठीक से हाइड्रेट भी रहेंगी। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप दिन में 3-4 लीटर पानी अवश्य पियें।

5) शराब का सेवन

अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो यह आपकी पेरिफेरल विजन जिसे परिधीय दृष्टि भी कहा जाता है उसको खराब कर सकती हैं। जिससे आपको टनल विजन भी हो सकता है। इससे आपकी आंखों की रोशनी सिकुड़ जाती है साथ ही आपको धुंधला दिखाई देने लगता है। इसलिए जितना हो सके आप शराब पीने से बचें क्योंकि यह सिर्फ आपकी आंखे ही खराब नहीं करती बल्कि आपके लिवर और बाकि अंगों पर भी बुरा प्रभाव डालती हैं।

6) धूम्रपान करना

अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग के CDC की एक रिपोर्ट के अनुसार धूम्रपान करने से आंखों की रोशनी को काफी नुकसान होता है। CDC ने अपनी रिसर्च में पाया कि धूम्रपान ना करने वाले लोगों की तुलना में स्मोकिंग करने वालों में एएमडी होने की संभावना दोगुनी होती है। वहीं यदि कोई व्यक्ति दिन में 2-3 बार धूम्रपान करता है तो उनमें मोतियाबिंद होने की संभावना दो से तीन गुना बढ़ जाती है।

7) पूरी नींद ना लेना

हरेक मनुष्य के लिए 7-8 घंटे की नींद जरूरी होती है। इस नींद से ना सिर्फ आपके शरीर के पूरे बॉडी पार्ट खुदको रिकवर करते हैं बल्कि रिलेक्स भी करते हैं ताकि अगले दिन आप पूरी एनर्जी के साथ काम कर सकें। ऐसे में अगर आप कम नींद लेते हैं तो आपके शरीर के दूसरे अंगो पर तो इसका विपरीत असर पड़ेगा ही पर आपकी आंखों की नसें भी कमजोर होना शुरू हो जाएंगी। जिससे नसों के जरिए आंखों को मिलने वाले पोषण में दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप रोजाना 7-8 घंटे की एक नींद तो जरूर लें।

क्या करें?

आप अगर टीवी देख रहें हैं तो कम से कम टीवी से 4-5 फीट की दूरी बनाए रखें और लगातार 1 घंटे से ज्यादा टीवी ना देखें और अगर आपको देखना ही है तो 1 घंटे बाद ब्रेक लेकर पानी पियें और आंखों को पानी से जरूर धोएं। वहीं आप अगर मोबाइल या लैपटॉप पर घंटो भर काम करते हैं तो एंटी ग्लेयर गलास वाले चश्मे को पहने क्योंकि यह 70-80% तक UV Rays को आपकी आंखों तक पहुंचने से रोकता है। इसके अलावा आप हर 30-40 मिनट में एक ब्रेक लें।

आंखों में जलन होने पर यह उपाय आजमाएं

अगर आपको आंखों में जलन महसूस होती है या फिर उन्हें रगड़ने का मन करता है तो ऐसे में आप आई-ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं. कई बार आंखों में धूल के कण चले जाने के कारण होता है आप चाहे तो पानी के छींटे मारकर भी अपनी आंखों को धो सकते हैं। यदि फिर भी आपको ये समस्या निरंतर बनी हुई रहती है तो हमारी सलाह रहेगी कि एक बार डॉक्टर से आंखों का चेकअप जरूर करवाएं।

अपनाएं ये तरीका

आंखों के लिए आयरन और फाइबर वाली चीजों का सेवन अच्छा माना जाता है। इससे ना सिर्फ आपकी आंखों की रोशनी बनी रहती है बल्कि यह आंखों में होने वाली दूसरी समस्याओं से निजात पाने में भी मदद करता है। आप सनफ्लावर सीड्स, चने, गाजर का जूस, बींस, पत्तेदार सब्जियों आदि का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जिंक, ओमेगा -3 फैटी एसिड और विटामिन सी और ई वाले पदार्थों का सेवन भी कर सकते हैं।

शाहरुख और विराट कोहली ने आईपीएल के 18वें सीजन की शुरूआत की

■ बीएनटी न्यूज

मेगास्टार और कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान ने यहां ईडन गार्डन्स में 2025 इंडियन प्रीमियर लीग सीजन के उद्घाटन समारोह में कार्यवाही की शुरूआत की। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) अब अपने 18वें सीजन में प्रवेश कर रहा है, इस सदाबहार अभिनेता, जिन्हें अपने दशकों के काम के माध्यम से प्रशंसकों को झूमने पर मजबूर करने का हुनर है, ने टॉस से पहले सिटी ऑफ जॉय को संबोधित किया।

शाहरुख ने कहा, यह सिर्फ एक लीग के रूप में नहीं बल्कि एक आंदोलन के रूप में सामने आया है। खेल का उत्सव, जुनून का त्योहार, एक युद्ध का मैदान जहां नायक बनते हैं। हम यहां 'जॉय के शहर' कोलकाता में हैं। तो चलिए इस भव्य तमाशे को उसी ऊर्जा, उसी पागलपन, उसी प्यार के साथ प्रज्वलित करते हैं जो आईपीएल है, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग। कोलकाता! क्या आप तैयार हैं?

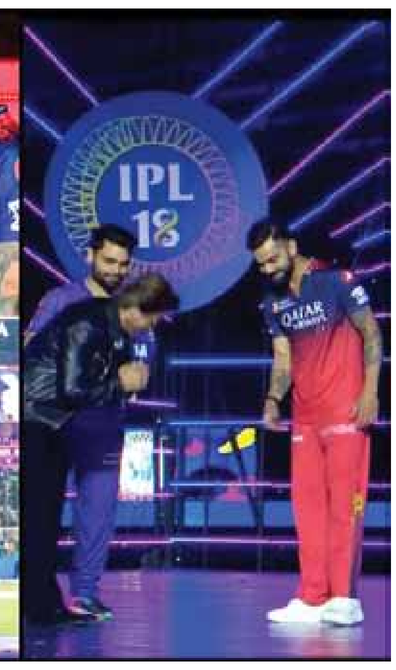

शाहरुख खान के खास अंदाज में, अभिनेता ने अपनी एक फिल्म 'पठान' का संदर्भ देते हुए भीड़ को उन्माद में डाल दिया। उन्होंने कहा, पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान खुद आएगा और पटाखे भी लाएगा।

हालांकि 59 वर्षीय अभिनेता ने उस दिन कोई प्रस्तुति नहीं दी, लेकिन उन्होंने गायिका श्रेया घोषाल, अभिनेत्री दिशा पटानी और हिप-हॉप कलाकार करण औजला के लिए मंच तैयार किया।

हालांकि, घटनाओं के अप्रत्याशित मोड़ में, शाहरुख मैदान पर वापस आए और टूनामेंट के 18 सत्रों में एक टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र खिलाड़ी विराट कोहली और युवा खिलाड़ी रिंकू सिंह को 'गोल्ड बनाम बोल्ड बहस में शामिल होने के लिए पेश किया।

कोहली ने कहा, बोल्ड पीढ़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन पुरानी पीढ़ी यहीं रहने वाली है।

रिंकू ने कहा, "हम निश्चित रूप से उन्हें टक्कर दे सकते हैं।"

रिंकू और कोहली दोनों ने हंसी-मजाक किया और इस सेगमेंट को खत्म करने के लिए बॉलीवुड के बादशाह के साथ डांस किया। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया, आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल, बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और बीसीसीआई कोषाध्यक्ष प्रभतेज सिंह भाटिया को भी मंच पर आमंत्रित किया गया था। बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने कोहली को आईपीएल सीजन 18 का विशेष स्मृति चिन्ह भेंट किया।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) दो टीमें हैं जो सीजन की शुरूआत करेंगी और दिलचस्प बात यह है कि दोनों टीमें नए नेतृत्व के तहत अपना अभियान शुरू करेंगी, जिसमें अजिंक्य रहाणे कोलकाता की कप्तानी करेंगे जबकि रजत पाटीदार आरसीबी की कमान संभालेंगे।

एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि इन दोनों टीमों का पहले संस्करण के शुरूआती मैच में आमना-सामना हुआ था। केकेआर अपने खिताब की रक्षा के लिए मजबूत शुरूआत की उम्मीद कर रही होगी, जबकि पाटीदार की अगुवाई वाली आरसीबी इस बार पिछले प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश करेगी। पिछले साल टी20 विश्व कप में भारत की जीत के बाद खेल के सबसे छोटे प्रारूप से संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय दिग्गज विराट कोहली को पहली बार टी20 प्रारूप में देखना घरेलू प्रशंसकों के लिए भी एक शानदार नजारा होगा।

दोनों टीमें आईपीएल इतिहास में 34 बार आमने-सामने हुई हैं, लेकिन संयोग से, दोनों टीमें 2008 में उद्घाटन संस्करण के उद्घाटन मैच में खेली थीं, जिसमें केकेआर ने 20 जीत के साथ बढ़त हासिल की थी। दोनों पक्षों के बीच पिछले पांच मैचों में, रुझान कोलकाता के पक्ष में बदल गया है क्योंकि उन्होंने चार मौकों पर जीत हासिल की है। केकेआर के खिलाफ आरसीबी की आखिरी जीत आईपीएल 2022 सीजन में आई थी।

93 वर्षीय पानी देवी ने जीते तीन गोल्ड

■ बीएनटी न्यूज

राजस्थान के बीकानेर की 93 वर्षीय पानी देवी गोदारा ने हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित 45वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट, 100 मीटर दौड़ और डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी शानदार फिटनेस और खेल की क्षमताओं को साबित किया है। पानी देवी का अगला लक्ष्य अगस्त में स्वीडन में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश के लिए पदक जीतना है। इसके अलावा, सितंबर में इंडोनेशिया में होने वाली एशियन मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भी उनका चयन हुआ है, जहां वह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।

बीकानेर की चौधरी कॉलोनी में रहने वाली पानी देवी अपनी गायों और भैंसों की सेवा करते हुए अपनी फिटनेस पर भी पूरा ध्यान देती हैं। वह नियमित रूप से व्यायाम करती हैं, जो उनकी सफलता का मुख्य कारण है। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण से यह साबित होता है कि उम्र केवल एक संख्या है और अगर इच्छाशक्ति मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

पानी देवी की यह उपलब्धि न केवल बीकानेर, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उनके संघर्ष और मेहनत से आज की महिलाओं को यह सीखने को मिलता है कि शिक्षा और सही दिनचर्या अपनाकर किसी भी आयु में सफलता प्राप्त की जा सकती है।

पानी देवी ने कहा, "मुझे विदेश जाने की बहुत खुशी है। मुझे यह खेल खेलते हुए तीन साल हो गए हैं। इन तीन साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है। उसी दम पर मैंने यह सब हासिल किया है। मुझे उम्मीद है कि विदेश से भी मैं मेडल जीतकर लाऊंगी। मुझे खेलकूद में बहुत खुशी मिलती है और मैं हमेशा इसे जारी रखना चाहती हूं। मुझे खेलना-कूदना बहुत अच्छा लगता है। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं विदेश जाऊं, वहां खेलूं-कूदूं और मेडल जीतकर लाऊं। इसके लिए मैं यहां तैयारी भी करती हूं।"

केकेआर के खिलाफ आरसीबी की सात विकेट से 'विराट' जीत, कोहली ने लगाई हाफ सेंचुरी

■ बीएनटी न्यूज

ईडन गार्डन्स में आईपीएल 2025 के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को सात विकेट से हरा दिया। आरसीबी के लिए पूर्व कप्तान विराट कोहली ने 59 रनों की शानदार पारी खेली।

विराट ने पारी के दौरान चार चौके और 3 गगनचुंबी छक्के भी जड़े। विराट का स्ट्राइक रेट 163.89 रहा। वहीं, उनके साथ फिल साल्ट ने भी शानदार बल्लेबाजी की। केकेआर से मिले 175 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी को विराट के साथ फिल साल्ट ने एक ठोस शुरूआत दी। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 95 रनों की साझेदारी की। दोनों की इस साझेदारी ने टीम की जीत के लिए एक मजबूत नींव रखी। हालांकि, 95 रन पर आरसीबी को फिल साल्ट के तौर पर पहला झटका लगा। साल्ट ने 31 गेंदों पर 56 रन की पारी खेली। पारी के दौरान उन्होंने 9 चौके और दो छक्के लगाए। साल्ट के आउट होने के बाद दूसरे छोड़ पर विराट ने पारी को संभाले रखा। वहीं, आरसीबी के लिए पहली बार कप्तानी कर रहे रजत पाटीदार ने भी तूफानी पारी खेली। उन्होंने 16 गेंदों पर 34 रन बनाए। जिसमें 5 चौके और एक छक्का लगाया। 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर लियाम

लिविंगस्टोन ने चौका जड़कर टीम को इस सीजन की पहली जीत दिलाई।

इसी के साथ ही टीम ने अपना खाता 2 अंकों के साथ खोल लिया है। इसके पहले आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। केकेआर ने अपना पहला विकेट क्विंटन डी कॉक के रूप में जोश हेजलवुड की गेंद पर पहले ओवर में ही गंवा दिया। लेकिन इसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए दूसरे विकेट के लिए 103 रन की तूफानी साझेदारी की। एक समय केकेआर का स्कोर 10 ओवरों में एक विकेट के नुकसान पर 107 रन था और टीम आसानी से 200 की ओर जाती दिख रही थी। लेकिन इसके बाद जल्दी-जल्दी अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण के विकेट गिरे और फिर आरसीबी के स्पिनर्स और बाद में तेज गेंदबाज मैच पर छा गए। टीम 200 क्या 175 तक भी नहीं पहुंच पाई।

रहाणे ने मात्र 31 गेंदों पर 56 रन में छह चौके और चार छक्के लगाए, जबकि नारायण ने 26 गेंदों पर 44 रन में पांच चौके और तीन छक्के लगाए। इस साझेदारी के टूटने और दोनों के जल्दी-जल्दी आउट होने के बाद बाकी के बल्लेबाज विकेट पर टिकने का धैर्य नहीं दिखा पाए। लेफ्ट आर्म स्पिनर कुणाल पांड्या ने 29 रन पर तीन विकेट लेकर केकेआर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। वेंकटेश अय्यर छह और रिंकू सिंह 12 रन बनाकर आउट हुए। आंद्रे रसेल चार रन ही बना सके। अंगकृश रघुवंशी ने दो चौकों और एक छक्के की मदद से 30 रन बनाकर केकेआर को लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचाया। हेजलवुड ने 22 रन पर दो विकेट लिए, जबकि यश दयाल, रसिख सलाम और सुयश शर्मा को एक-एक विकेट मिला।

मौजूदा चैंपियन मीनाक्षी ने महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में नीतू घनघस को चौंकाया

मौजूदा मिनिममवेट (45-48 किग्रा) राष्ट्रीय चैंपियन मीनाक्षी ने 8वीं इलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक हाईवोल्टेज क्वार्टर फाइनल मुकाबले में राष्ट्रमंडल और विश्व चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता नीतू घनघस को हराकर अपने खिताब की रक्षा करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया।

अखिल भारतीय पुलिस (एआईपी) का प्रतिनिधित्व करते हुए, एशियाई चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता ने सोमवार को एलीट दावेदारों की लड़ाई में नीतू को कड़े मुकाबले में 4-1 के स्प्लिट डिसीजन से हराया।

उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन के सहयोग से बीएफआई द्वारा आयोजित यह चैंपियनशिप 20 से 27 मार्च, 2025 तक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी है। सप्ताह भर चलने वाले इस टूनामेंट में 24 राज्य इकाइयों के 180 मुक्केबाज 10 भार श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जो विश्व मुक्केबाजी तकनीकी और प्रतियोगिता नियमों का पालन करता है। इसमें एक मिनट के ब्रेक के साथ 3-3 मिनट के राउंड शामिल हैं।

भारत की प्रो-रेसलिंग क्रांति के लिए मंच तैयार किया

■ बीएनटी न्यूज

रेसलिंग एक्सट्रीम मेनिया (डब्ल्यूएक्सएम) ने अपने बहुप्रतीक्षित ग्राउंड जीरो टेपिंग्स को पूरा करते हुए भारत में पेशेवर कुश्ती के विकास में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर ली है।

गुरुग्राम स्थित डब्ल्यूएक्सएम की आधुनिक यूनिट में हाई-ऑक्टेन मैच देखने को मिले, जिनमें दुनिया भर में विख्यात सुपरस्टार जैसे राज-द महाराजा (उर्फ. जिंदर महल), एक्सेल टिशर, सैमुरे डेल सोल (कलिस्टो), डिजाक और प्रो-रेसलिंग की प्रतिभाशाली खिलाड़ी शामिल हुए। पिछले कई सालों से भारत के प्रो-रेसलर्स को अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए कोई उचित मंच नहीं मिला है। जो खिलाड़ी इस क्षेत्र में करियर बनाने के सपने देखते हैं, उन्हें अपने देश में कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, ऐसे में उन्हें मजबूरन विदेशों की ओर रुख करना पड़ता है। डब्ल्यूएक्सएम रेसलिंग की स्वदेशी प्रतिभा को विश्वस्तरीय बुनियादी सुविधाएं, सर्वोच्च स्तर की कोचिंग प्रदान कर इस क्षेत्र में बदलाव ला रहा है। यह भारतीय रेसलर्स को ऐसा मंच प्रदान करता है, जहां वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के सामने अपने आप को साबित कर सकें।

उनकी आधुनिक सुविधाएं और अखाड़े को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह रेसलिंग के सुपरस्टार्स की अगली पीढ़ी को विकसित होने का मौका देती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के उपकरणों, एथलीट्स के विकास के लिए विशेष प्रोग्रामों तथा रेसलिंग के विश्वस्तरीय दिग्गजों के मार्गदर्शन के द्वारा डब्ल्यूएक्सएम भारतीय प्रतिभा

को हर वो सहयोग प्रदान कर रहा है, जो उन्हें रेसलिंग के क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए जरूरी है।

इस अवसर पर डब्ल्यूएक्सएम के सीओओ जीत ने कहा, "भारतीय रेसलर्स लंबे समय से सही अवसरों के इंतजार में हैं और डब्ल्यूएक्सएम उनके लिए वही अवसर लेकर आया है। हम उन्हें विश्वस्तरीय प्रशिक्षण, प्रतिस्पर्धी प्लेटफॉर्म और विश्वस्तरीय मंच पर अपने आप को साबित करने का मौका देते हैं। यह सिर्फ एक शुरूआत है।"

डब्ल्यूएक्सएम के सीईओ ऋषि ने कहा, "हमें प्रशंसकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली है। अखाड़े में दिख रही ऊर्जा, सोशल मीडिया पर उत्साह और दर्शकों का प्यार इस बात की पुष्टि करता है कि भारत रेसलिंग के क्षेत्र में अपनी नई क्रांति लाने के लिए तैयार है। हम कुछ ऐसा ला रहे हैं जो समय की कसौटी पर खरा उतरेगा।"

राज-द महाराजा (उर्फ. जिंदर महल), इंटरनेशनल रेसलर, डब्ल्यूएक्सएम ने कहा, "दुनिया की निगाहें डब्ल्यूएक्सएम पर टिकी हैं। यूएस, कनाडा, यूके, जर्मनी, जापान और दुनिया भर के देशों से अंतर्राष्ट्रीय सितारे भारतीय रिंग में उतर रहे हैं। यह भारत में उत्पन्न हुआ विश्वस्तरीय प्रोडक्ट है, जल्द ही दुनिया के हर कोने के प्रशंसक हमारे इस प्रोडक्ट को देख रहे होंगे।"

यह हर उस भारतीय के बारे में है जिसे भरोसा है कि हम कुछ विश्वस्तरीय बना सकते हैं, कुछ ऐसा जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा।

डब्ल्यूएक्सएम प्रो-रेसलिंग को भारत के टॉप दो स्पोर्ट्स में लाने के मिशन की ओर कार्यरत है, इसकी लोकप्रियता को क्रिकेट के समकक्ष लाना चाहता है। उच्च क्षमता के प्रोडक्शन, स्टोरीटेलिंग एवं सामरिक साझेदारियों के माध्यम से डब्ल्यूएक्सएम ऐसे सिस्टम का निर्माण कर रहा है, जो खेल और मनोरंजन (स्पोर्टेनमेंट) का बेहतरीन संयोजन होगा और सुनिश्चित करेगा कि हर मैच न सिर्फ एक प्रतियोगिता बल्कि एक यादगार अनुभव बन जाए अनुभव बन जाए।

बीसीसीआई ने की चैंपियंस ट्रॉफी जीत के पुरस्कार वितरण की घोषणा

15 खिलाड़ियों-कोच को 3-3 करोड़ रुपये

■ बीएनटी न्यूज

बीसीसीआई सचिव सैकिया ने कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया ने आईएएनएस को बताया है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने वाली टीम इंडिया के लिए घोषित 58 करोड़ रुपये के नकद इनाम में से 15 खिलाड़ियों और मुख्य कोच गौतम गंभीर को 3-3 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने इस आठ टीमों के टूनामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने ग्रुप ए में बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया। फिर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद, फाइनल में न्यूजीलैंड को मात देकर 9 मार्च को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में अपनी तीसरी चैंपियंस ट्रॉफी जीती।

इस इनाम की राशि उन खिलाड़ियों को भी मिलेगी जो टूनामेंट में एक भी मैच नहीं खेले, जैसे अर्शदीप सिंह,

ऋषभ पंत और वाशिंगटन सुंदर।

सैकिया ने यह भी बताया कि बाकी कोचिंग स्टाफ - बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक, सहायक कोच अभिषेक नायर और रयान टेन डोशेट, फील्डिंग कोच टी दिलीप, और फिजियोथेरेपिस्ट कमलेश जैन व योगेश परमार, टीम डॉक्टर आदित्य दफ्तरी, थ्रोडाउन विशेषज्ञ राघवेंद्र द्विगी, नुवान उडेनेक और दयानंद गरानी, मसाजर चेतन कुमार, राजीव कुमार और अरुण कानाडे, और कंडीशनिंग कोच सोहम देसाई को 50-50 लाख रुपये मिलेंगे।

इसके अलावा, बीसीसीआई से जुड़े अन्य अधिकारी जैसे वीडियो एनालिस्ट हरी प्रसाद मोहन, लायजन ऑफिसर और मीडिया मैनेजर को 25-25 लाख रुपये मिलेंगे।

बीसीसीआई सचिव ने बताया कि चयन समिति के प्रमुख अजीत अगरकर को 30 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि अन्य सदस्य - सुब्रतो बनर्जी, अजय रात्रा, एस शरत और शिव सुंदर दास को 25-25 लाख रुपये दिए जाएंगे। सैकिया ने यह भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने विजेता भारतीय टीम को लगभग 19.45 करोड़ रुपये इनाम में दिए, जो केवल खिलाड़ियों में बांटे गए। प्रत्येक खिलाड़ी को 1.43 करोड़ रुपये मिले।

सैकिया ने जारी बीसीसीआई के बयान में कहा, "खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ को यह इनाम देना हमारे लिए गर्व की बात है। उनकी मेहनत और रणनीतिक खेल की बदौलत भारत विश्व क्रिकेट में शीर्ष पर पहुंचा है। यह जीत सफेद गेंद क्रिकेट में भारत की श्रेष्ठता साबित करती है, और हमें विश्वास है कि टीम आने वाले वर्षों में और ऊंचाइयों को छुएगी।"

उन्होंने आगे कहा, "खिलाड़ियों द्वारा दिखाए गए समर्पण और प्रतिबद्धता ने एक नया मानदंड स्थापित किया है, और हमें विश्वास है कि भारतीय क्रिकेट वैश्विक मंच पर अपना मानक ऊंचा करता रहेगा।"

मियामी ओपन : निक किर्गियोस ने 896 दिनों में दर्ज की अपनी पहली जीत

■ बीएनटी न्यूज

निक किर्गियोस ने मियामी ओपन में अमेरिकी क्वालीफायर मैकेंजी मैकडोनाल्ड को हराकर 2022 के बाद अपना पहला एटीपी टूर मैच जीता। 29 वर्षीय किर्गियोस पिछले 18 महीनों से पैर और कलाई की चोटों से परेशान थे और इस साल की शुरूआत में उन्होंने दोबारा खेलना शुरू किया।

कलाई की लगातार तकलीफ के कारण किर्गियोस पिछले दो साल से टेनिस से दूर थे। कुछ हफ्ते पहले इंडियन वेल्स में उन्हें पहले ही दौर में मैच छोड़ना पड़ा था, लेकिन मियामी ओपन में उन्होंने मैकडोनाल्ड को 3-6, 6-3, 6-4 से हराकर शानदार वापसी की।

अक्टूबर 2022 में जापान ओपन में दूसरे दौर के मुकाबले के बाद से ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को जीत नहीं मिली थी और यह अब यह जीत 896 दिनों के

बाद आई। कलाई की चोट के चलते किर्गियोस का करियर खतरे में पड़ गया था, लेकिन अब इस जीत को वह अपनी वापसी का सबसे बड़ा पल मानते हैं। उन्होंने कहा, "यह मेरे लिए लंबा सफर रहा है। कई बार तो मैच खेलना भी डराने वाला था कि मैं इसे पूरा कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन अब एक जीत हासिल करके यह महसूस करना कि मैं फिर से इस खेल का हिस्सा हूं, बहुत खास अहसास है।"

अब उनका अगला मुकाबला 22वीं वरीयता प्राप्त करेन खाचानोव से होगा, जिनसे वह 2022 यूएस ओपन के क्वार्टरफाइनल में हार चुके हैं। इस बार किर्गियोस उस हार का बदला लेना चाहेंगे।

किर्गियोस, जो अब तक अपने सातों खिताब हार्ड कोर्ट पर जीत चुके हैं, मियामी ओपन में पांच बार चौथे दौर तक पहुंचे हैं। यह टूनामेंट उनके लिए सबसे सफल मास्टर्स 1000 प्रतियोगिता रही है।

उन्होंने कहा, "मियामी में खेलते हुए मुझे हमेशा अच्छा महसूस होता है। मैं अपने प्रदर्शन पर गर्व महसूस कर रहा हूं। इस स्तर पर आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी होती है।"

जिसको मानते थे अपना आदर्श, उसी के रिप्लेसमेंट के तौर पर इंडस्ट्री में मिली एंट्री

■ बीएनटी न्यूज

हिंदी सिनेमा की एक ऐसी रूहानी आवाज जिनके सुरों में इतनी जान थी कि वह हर किसी के दिल को छू ले। एक ऐसी आवाज जिसके साथ सुबह की शुरूआत लोग आज भी करते हैं। जिनकी आवाज में भजन हो या फिर देशभक्ति गीत, एक बार कोई सुन ले तो वह मदहोश हो जाए। एक ऐसा फनकार जिनकी आवाज सुनकर मो. रफी ने कह दिया था कि 'हम दोनों साथ में गाने नहीं गाएंगे, क्योंकि हमारी आवाजें मिलती हैं।'

महेंद्र कपूर इंडस्ट्री का हिस्सा तब बने जब रफी साहब इंडस्ट्री में बड़े गायक बन चुके थे। महेंद्र कपूर ने रियलिटी शो मेट्रो मर्फी प्रतियोगिता जीती और उन्हें कॉन्टेस्ट जीतने के बाद फिल्म 'नवरंग' में गाना गाने का अवसर प्राप्त हुआ था। महेंद्र कपूर हनुमान जी के बड़े भक्त थे, ऐसे में भगवान के आशीर्वाद से उनके आलाप का दायरा भी उतना ही विशाल था।

अमृतसर पंजाब में 9 जनवरी 1934 को जन्मे महेंद्र को बचपन से ही गाने का शौक था। मोहम्मद रफी की गायकी का उन पर काफी ज्यादा प्रभाव था। वह एक सफल पार्श्वगायक बनना चाहते थे। फिर सितारों ने उनका साथ भी दिया और उन्होंने रियलिटी शो मेट्रो मर्फी प्रतियोगिता जीत ली। इसके बाद उनका मुंबई आने का रास्ता साफ हो गया। फिर 1953 में आई फिल्म 'मदमस्त' में साहिर लुधियानवी के लिखे गाने 'आप आए तो खयाल-ए-दिल-ए नाशाद आया' को महेंद्र कपूर ने अपनी आवाज दी। हालांकि, 1958 में फिल्म 'नवरंग' में 'आधा है चंद्रमा रात आधी' गाने में उन्होंने जब अपनी आवाज दी तो उन्हें लोगों के बीच पहचान मिली।

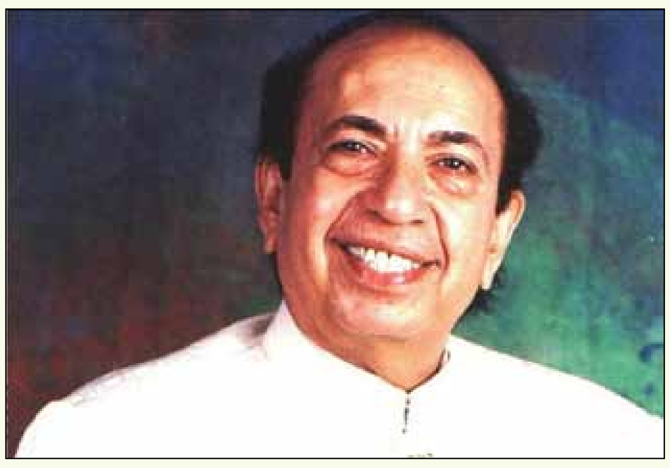

फिल्म 'उपकार' के गीत 'मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती..' ने तो उन्हें एक अलग ही मुकाम दे दिया। इस गाने के लिए उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवॉर्ड भी मिला।

मनोज कुमार तब देशभक्ति फिल्मों में अभिनय के लिए जाने जाते थे। वह महेंद्र कपूर और उनकी आवाज को अपने लिए लकी मानते थे। 'नीले गगन के तले', 'तुम अगर साथ देने का वादा करो', 'बीते हुए लम्हों की कसक', 'चलो एक बार फिर से अजनबी', 'किसी पत्थर की मूरत' जैसे रोमांटिक गानों को भी महेंद्र कपूर ने जब अपनी आवाज दी तो उनके आवाज की मधुरता लोगों के कानों में चीनी की चाशनी की तरह घुल गई।

जब महेंद्र कपूर ने गायक के तौर पर बॉलीवुड में पदार्पण किया तब हिंदी सिनेमा में संगीत का स्वर्ण काल चल रहा था और मो. रफी, किशोर कुमार, मन्ना डे, तलत महमूद जैसे दिग्गज गायक पहले से मौजूद थे और उनकी आवाज लोगों को अपना दीवाना बना चुकी थी।

ऐसे में महेंद्र कपूर के लिए अपनी जगह बनाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि उनकी आवाज रफी साहब से मिलती थी। वह आए भी इंडस्ट्री में मोहम्मद रफी के रिप्लेसमेंट के तौर पर ही थे। लेकिन, उनका संगीत के प्रति जुनून और उनकी काम के प्रति दीवानगी ही थी, जिसने उन्हें 'वॉयस ऑफ इंडिया' का नाम दिलाया।

एक और बात है बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म निमार्ता बीआर चोपड़ा और मोहम्मद रफी के बीच मनमुटाव ने ही महेंद्र कपूर को इंडस्ट्री में पांव जमाने में मदद की।

बीआर चोपड़ा चाहते थे कि मोहम्मद रफी केवल उनकी फिल्मों में गाएं, यह मोहम्मद रफी को मंजूर नहीं था। इसी बात से नाराज बीआर चोपड़ा ने इंडस्ट्री को एक और मोहम्मद रफी देने का फैसला कर लिया, तब उनकी नजर महेंद्र कपूर पर पड़ी।

1972 में भारत सरकार ने महेंद्र कपूर को कला के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। 27 सितंबर 2008 को दिल का दौरा पड़ने से महेंद्र कपूर का निधन हो गया।

■ बीएनटी न्यूज

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर बगैर नाम लिए कसे तंज को लेकर कॉमेडियन कुणाल कामरा फिर सुर्खियों में हैं। कॉमेडियन के खिलाफ मुंबई के एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। हालांकि, यह कोई पहली बार नहीं है जब कुणाल मुसीबतों में फंसते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी वह अपने बयान को लेकर हंगामा बरपा चुके हैं।

कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने यूट्यूब चैनल पर महाराष्ट्र की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए एक वीडियो अपलोड किया। वीडियो में उन्होंने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को 'गद्दार' बताया। इस वीडियो की एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के सदस्यों ने तीखी आलोचना की और आक्रोश जताया। वीडियो के बाद शिंदे गुट के नेता राहुल कनाल ने मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में कामरा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

शिवसेना के विधायक मर्जी पटेल ने एमआईडासी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(1), 353(2) और 356(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

ओला फाउंडर भाविश अग्रवाल से भिड़े थे कुणाल कामराः- कामरा साल 2024 में ओला फाउंडर भाविश अग्रवाल से कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री, सर्विस को लेकर तीखी बहस हुई थी। कामरा ने ओला ई-स्कूटर सर्विस सेंटर की एक तस्वीर शेयर कर ओला की खस्ताहाल सेवाओं पर सवाल उठाया था, जिसे लेकर दोनों के बीच सोशल मीडिया पर खूब बहस हुई थी। कुणाल और भाविश के बीच बहस इतनी बढ़ी कि भाविश ने उन्हें ये तक कह दिया कि हमारे लिए काम करो, तुम्हारे फेल कॉमेडी करियर से ज्यादा पैसे देंगे।

राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोपः- साल 2022 में कॉमेडियन कुणाल कामरा पर भारतीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगा था। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की एक एडिट की गई तस्वीर शेयर की थी। कामरा के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज को एक राजनीतिक दल के ध्वज से बदलने के लिए परिवाद दाखिल की गई थी। परिवाद वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने दायर किया था। उन्होंने कामरा के सोशल मीडिया पोस्ट को भारतीय राष्ट्रीय झंडे का अपमान बताया था।

इंडिगो ने लगाया था 6 महीने का प्रतिबंधः- कुणाल को साल 2020 में इंडिगो और स्पाइसजेट समेत 4 एयरलाइन्स ने प्रतिबंधित कर दिया था। उन पर एक पत्रकार को फ्लाइट में परेशान करने का आरोप था। इंडिगो ने कामरा पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाया था।

'कर्ज' के लिए ट्रॉफी मिलते ही नीतू सिंह ने आसमान की ओर देखा, पति ऋषि कपूर को किया याद

■ बीएनटी न्यूज

मशहूर फिल्म निमार्ता-निर्देशक सुभाष घई ने सोशल मीडिया पर अभिनेत्री नीतू कपूर की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह अपने दिवंगत पति ऋषि कपूर की ओर से ट्रॉफी प्राप्त करती दिखीं।

फिल्म निमार्ता-निर्देशक सुभाष घई ने इंस्टाग्राम पर मुंबई में चल रहे रेड लॉरी फिल्म फेस्टिवल की एक तस्वीर शेयर की। तस्वीर में नीतू ट्रॉफी पकड़े हुए दिखाई दे रही हैं।

उन्होंने कैप्शन में एक लंबा नोट भी लिखा, "रेड लॉरी फिल्म फेस्टिवल में 'कर्ज' की रिलीज के 45 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ट्रॉफी प्राप्त करते हुए जब नीतू ऋषि कपूर ने अपने पति ऋषि कपूर को भगवान की ओर देखते हुए श्रद्धांजलि दी। यह हम सभी के लिए वास्तव में एक भावनात्मक क्षण था। हमने ऋषि कपूर को एक बेहतरीन अभिनेता और व्यक्ति के रूप में याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी।"

'कर्ज' एक सफल फिल्म है जो पुनर्जन्म पर आधारित है। इस फिल्म का रीमेक साल 2008 में हिंदी में किया गया, जिसमें हिमेश रेशमिया ने मुख्य भूमिका निभाई थी।

इससे पहले घई ने एक पोस्ट शेयर कर बताया था कि साल 1980 में रिलीज 'कर्ज' की पटकथा को उन्होंने कैसे लिखा। फिल्म से जुड़े एक सीन का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि एक सीन के इर्द-गिर्द उन्होंने फिल्म की पटकथा लिख डाली थी।

'कर्ज' से जुड़े एक सीन की तस्वीर को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए सुभाष घई ने लिखा, फिल्म 'कर्ज' का निर्माण केवल इस एक सीन की वजह से हुआ। एक ऐसा क्षण जब मां की आत्मा अपने मरे हुए बेटे की आत्मा को पहचान जाती है और उसके बेटे मोंटी को छोड़कर हर कोई हैरान रह जाता है। मैंने इस सीन के इर्द-गिर्द पूरी कहानी की पटकथा लिख डाली थी। कभी नहीं सोचा था कि यह एक कल्ट क्लासिक होगी और 45 साल बाद भी इसकी चर्चा होगी। एक पोस्ट में सुभाष घई ने बताया था कि उनकी फिल्म निर्माण कंपनी 'मुक्ता आर्ट्स' कलाकारों की नहीं बल्कि उन लेखकों और निर्देशकों की तलाश कर रही है, जो पैन सिनेमा के लिए बेहतरीन काम कर सकें।

घई ने बताया कि वह दर्शकों के लिए फिर से कुछ नया और शानदार लेकर आने के लिए तैयार हैं। 'कर्ज' का रेड लॉरी फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर 21 मार्च को सुबह 11 बजकर 30 मिनट पर पीवीआर बीकेसी बांद्रा, मुंबई में हुआ।

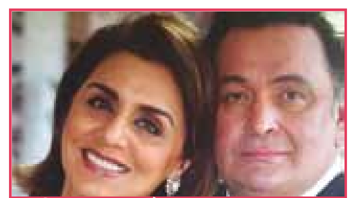

नीतू कपूर ने बताया, 'कर्ज' की शूटिंग के दौरान वह ऋषि कपूर को डेट कर रही थीं

'कर्ज' टीम के रीयूनियन के अवसर पर निर्देशक सुभाष घई, सिमी गरेवाल और टीना अंबानी भी उपस्थित थे।

अपने दिवंगत पति को श्रद्धांजलि देते हुए नीतू ने खुलासा किया कि वह 'कर्ज' की शूटिंग के दौरान ऋषि को डेट कर रही थीं और जून में जब फिल्म रिलीज हुई, तब तक वे शादीशुदा थे।

'जाट' के ट्रेलर की रिलीज डेट आगे बढ़ाई

■ बीएनटी न्यूज

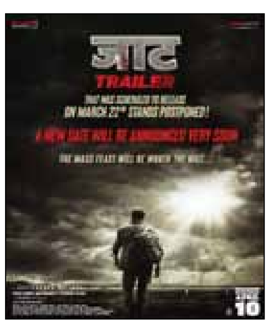

निर्देशक गोपीचंद मालिनेनी की एक्शन फिल्म 'जाट' के निमार्ताओं ने जानकारी दी है कि शनिवार को लॉन्च होने वाले फिल्म के ट्रेलर को स्थगित किया जा चुका है। निमार्ताओं ने बताया कि नई तारीख जल्द जारी की जाएगी।

फिल्म का निर्माण कर रहे प्रसिद्ध प्रोडक्शन हाउस मैत्री मूवी मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा,'जाट ट्रेलर की रिलीज स्थगित कर दी गई है! जल्द ही नई तारीख की घोषणा की जाएगी। जाट 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वैसाखी विद जाट।"

तेलुगू निर्देशक गोपीचंद मालिनेनी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विनीत कुमार सिंह, सैयामी खेर और रेजिना कैसंड्रा जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म का संगीत तेलुगू और तमिल संगीत निर्देशक थमन एस ने तैयार किया है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी ऋषि पंजाबी ने की है और संपादन नवीन नूली ने किया है, जबकि अविनाश कोला ने प्रोडक्शन डिजाइन किया है।

फिल्म में रणदीप हुड्डा खलनायक के किरदार में नजर आएंगे। उन्होंने फिल्म में अपने किरदार 'रणतुंगा' में ढलने के लिए वजन बढ़ाने के साथ ही अपनी आवाज के उतार-चढ़ाव पर भी काम किया है।

प्रोडक्शन से जुड़े एक करीबी सूत्र ने बताया, 'खलनायक हो या हीरो का किरदार, रणदीप उसमें डूब जाते हैं और उसे जीवंत करने के लिए खूब मेहनत करते हैं। 'जाट' भी इससे अलग नहीं है और अपने खलनायक किरदार रणतुंगा को मजबूत करने के लिए वह पहले दिन से ही जुटे हुए हैं।

उन्होंने बताया, 'रणदीप हुड्डा ने अपने किरदार के लिए बाल बढ़ाए और अपनी बॉडी पर काम किया ताकि उनका किरदार अधिक खतरनाक दिख सके।' यह पहली बार नहीं है जब रणदीप ने ट्रांसफॉर्मेशन किया है। इससे पहले अभिनेता साल 2016 में आई फिल्म 'सरबजीत' और 2024 में रिलीज फिल्म 'स्वतंत्र वीर सावरकर' की भूमिका निभाने के लिए भी अपनी बॉडी में बदलाव किए थे।

अमेरिकी टूर पर धूम मचाएंगी जैमी लीवर

■ बीएनटी न्यूज

अभिनेता-कॉमेडियन जॉनी लीवर की बेटी और कॉमेडियन जैमी लीवर भारत के बाद अब अमेरिका में दर्शकों को हंसाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एडिटेड वीडियो निराले अंदाज में शेयर किया।

जैमी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह मजेदार अंदाज में ट्रंप के एक एडिट भाषण के साथ अपने शो की मार्केटिंग कर रही हैं। वीडियो को शेयर करते हुए जैमी ने कैप्शन में लिखा, "उत्तरी अमेरिका टूर 'द जेमी लीवर शो'। स्थान जल्द ही अपडेट किए जाएंगे!'

वीडियो क्लिप में ट्रंप के अलग-अलग भाषणों के कुछ अंश लिए गए हैं, जिसमें ट्रंप के सवाल हैं और जैमी की हाजिर जवाबी भी है। ये जवाब भी उन आर्टिस्ट्स के अंदाज में हैं जिनकी मिमिक्री के लिए वह मशहूर हैं।

शुरूआत होती है जब ट्रंप बोलते हैं, "आप कहां से हैं?" इस पर जैमी करीना के 'कभी खुशी कभी गम' की पूजा वाला एटीट्यूड दिखाते हुए कहती हैं, "प्लीज, आपको नहीं पता मैं कहां से हूं, जहां से सुनीता विलियम्स हैं, मैं भी वहीं से हूं।"

जैमी की जैमिंग आगे बढ़ती है और फिर ट्रंप कहते सुने जा सकते हैं, "क्या आप थोड़ा तेज बोल सकती हैं?" इस पर जैमी करीना के 'पूजा अवतार' में कहती हैं, "ड्रामा ना करो, वो कौन है, जिसने मुझे मुड़कर नहीं देखा।"

एडिट किए हुए मजेदार बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है, जिसमें ट्रंप कहते हैं, "यही समस्या है कि मैं नहीं समझ पा रहा कि आप क्या कह रही हैं।" इस पर जैमी कंगना रनौत की तरह कहती हैं, "देखिए भारत एक खूबसूरत देश है और अमेरिका प्रेरणा है। कभी-कभी हममें प्रेरणा की कमी होती है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म करने में मदद करूंगी।"

ट्रंप कहते हैं, "शुभकामनाएं और शांति से रहें।" इस पर जैमी कहती हैं, "लेकिन ट्रंप जी, हम आपको शांति में नहीं रहने देंगे।" जैमी फिर कहती हैं, "हम आ रहे हैं 5, 6, 7 को जैमी लीवर शो के साथ उत्तरी अमेरिका में जल्द ही मिलते हैं।"

यहां पर उनके अंदर की फराह बाहर निकलती हैं और आखिर में आशा भोसले की मिमिक्री में फैंस को न्योता देते दिखती हैं।

उनके इस अंदाज पर नेटिजन्स अपनी हंसी नहीं रोक पाए। किसी ने कहा शानदार तो किसी ने लोट पोट होते इमोजी से दिल के जज्बात जाहिर किए।

जैमी कॉमेडियन और अभिनेता जॉनी लीवर की बेटी होने के साथ ही बेहद प्रतिभाशाली कलाकार हैं। उन्होंने साल 2012 में लंदन स्थित मार्केट रिसर्च एजेंसी विजनगैन में मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव के रूप में अपने करियर की शुरूआत की थी।

जैमी, कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं' में भी अपने अभिनय कौशल का प्रदर्शन कर चुकी हैं। इसके बाद वह 'हाउसफुल 4', 'भूत पुलिस' और विद्युत जामवाल अभिनीत 'क्रैक' में नजर आईं।

कल्कि कोचलिन को भारी पड़ा ज्यादा गौरी होना

बीएनटी न्यूज

एक्ट्रेस कल्कि कोचलिन ने फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने भले ही अब तक चुनिंदा फिल्में की हैं, लेकिन वे चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं के साथ अपनी तगड़ी एक्टिंग की बदौलत फैंस का दिल जीतने में सफल रहीं। कल्कि जल्द हीं मच अवेटेड वेब सीरीज 'मेड इन हेवन 2' में एक बार फिर से 'फैजा' के ...दार में दिखेंगी। देव डी और ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्मों में काम कर चुकीं कल्कि को एक्टिंग की दुनिया में कदम रखे एक दशक से ज्यादा समय बीत चुका है। कल्कि शैतान, शंघाई, एक थी डायन, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और गली बॉय मूवी में भी नजर आ चुकी हैं।

कल्कि ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें करिअर बनाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। कल्कि ने बताया कि ज्यादा गौरी होने से लोग उन्हें कैसी नजरों से देखते थे। उन्हें गौरे रंग के चलते काफी बातें सुननी पड़ती थीं। कल्कि ने कहा कि मैंने बचपन से भेदभाव देखा है। लोग समझते थे कि मैं ड्रग्स लेती हूं क्योंकि मेरे ग्रुप में मैं अकेली बहुत गौरी लड़की थी। इसमें मेरी गलती नहीं है कि मेरा रंग बहुत गौरा है।

कल्कि ने आगे बताया कि इतना ही नहीं गौरी होने से मेरे कैरेक्टर पर भी बहुत सवाल उठते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि गौरी लड़कियां कैरेक्टरलेस होती हैं। लेकिन जैसे ही मैं उन्हें तमिल में जवाब देती थी, तो वो लोग मुझे अक्का और सिस्टर कहने लगते थे।

मेरी भाषा सुनकर उनकी सोच बदल जाती थी। गौरतलब है कि कल्कि का जन्म पुडुचेरी में एक फ्रेंच परिवार में हुआ। उनके माता-पिता फ्रेंच मूल के हैं, लेकिन उनकी वेशभूषा और भाषा भारतीय ही रही। कल्कि कास्टिंग काउच की शिकार भी हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि मैंने एक फिल्म का ऑडिशन दिया था, जिसके लिए मुझसे कहा गया कि प्रोड्यूसर से मिलना पड़ेगा। जब मैं ऑफिस में प्रोड्यूसर से मिलने गई तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे लिए बड़ा मौका है। मैं तुम्हे और अच्छे से जानना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। मैं समझ गई कि ये कुछ गलत करना चाहता है। तभी मैंने कहा देखो, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूं। उल्लेखनीय है कि कल्कि की शादी साल 2011 में डायरेक्टर अनुराग कश्यप के साथ हुई थी। हालांकि साल 2015 में उनका तलाक हो गया।

मानसिक स्वास्थ्य ने मुझे कमजोर बना दिया : लेडी गागा

अभिनेत्री–गायिका लेडी गागा ने बताया है कि पांच साल पहले उन्हें मनोविकृति का अनुभव हुआ था।

'मिरर.को.यूके' की रिपोर्ट के अनुसार, 38 वर्षीय गायिका और अभिनेत्री ने न्यूयॉर्क टाइम्स के द इंटरव्यू पॉडकास्ट पर अपने मानसिक स्वास्थ्य संघर्ष के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि वह कुछ समय के लिए वास्तविकता से कट गई थीं।

हालांकि, उन्होंने अपने अब के मंगेतर माइकल पोलांस्की के साथ इस कठिन समय से उपजे एक 'विशेष' पल के बारे में भी बात की।

'मिरर.को.यूके' के अनुसार, 'पोकर फेस' गायिका ने बताया कि पांच साल पहले, मुझे मनोविकृति हुई थी। मैं कुछ समय के लिए वास्तविकता से गहराई से जुड़ी नहीं थी। इसने मुझे जीवन से पूरी तरह से दूर कर दिया, और कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद मैंने खुद को वापस पाया। उन्होंने बताया कि माइकल से मिलना उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था।

उन्होंने बताया कि "यह एक कठिन समय था और वास्तव में यह बहुत खास था जब मैं अपने साथी से मिली, क्योंकि जब मैं माइकल से मिली, तो मैं बहुत बेहतर स्थिति में थी, लेकिन मुझे याद है कि उन्होंने मुझसे बहुत पहले कहा था, 'मुझे पता है कि तुम जितनी खुश हो, उससे कहीं अधिक खुश हो सकती हो।'

सप्ताह की शुरूआत में अपना सातवां स्टूडियो एल्बम रिलीज करने वाली लेडी गागा ने स्वीकार किया कि ये शब्द सुनना चुनौतीपूर्ण था।

उन्होंने कहा कि मेरे लिए उसे यह कहते हुए सुनना वाकई मुश्किल था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह मेरे बारे में ऐसा सोचे। मैं चाहती थी कि वह मुझे एक खुशमिजाज, पूरी तरह से एकजुट व्यक्ति की तरह समझे।

माइकल के चरित्र की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, "जिस क्षण से मैं माइकल से मिली, वह शायद मेरे पूरे जीवन में मिले किसी भी व्यक्ति की तुलना में सबसे गर्मजोशी और दयालु स्वभाव का है।"

अपने खुलेपन के बावजूद, पुरस्कार विजेता गायिका ने स्वीकार किया कि अपने मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करना उनके लिए आसान नहीं है। उन्होंने कहा, "यह ऐसी चीज है जिसके बारे में बात करना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। मुझे इससे परिभाषित होने से नफरत है। ऐसा लगा कि मुझे इस पर शर्म आ रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर हम ऐसे समय से गुजरते हैं, तो हमें शर्मिंदा होना चाहिए। मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि यह बेहतर हो सकता है। मेरे लिए यह बेहतर हुआ और मैं इसके लिए आभारी हूं।"

फिल्मों में की गई हिंदी की दुर्गति, 'हिंग्लिश' ने बिगाड़ा खेल

■ बीएनटी न्यूज

निमार्ता–निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने न्यूज एजेंसी बीएनटी न्यूज से बातचीत में हिंदी भाषा की दुर्दशा पर दुख जताया। उन्होंने कहा, "अब्राहमिक विचारधारा या हिंग्लिश ने हिंदी को विनाश के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया है।"

राजनीति हो, देश का कोई ज्वलंत मुद्दा हो या फिल्म से जुड़ा कोई बेबाक सवाल, विवेक रंजन अग्निहोत्री बेधड़क बात रखने में यकीन रखते हैं। बीएनटी न्यूज से बातचीत में उन्होंने बॉलीवुड में हिंदी भाषा की स्थिति पर प्रकाश डाला।

अग्निहोत्री ने हिंदी भाषा को पहुंचे नुकसान की वजह भी बताई। उन्होंने कहा, 'फिल्मों में हिंदी का लगातार विनाश होता आया है। ऐसा नहीं है कि लोग हिंदी नहीं लिख सकते, लेकिन हमारे गाने धीरे–धीरे अब पाकिस्तान या पाकिस्तानी पंजाब से प्रभावित हो गए हैं। इन गानों में रब, खुदा, अल्लाह मिलेगा। इसमें अब्राहमिक विचारधारा भी मिलेगी। हिंदी को इससे काफी क्षति पहुंची है।'

निर्देशक के मुताबिक, हिंग्लिश ने हमारी सभ्यता और संस्कृति को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा, 'मैं देश भर में भ्रमण करता हूं। कभी भोपाल, कभी कानपुर, तो कभी आगरा या लखनऊ, और मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि हिंग्लिश बातचीत के लिए सही है। देश भर में मैंने हिंदी का हिंग्लिश के रूप में ऐसा इस्तेमाल नहीं देखा, जैसा फिल्मों में होता है। हिंग्लिश जैसी चीजें हमारी सभ्यता और संस्कृति पर भी गलत असर डालती हैं। जिस तरह की भाषा आज के समय में इस्तेमाल की जा रही है, वह गलत है। फूहड़ता की वजह से भाषा का नुकसान होता है और वह टूटने लगती है।'

विवेक रंजन ने बताया कि वह खासतौर पर अपनी फिल्मों में भाषा की शुद्धता को लेकर सचेत रहते हैं और क्लिष्टता को देखकर ही वह कलाकारों का चयन करते हैं। उन्होंने बताया, 'चयन के समय मैं सोचता हूं कि फिल्म में कलाकार ऐसे हों जो काव्य की समझ रखते हों और भाषा की शुद्धता को जानते हों, और इसी के सहारे मैं हिंदी के लिए कुछ योगदान दे सकता हूं।'

वर्कफ्रंट की बात करें तो विवेक की बंगाल त्रासदी और हिंदू नरसंहार पर बनी फिल्म 'द दिल्ली फाइल्सः बंगाल चैप्टर' जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के साथ अनुपम खेर, गोविंद नामदेव, पुनीत इस्सर, बब्बू मान और पालोमी घोष भी अहम भूमिकाओं में हैं।

'द दिल्ली फाइल्सः द बंगाल चैप्टर' का निर्देशन विवेक रंजन अग्निहोत्री ने किया है। फिल्म का निर्माण अभिषेक अग्रवाल और पल्लवी जोशी ने तेज नारायण अग्रवाल और आई एम बुद्धा प्रोडक्शंस के सहयोग से किया है।

'द दिल्ली फाइल्स' भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को बड़े पैमाने पर जीवंत करती है। फिल्म स्वतंत्रता दिवस पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

महिलाओं की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए काम : कृतिका कामरा

■ बीएनटी न्यूज

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृतिका कामरा जल्द ही अपने गृहनगर मध्य प्रदेश जाने वाली हैं, जहां वे उन महिला कारीगरों के साथ समय बिताएंगी, जो महिलाओं को सशक्त बनाने वाली उनकी एक खास पहल का अहम हिस्सा हैं।

उन्होंने यह पहल साल 2024 में शुरू की थी, जो महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद करती है। उनका कहना है कि वे हमेशा से अपने माध्यम का इस्तेमाल अगली पीढ़ी की महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए करना चाहती थीं।

कृतिका ने कहा, "मेरी मां मध्य प्रदेश से हैं, इसलिए मेरे लिए इस जगह से गहरा और व्यक्तिगत जुड़ाव है। बचपन में उन्होंने मुझे चंदेरी और उसके खूबसूरत लोगों और कपड़ों की कारीगरी से परिचित कराया।"

उन्होंने कहा, "जब हमने शुरूआत की थी, तो हमारा बड़ा लक्ष्य और कोशिश थी कि राज्य की महिलाओं, खासकर इस क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार दें, उन्हें सशक्त बनाएं और उनके काम को सामने लाएं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि रोजगार बढ़ाएं, इन महिलाओं को अपनी पहचान दें और उन्हें उचित कीमतों का अधिकार दिलाएं, ताकि उनकी जिंदगी बेहतर हो सके।"

उन्होंने आगे कहा, "एक एक्ट्रेस के रूप में मेरा हमेशा से मानना रहा है कि हमें अपनी आवाज का इस्तेमाल महिलाओं की अगली पीढ़ी को ऊपर उठाने के लिए करना चाहिए। हम आगे बढ़ने के साथ–साथ अधिक से अधिक महिलाओं के साथ काम करना जारी रखेंगे और उन्हें सशक्त बनाने में मदद करेंगे।"

बता दें कि कृतिका उन प्रतिभाशाली कारीगरों के साथ समय बिताने की योजना बना रही हैं, जो उनका समर्थन कर रहे हैं। कृतिका अवसर प्रदान करने और जमीनी स्तर की प्रतिभाओं के योगदान को पहचानने के महत्व को समझती हैं, खासकर मध्य प्रदेश के चंदेरी में गहरी सांस्कृतिक जड़ें रखने वाले हथकरघा और कपड़ा उद्योगों में।

'गांधारी' की शूटिंग खत्म, तापसी ने पढ़ा 'संघर्ष से संतोष' का पाठ

अभिनेत्री तापसी पन्नू ने 'गांधारी' की शूटिंग पूरी कर ली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर तापसी ने प्रशंसकों को यह जानकारी दी। अभिनेत्री ने बताया कि फिल्म बेहद खास है और वह जल्द ही खास और एकदम अलग हटकर नए अंदाज में दर्शकों के सामने आने के लिए तैयार हैं।

तापसी ने इंस्टाग्राम पर अपनी अपकमिंग फिल्म 'गांधारी' के सेट से कुल चार तस्वीरें शेयर की। पहली तस्वीर में वह आंखों पर पट्टी बांधकर बच्चों के साथ खेलती नजर आईं। वहीं, दूसरी तस्वीर में वह सह–अभिनेता इश्वाक सिंह, लेखिका कनिका ढिल्लों और निर्देशक देवाशीष मखीजा के साथ पोज देती दिखीं। तापसी ने एक चॉकलेट केक की तस्वीर भी शेयर की, जिस पर 'गांधारी इट्स ए रैप' लिखा था।

रणवीर-विक्की-आयुष्मान के साथ फिल्मों में काम करना चाहती है : नरगिस

■ बीएनटी न्यूज

बालीवुड एक्ट्रेस नरगिस फाखरी ने हाल ही में कुछ एक्टर्स के नाम साझा किए जिनके साथ वह काम करना चाहती है। एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि वह उनके साथ क्यों काम करना चाहती हैं। नरगिस ने कहा, सबसे पहले रणवीर सिंह होंगे। मुझे उनकी ऊर्जा और सेट पर उनकी इनटेंसिटी पसंद है।

मैं उनके साथ कोई पीरियड ड्रामा करना चाहूँगी। एक और एक्टर, जिससे मैं वास्तव में प्रभावित हूँ, वह हैं आयुष्मान खुराना। इन्होंने अपनी अनोखी लेकिन महत्वपूर्ण स्क्रिप्ट के चयन से इंडस्ट्री में अपने लिए एक अलग जगह बनाई है। मुझे राजकुमार राव की सादगी और सहजता बहुत पसंद है। जब भी वह स्क्रीन पर होते हैं, तो वाकई खास नजर आते हैं। विक्की कौशल भी बढ़िया काम कर रहे हैं। बेशक, अगर मैं अमिताभ बच्चन के साथ काम कर पाऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हां, मैं इम्तियाज अली की एक और फिल्म में रणबीर के साथ काम करना चाहूंगी, क्या यह मजेदार नहीं होगा? इस साल की शुरूआत में, नरगिस ने मद्रास कैफे में काम किया और जॉन अब्राहम के साथ काम करने के अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने 'रॉकस्टार' की री–रिलीज का जश्न भी मनाया। आखिरी बार टटलूबाज में नजर आईं, एक्ट्रेस फिलहाल कुछ दिलचस्प स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं। उम्मीद है कि वह इस साल के अंत में कुछ प्रोजेक्ट की घोषणा करेंगी। मालूम हो कि एक्ट्रेस नरगिस फाखरी ने जब से अपने अभिनय करियर की शुरूआत की है, तब से उन्होंने कई मशहूर हस्तियों के साथ काम किया है। अपनी पहली फिल्म में ही, रणबीर कपूर के साथ अभिनय करने के बावजूद, उन्होंने 'रॉकस्टार' में हीर के रूप में दर्शकों पर प्रभाव डाला। बाद में, उन्होंने जॉन अब्राहम, वरुण धवन और कई–कई एक्टर्स के साथ काम किया। हालाँकि, उन्होंने पहले इन एक्टर्स के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की थी।

मैं नहीं चाहती मेरे किसी भी गाने को रीक्रिएट किया जाएः श्रेया घोषाल

■ बीएनटी न्यूज

'बैरी पिया', 'सिलसिला ये चाहत का' जैसे अनगिनत हिट ट्रैक को अपनी आवाज देने वाली बहुमुखी और प्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल का कहना है कि वह नहीं चाहतीं कि उनके किसी भी गाने को रीक्रिएट किया जाए क्योंकि उनसे उनकी 'मजबूत यादें' जुड़ी हुई हैं।

श्रेया ने हिंदी, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम सहित 20 से अधिक भाषाओं में पेशेवर गायकी की है। उन्होंने इन सभी भाषाओं में 2,400 से अधिक गाने गाए जिनमें हिंदी में गाए गए 1,100 से अधिक गाने शामिल हैं।

उस प्रवृत्ति के बारे में बात करते हुए जहां मूल रचनाएं अक्सर मनोरंजन और रीमिक्स के साथ टकराती हैं, श्रेया ने बीएनटी न्यूज को बताया, 'हाल के दिनों में बहुत ज्यादा रीक्रिएशन नहीं हो रहे हैं। तीन–चार साल पहले ऐसा बहुत हो रहा था। मैं कुछ साल पहले इससे परेशान थी। लेकिन अब मुझे उतना कुछ होता नहीं दिख रहा है।'

उन्होंने कहा, "एक ही गाने के बार–बार दोहराए जाने से लोग काफी बोर भी हो गए हैं। जैसे ही आप देखते हैं कि गाना अच्छा नहीं है या अच्छा नहीं बना है, लोग तुरंत उसे अस्वीकार कर देते हैं। गाना अंततः लोगों को पसंद आना चाहिए। कलाकार दर्शकों की निराशा का जवाब दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सारे मौलिक काम हो रहे हैं।

श्रेया, जो 2014 में रिलीज हुए अपने गजल एल्बम 'हमनशीं' के लिए भी जानी जाती हैं, ने कहाः "मुझे लगता है कि हमें आज के समय में हो रहे अद्भुत स्वतंत्र संगीत का भी जश्न मनाना चाहिए। सिर्फ फिल्मी संगीत ही नहीं, बल्कि नए कलाकार भी मुझे सुनने को मिलते हैं, ऐसा तीन–चार साल पहले नहीं हो रहा था। यह नया है, और हम बहुत अलग समय में हैं। अब, भूमिगत कलाकार धूम मचा रहे हैं। आज की पीढ़ी अलग तरह से संगीत सुन रही है और उनके पास बहुत मजबूत विकल्प हैं। समय बदल रहा है और संगीत को उसके अनुरूप प्रासंगिक होना होगा।

क्या वह चाहती हैं कि उनके गाने रीक्रिएट किए जाएं?

इसके जवाब में 39 वर्षीय गायिका ने कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी गाना रीक्रिएट किया जाए, मेरा कोई भी गाना नहीं। यहां तक कि अगर मुझसे खुद इसे रीक्रिएट करने के लिए भी कहा जाए तो मैं शायद ना ही कहूंगी। मेरे बहुत सारे गाने हैं जिनसे मेरी बहुत गहरी यादें जुड़ी हुई हैं। ये भावुक बातें हैं। उन्होंने कहा, हो सकता है मेरी कुछ भावनाएँ हों, लेकिन दूसरे श्रोताओं की नहीं। लेकिन, मेरे पास उस गीत की, उस गीत के बनने की प्रक्रिया की एक व्यक्तिगत स्मृति है। इसलिए, शायद मेरे लिए अपने गानों के रीक्रिएशन की सहमति देना मुश्किल होगा।

श्रेया ने हाल ही में एक नए सिंगल 'सुन्न बेलिया' के लिए अलेक्जेंड्रियन रैपर और गीतकार अफ्रोटो के साथ मिलकर काम किया है, जो प्रभावशाली कोक स्टूडियो 2023 रिलीज लाइनअप का एक हिस्सा है। यह असंभावित संयोजन श्रेया के विश्व स्तर पर प्रसिद्ध गायन और वाक्यांशों को अफ्रोटो की नई हदें तय करने वाली धुन की भावना के साथ मिलाता है।

उन्होंने कहा, दो शैलियों का मिश्रण है, और कई अलग–अलग प्रकार के संगीतकार एक साथ आ रहे हैं – रॉक, पॉप, शास्त्रीय सब कुछ। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बार दो देशों के कलाकार एक साथ मिलकर काम करेंगे, एक पूरी तरह से अलग उपमहाद्वीप से, – पूरी तरह से अप्रत्याशित – यह नया है।

अफ्रोटो को एक अद्भुत टीम प्लेयर बताते हुए श्रेया ने कहा कि वह उनके लिए बहुत दिलचस्प कलाकार थे। उन्होंने कहा, मैं उनके उत्साह और जोश, और हम दोनों के बीच, दोनों टीमों के बीच जिस तरह से संवाद हुआ उसे देखकर बहुत खुश हुई। यह निर्बाध था, हर मायने में बहुत सहज महसूस हुआ। इसके अलावा मुझे न केवल हिंदी, जो मेरी राष्ट्रीय भाषा है, बल्कि बांग्ला, जो मेरी मातृभाषा है, का भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। मुझे एक गाने में दो चीजें करने को मिलीं।

उन्होंने कहा कि 'सुन्न बेलिया' गीत में लोगों के बीच सद्भाव के बारे में एक बहुत मजबूत संदेश है। "यह लगभग एक गान, एक आंदोलन जैसा है। इसलिए मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही सकारात्मक, आशावादी ऊर्जा प्रदान करने वाला गीत है। मैं देख सकती हूं कि लोग पहले से ही इसे इतना प्यार दे रहे हैं।"

श्रेया के करियर के दो दशक शानदार और सफल रहे हैं। आप पूरे समय किस विश्वास पर कायम रही हैं?

श्रेया ने कहा, मैंने 16 साल की छोटी उम्र में ही अपने फि ल्मी गाने शुरू कर दिए थे। मैंने कभी पहले से प्लान नहीं किया, यहां तक कि मेरे माता–पिता भी, जो इस ट्रेन के इंजन हैं – हममें से किसी ने भी योजना नहीं बनाई। और आगे कोई रास्ता भी नहीं बताया गया था। मैं बहुत आवेगी हूं, मेरे पिता भी हैं और हम तत्काल निर्णय लेते हैं कि उस समय क्या सही है।

उसने कहा, यहाँ तक कि जब मुझे यह कोक स्टूडियो गाना मिला, तो मैंने सोचा कि यह इस समय की जरूरत है। एक कलाकार के तौर पर अब मुझे यही करने की जरूरत है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मैं वही कर रही होती जो पिछले 20 साल से कर रही हूं। मुझे कुछ अलग करने की जरूरत है। इसलिए हर पल एक एक्शन की मांग करता है और वह आगे का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए चाहे सफलताएं हों या असफलताएं, यह मायने नहीं रखती। आप उन चीजों की योजना नहीं बना सकते। ऐसी कोई भी चीज जो आप अपने भविष्य के लिए योजना नहीं बना सकते। भगवान ने आपके लिए सब कुछ योजना बनाई है, और आपको बस अपने कार्यों के प्रति सच्चा होने की जरूरत है।

Printed and Published by Mr. Rajendra Kumar Goel for and behalf of BNT Media & Entertainment Ltd. 339, 3rd Floor , Tower B-3, Spaze Techpark, Sohna Road, Gurgaon-122002 Haryana, India.
Printed at Vivek Publisher, A16, Sector-7, Noida, UP.; Editor Rajendra Kumar Goel. Reproduction in any manner, form or part is prohibited